# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

**विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 12 मार्च, 2020 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।**

## प्रश्न काल

## तारांकित प्रश्न

12.03.2020/1100/SS-AG/1

**प्रश्न संख्या 2656**

(No Supplementary Question)

12.03.2020/1100/SS-AG/2

**प्रश्न संख्या 2657**

**डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल :** अध्यक्ष महोदय, जैसे हम सभी को मालूम है कि हरिद्वार हमारी श्रद्धा का केन्द्र है और सभी लोग वहां जाना चाहते हैं तो लगभग पांच साल पहले यह बस सेवा (हरिद्वार वाया सेरीघाट कुनिहार धर्मपुर बस सेवा) आरम्भ की गई थी। यह इसी क्षेत्र से होती हुई शिमला ग्रामीण, पूरा अर्की, कुनिहार और धर्मपुर का क्षेत्र पार करके हरिद्वार तक जाती रही है। परन्तु जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है शायद 10 जनवरी, 2018 के बाद इसे बन्द कर दिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के साथ अन्तर्राज्यीय समझौते में शामिल होने के बाद शायद यह बस सेवा फिर बहाल कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बस सेवा है इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से प्रश्न है कि कब तक यह बस सेवा बहाल कर दी जायेगी?

**वन मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि यह बस सेवा 2017 में प्रारम्भ हुई थी और 10.1.2018 को बंद हो गई थी। इसका मुख्य कारण यह रहा कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में 18 बसों के एग्रीमैंट हैं यह बस उस एग्रीमैंट में नहीं थी। जिसके कारण से उत्तराखंड के परिवहन विभाग और वहां की कारपोरेशन के कर्मचारियों ने विरोध करके इस बस को चलने नहीं दिया। **हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी इसी महीने उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता हो जाए और जैसे ही हमारे समझौते में यह बस आयेगी तो निश्चित रूप से हम इस बस को चलायेंगे।**

प्रश्न समाप्त

**12.03.2020/1100/SS-AG/3**

**प्रश्न संख्या 2658**

**श्री नरेन्द्र ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि पिछले दो सालों में आपने प्रदेश की आम जनता को बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं दी हैं और आम जनता उन सुविधाओं को ग्रहण भी कर रही है। लेकिन फिर भी हमें हैल्थ में बहुत आगे जाना है तो मेरा निवेदन है कि अभी भी पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी PET scan machines नहीं हैं और

जारी श्रीमती के0एस0

**12.03.2020/1105/केएस/एजी/1**

**प्रश्न संख्याः 2658 जारी....**

**श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी**---

और दो मैडिकल कॉलेजों के अलावा बाकी किसी भी मैडिकल कॉलेज में न तो यह Linear Accelerator है, न Cobalt-60 है, न Brachytherapy की मशीन है और न CT Simulator है। जैसा कि सभी को पता है कि आजकल कैंसर के मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और शुरू में ही अगर कैंसर का पता लगाना है तो इन मशीनों की बहुत ज्यादा ज़रूरत है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हमीरपुर की OPD टांडा मैडिकल कॉलेज से भी ज्यादा है और लोअर हिमाचल में कैंसर के मरीज भी बहुत ज्यादा है । तो कम से कम Cobalt व Brachytherapy मशीन या CT Simulator हमीरपुर में भी देने का प्रयास करें। मेरा यह भी निवेदन है कि आने वाले समय में यह सुविधा बहुत जल्दी दूसरे मैडिकल कॉलेजों में भी दी जाए।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को ले कर संतोष है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। जहां-जहां एक्सपेंशन करनी थी, उसमें भी काम किया तथा दूर-दराज के इलाकों में संस्थान खोले और उनको चलाया भी जा रहा है। क्वालिटी हैल्थ के लिए भी हिमाचल सरकार ने एक नहीं अनेकों इनिशिएटिव्ज़ लिए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि पिछले कुछ अरसे से कैंसर के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश, पूरी दुनिया में यह बढ़ती जा रही है जिसके बहुत सारे कारण हैं। आम तौर पर यह धारणा बनी हुई है कि जिसको कैंसर हो गया, उसके बाद उसकी ज़िदगी बहुत लम्बे समय तक नहीं रहती लेकिन मैडिकल साइंस ने इस बात को काफी हद तक साबित कर दिया है कि कैंसर का इलाज है। ठीक है, क्वालिटी लाइफ उसमें कम्प्रोमाइज़ हो जाती है लेकिन हमने इस बात को भी देखा है कि मैडिकल साइंस ने जो लेटैस्ट रिसर्च की है, जो मैडिसिन्ज़ हैं, उसके उपयोग के बाद कई वर्षों तक मरीजों की लाइफ सेव हो रही है, वे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं।

**12.03.2020/1105/केएस/एजी/2**

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस बीमारी के इलाज के लिए हमारे पास और अच्छी सुविधा होनी चाहिए और उस दृष्टि से PET Scan एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी तक हमारे पास यह सुविधा नहीं है और जितने भी हमारे कैंसर के मरीज होते हैं, इस बीमारी को शुरूआती स्टेज पर डिटैक्ट करने के लिए जिस इन्वैस्टिगेशन की आवश्यकता रहती है, उसमें PET Scan की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हमारे यहां से PET Scan के लिए मरीजों को आमतौर पर चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत है कि यह सुविधा हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आपके पास था और मुझे यह बोलना पड़ रहा है, आप इस विषय पर हमसे बहुत अच्छा बोल सकते थे, मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो पूछा है, हिमाचल

प्रदेश में जो हमारी बिल्डिंग बननी है, जिसमें PET Scan होगा और उसके बाद हमारी मैडिकल Oncology थैरेपी का जो प्रोसिज़र होगा,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

**12.03.2020/1110/av-as/1**

**प्रश्न संख्या : 2658---------- क्रमागत**

**मुख्य मंत्री------ जारी**

इस बिल्डिंग को कैंसर हॉस्पिटल के साथ सड़क के पार बनाने की प्रपोज़ल है। अभी तक पैट स्कैन न तो आई0जी0एम0सी0 में है और न ही प्रदेश के किसी दूसरे मैडिकल कॉलेज में है। जहां पर यह बिल्डिंग बननी है उस स्थान के लिए फोरैस्ट क्लीयरैंस का प्रोसैस चला हुआ है और मुझे लगता है कि यह प्रोसैस 15 दिन में पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त एम0सी0 से एन0ओ0सी0 भी ले लिया है। आई0जी0एम0सी0 में यह मशीन लगभग 18 करोड़ रुपये से ऊपर की लागत से लगेगी। आपने जहां तक यह बात कही कि हमीरपुर में ओ0पी0डी0 का बहुत ज्यादा नम्बर है; तो हम इस बात से सहमत हैं। हमीरपुर में मैडिकल कॉलेज शुरू हो गया है और सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह एक बेहतर मैडिकल कॉलेज के रूप में अपनी पहचान बनायेगा तथा प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कांट्रीब्यूट करेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी मैडिकल कॉलेजिज में एक साथ पैट स्कैन की मशीन स्थापित करना हमारे लिए अभी सम्भव नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि इसको फेज्ड मैनर में सबसे पहले आई0जी0एम0सी0, उसके बाद टांडा मैडिकल कॉलेज और फिर धीरे-धीरे प्रदेश के दूसरे मैडिकल कॉलेज में भी पैट स्कैन की मशीनें स्थापित हो तथा इस बारे में हमारी साफ मंशा है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसकी हमने लिखित रूप में सारी डिटेल दी हुई है।

**श्री आशीष बुटेल :** अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हर साल कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आई0जी0एम0सी0 तथा टांडा मैडिकल कॉलेज में कॉबाल्ट और लिनीयर ऐक्सिलरेटर की मशीनें हैं जिसमें कॉबाल्ट स्पीड के लिए यूज़ हो रही है तथा लिनीयर एक्सिलरेटर एक्युरेसी के लिए होती है। नम्बर एक, मुझे लगता है कि दोनों अस्पतालों में दोनों ही मशीनें होनी चाहिए; तो क्या सरकार इसके लिए कुछ करने जा रही है? दूसरा, यहां पर जो आंकड़ा दिया गया है कि इन अस्पतालों में प्रतिदिन कितने मरीजों का

**12.03.2020/1110/av-as/2**

उपचार हो रहा है तो उसके हिसाब से तो पूरे साल में केवल 2200 के करीब लोगों का ट्रीटमैंट हो रहा है। लेकिन हम यदि साल के केवल 200 वर्किंग डेज भी रखें तो उसके हिसाब से भी 36,000 की कैपेसिटी बनती है। मगर अभी केवल 2200 लोगों का ट्रीटमैंट हो रहा है; इसके क्या कारण हैं? तीसरी बात मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में टाटा मैमोरियल सैंटर खुलने जा रहा है और मुझे लगता है कि वह शायद इसी साल आरम्भ हो जायेगा। अभी हाल ही में अखबारों में यह समाचार आया था कि पंजाब सरकार ने उनसे टाई-अप करके उसको एक सैंटर बनाया है ताकि किसी बड़ी सर्जरी के लिए दिल्ली न जाकर उसको वहीं पर रैफर किया जायेगा; तो क्या हिमाचल सरकार भी उनके साथ इस प्रकार का कोई टाई-अप करने जा रही है?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि तकनीकी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है। इसलिए हमारी भी यही इच्छा होती है कि हमारे पास भी लेटैस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तकनीक के साथ-साथ उसकी क्षमता भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि जितने भी मरीज आएं हम उनका ट्रीटमैंट करने में कामयाब हों। जहां तक आपने अपने प्रश्न के 'डी' पार्ट में पूछा है कि कितने मरीजों का ट्रीटमैंट होता है तो इसके बारे में हमने विस्तृत उत्तर दिया है। हमारी मशीन की कैपेसिटी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि For each Telecobalt Unit, 70 patients can be treated on daily basis at

maximum (as per AERB guidelines) output of machine during working hours of the Department. तो टेलीकॉबाल्ट मशीन से एक दिन में कुल 70 मरीज और एक साल में लगभग 1,550 मरीजों का ट्रीटमैंट किया जाता है। दूसरा --------

**टी सी द्वारा जारी**

**12.03.2020/1115/TCV/AS-1**

**प्रश्न संख्याः 2658... क्रमागत**

**श्री मुख्य मंत्री... जारी**

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि For HDR Brachytherapy Unit, 6-8 patients per day can be treated at maximum source strength. यानी HDR Brachytherapy के माध्यम से एक दिन में 6-8 पेशैंट्स का ट्रीटमैंट किया जा सकता है और इसकी एक साल में 150 पेशैंट्स का ट्रीटमेंट करने की क्षमता है। आपने Simulator के बारे में भी पूछा है Simulator (Acuity) is a planning unit. Approximately 10-15 numbers of patients during the working hours can be planned इसके माध्यम से ट्रीटमैंट का प्लॉन सुनिश्चित किया जाता है। जहां तक For Linear Accelerator and CT Simulator, the capacity is around 50-60 patients per day. इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को हम युटेलाइज करते हैं। **इससे भी ज्यादा कैपेसिटी वाली मशीन यदि उपलब्ध होती है, जिसमें ज्यादा-से-ज्यादा पेशैंट्स का ट्रीटमैंट किया जा सके तो भविष्य में उसके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे। उसमें जो ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, वह हम करने का प्रयास करेंगे।**

दूसरा, माननीय सदस्य ने टाटा मैमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, चण्डीगढ़ का ज़िक्र किया है कि उसमें पंजाब व साथ लगते राज्यों के लोगों का ट्रीटमैंट करने के लिए राज्य सरकार मदद करती है। इन्होंने यह सुझाव दिया है, हम इस सुझाव पर अमल करेंगे। **हम एग्जामिन**

**करेंगे** We will see that whether it is possible or not. **मुझे मालूम नहीं है कि इनके क्या रूल्ज़ और प्रोसीज़र होंगे? इसके बारे में इन सारी चीजों को एग्जामिन करने के बाद हम निर्णय करेंगे।**

**अध्यक्ष :** वैसे तो माननीय सदस्य जी बहुत विस्तार से उत्तर आ गया है परंतु संक्षेप में माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी अपनी बात रखें।

**12.03.2020/1115/TCV/AS-2**

**श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो पैट स्कैन मशीन है, इसके बगैर कैंसर का ट्रीटमैंट अधूरा है और एक पैट स्कैन करने के लिए 30,000-40,000 रुपये लगते हैं। अभी तक इसके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है और एन0ओ0सी0 भी लेना है। यह सारा कुछ करते हुए आपको 2-3 साल और लग जाएंगे। हम आउटसोर्स में बहुत विश्वास करते हैं, क्यों न यह पैट स्कैन आउटसोर्स पर आई0जी0एम0सी0 में चलाया जाये ताकि कैंसर की ट्रीटमैंट के लिए लोगों को फ़ायदा मिल सकें।

दूसरा, जो कोबाल्ट की 20-20 साल पुरानी मशीनें पड़ी हुई हैं, आज टैक्नोलॉजी कितनी अडवांस हो गई है, आप उनको क्यों नहीं बदल रहे हैं? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, शिमला में इसको आउटसोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे पास इसके लिए ज़मीन उपलब्ध हो गई है और इसकी क्लीयरेंस की जो औपचारिकताएं हैं वे भी बहुत अडवांस स्टेज पर हैं। सरकार इसको लगाने के लिए क्षमता रखती है और इसके लिए हम शीघ्रातिशीघ्र कोशिश करेंगे। जहां तक

इसको आउटसोर्स करने की बात है, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है और हम इसे सरकारी क्षेत्र में ही करेंगे।

**श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी ।**

12.03.2020/1120/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 2658... जारी

मुख्य मंत्री... जारी

Pet Scan मशीन ट्रीटमैंट करने के लिए नहीं होती यह डायग्नोस्टिक करने के लिए उपयोग की जाती है। किस स्टेज का कैंसर है, मरीज किस स्थिति में है, इन चीजों का पता लगाने के लिए यह मशीन उपयोगी होती है। यह मशीन काफी महंगी होती है। इसकी कीमत लगभग 18-20 करोड़ रुपये होती है इसलिए इसे सरकारी क्षेत्र में स्थापित करना ही उचित रहेगा। इसके लिए बेसिक नॉर्म्स भी बने हुए हैं। आपने पूछा कि ये मशीनें 20-20 साल पुरानी हैं। भले ही ये मशीनें पुरानी हों लेकिन इनकी समय-समय पर मरम्मत होती रहती हैं और इन्हें उचित रूप से संचालित किया जा रहा है। रेग्यूलेटरी बॉडी, ए.ई.आर.बी. के मुताबिक मैं यह कहना चाहूंगा कि there is no defect in the machine. Life span of each machine depends upon the recommendation of the regulatory body AERB (Atomic Energy Regulatory Board) and company service engineers. उस पैरामीटर्ज पर यह मशीन बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में हम अच्छी और लेटैस्ट टेक्नोलोजी के माध्यम से लोगों को त्वरित सर्विस मुहैया करवायें, इस पर विचार किया जाएगा।

12.03.2020/1120/RKS/DC-2

**<u>प्रश्न संख्याः 2659</u>**

**श्री सुरेन्द्र शौरी (बंजार)**: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या विभाग द्वारा बंजार, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हैंडलूम, हैंडिक्राफ्ट, इको टूरिज्म और फल एवं सब्जियां आधारित फूड प्रोसैसिंग उद्योग स्थापित करने पर विचार किया जाएगा? बंजार, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुरला, गड़सा और बंजार ऐसे क्षेत्र हैं जहां से पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए स्लेट जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्लेट आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सैंज की तलाड़ा पंचायत में विभाग के नाम लगभग 5 बीघा भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है और वहां उद्योग स्थापित करने के लिए और भी भूमि उपलब्ध हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उस भूमि पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करना चाहेंगे?

**उद्योग मंत्री**: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि औद्योगिक नीति के अनुसार आपका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 'सी' श्रेणी में आता है। जो क्षेत्र 'सी' श्रेणी में आते हैं उन क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाने के लिए विभाग द्वारा सबसे ज्यादा सब्सिडी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आपने जो हैंडलूम, हैडिक्राफ्ट या अन्य उद्योग लगाने का ज़िक्र किया है, मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री डिपार्टमैंट इंडस्ट्रीज लगाने का काम नहीं करता। इंडस्टी डिपार्टमैंट इंडस्ट्री लगाने के लिए सहूलियतें प्रदान करता है। जो व्यक्ति वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है और उसे किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्ज की जरूरत है तो विभाग उसकी मदद कर सकता है। आपने जो सैंज एरिया में इंडस्ट्री लगवाने के बारे में विषय रखा है, मेरा निवेदन है कि यदि आप इस बारे में डिटेल देंगे तो वहां निरीक्षण हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जाएगा। यदि उस क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल एरिया बन सकता है तो विभाग द्वारा वहां नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा।

प्रश्न संख्या 2660 श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

12.03.2020/1125/बी.एस./डी.सी./-1

**प्रश्न संख्याः 2660**

**श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना सभापटल पर रखी है उसमें कहा गया है कि शिलाई की सैटलमैंट पिछले छह वर्षों से हो रही है और अब वह खत्म होने के कागार पर है। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को विधायकों की बैठक में भी अवगत करवाया था कि जो सैटलमैंट शिलाई में हो रही है वह मौके के मुताबिक नहीं हो रहा है। जब इस क्षेत्र की तकसीम हुई तो उसमें पटवार खाने में बैठक करके तकसीम की गई। जिसकी वजह से जो मौके के कब्जे हैं और जो कागज़ो में रिकॉर्ड है उसमें अन्तर है। अब जब सैटलमैंट हो रहा है तो किसी का खेत दूसरे की ऑनरशिप में जा रहा है, किसी और का मकान कहीं और स्थान पर जा रहा है। क्या आप विभाग को आदेश करेंगे कि जो सैटलमैंट है वह मौके के मुताबिक हो। मौके पर जिन लोगों के कब्जे हैं उसके मुताबिक उसे किया जाए। ताकि इसमें झगड़े न बढ़ें। इसमें क्या होगा कि सैटलमैंट में जो revenue disputes है उसे कम करने के लिए किया जाता है यदि इसे कागज़ के मुताबिक किया जाता है तो उससे मौके में ज्यादा disputes बढ़ेंगे। जब शिलाई में जनमंच का आयोजन किया गया था उस वक्त भी लोगों ने इस इश्यू को मंच से उठाया था। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी वहां गए थे, लोगों ने भी निवेदन किया था कि मौके के मुताबिक जो वहां पर लोगों की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं हैं उनके अनुसार आप उसे करवाएं। वहां कोई झगड़े वाली बात नहीं है और न ही कोई अपनी भूमि,खेत,घर या बगीचे के लिए क्लेम कर रहा है। इस तरह की वहां पर कोई बात नहीं है, amicably कब्जे के मुताबिक इसे आप विभाग को करने के आदेश देंगे?

**मुख्य मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह एक अच्छा सुझाव है और व्यावहारिक भी है क्योंकि जो revenue disputes होते हैं वह बहुत पेचिदा होते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर यह सैटलमैंट का प्रोसैस मौके के मुताबिक किया जाए तो उसमें थोड़ी सुविधा हो सकती है और झगड़े वाली बात भी कम होगी।

लेकिन यह भी सत्य है कि रेवेन्यू के रिकॉर्ड को ठीक करना है तो वह उसी रिकार्ड से ही हो पाएगा। **इन सारी चीजों को ले करके, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसे हम**

12.03.2020/1125/बी.एस./डी.सी./-2

**एग्जामिन करेंगे।** हम विभाग को कहेंगे, क्योंकि वास्तव में सैटलमैंट लोगों की सुविधा के लिए होता है। सही मायने में जहां उनकी जमीन है, जहां वे कास्त कर रहे हैं, जहां उनका कब्जा है वह जमीन उनके हिस्से में आए। उस जमीन को उन्होंने जोता होता है और उस जमीन को उन्होंने सही ढंग से बनाया होता है। उससे उनकी भावनाएं भी जुड़ी होता हैं। उसमें उन्होंने अपना कमान बनाया होता है। स्वाभाविक रूप से अगर मौके के मुताबिक जिस आदमी का जिस जगह, जिस खसरा नम्बर है और उसके साथ-साथ उसने वहां पर मकान बना लिया है अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई है वह सारी जमीन उसके नाम से उसी तरह से आए तो वह सुविधाजनक रहता है। सैटलमैं में अगर रिकॉर्ड के मुताबिक चलते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। जमीन में कब्जा किसी का है और जमीन किसी अन्य के पास चली जाती है। यह माननीय सदस्य का अच्छा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि किसी भूमि मालिक को भूमि कागज़ात और सजरा के विपरीत किसी अन्य जगह पर कब्जा पाया जाता है तो इस बारे में नायब तहसीलदार बन्दोबस्त के समय संबंधित पक्षों को सुनने के बाद निपटारा कर देता है। **मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका समाधान करेंगे।** इस संबंध में माननीय सदस्य ने कर्मचारियों के बारे में भी पूछा है। हमने प्रश्न के "ख" भाग में पूरी जानकारी दी है। उसमें बताया है कि एक नायब तहसीलदार, 3 कानूनगो, 20 पटवारी और 2 चेन मैंन वहां पर लगाए गए हैं। अगर आप शिलाई, क्यारीकुण्डा की बात करें, इस संदर्भ में आपने पहले भी प्रश्न पूछा था। इस कार्य को हम दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करने की हमारी कोशिश है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

12.03.2020/1130/DT/HK-1

**प्रश्न संख्या 2660 क्रमागत**

**हर्षवर्धन चौहानः** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि शिलाई एक शहर का रूप ले रहा है और वहां जनसंख्या 10 से 12 हज़ार की है। 1500 के करीब वहां पर मकान हैं। अगर आप मौके के मुताबिक सेट्टलमेन्ट नहीं करोगे तो हर व्यक्ति अपनी जगह के अतिरिक्त दुसरे की जगह में भी जा रहा है। यह एक बहुत गम्भीर विषय है। मैंने जब तहसीलदार या नायब तहसीलदार, जो सैट्टलमेन्ट का काम कर रहें हैं, उनको भी कहा पर उन्होंने कहा कि हमें कोई आदेश नहीं मिले हैं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, इसमें आपको सैट्टलमेन्ट को रिव्यू करने के आदेश देने पडेंगे। नहीं तो खानापूर्ति वाला काम ही होगा। क्योंकि जमीन किसी के नाम होगी और कब्जा किसी और के पास होगा। इससे तो मामला वैसे का वैसा ही रहेगा। इसलिए सरकार को वहां सैट्टलमेन्ट को रिव्यू करने के आदेश जारी करने चाहिए और अधिकारी मौके में जा कर लोगों से इस बारे में पूछें। वहां सैट्टलमेन्ट विभाग के लोग सैट्टलमेन्ट कर रहें हैं लेकिन न तो वह आम जनता से और न ही जनप्रितिनिधि से वो बात कर रहें हैं। वह बस कागज़ों में खानापूर्ति कर रहें हैं। वह हर व्यक्ति को कह रहें हैं कि तुम इसकी जमीन में बैठ गये, तुम उसकी जमीन में बैठ गये, तुम तो इस भूमि के मालिक ही नहीं हो। एक भय का माहौल इस समय शिलाई में है। वहां पर कोई डिसप्यूट नहीं है, वहां कोई क्लेम नहीं कर रहा कि यह मेरा खेत है या मेरा मकान है। एक व्यक्ति का पूरा बगीचा दूसरे के नाम कर दिया। एक वयक्ति का एक करोड़ का मकान दूसरे के नाम कर दिया। इस तरह के बहुत सारे मामले वहां पर हैं अतः माननीय मुख्य मन्त्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक इन मामलों में विचार कर अधिकारियों को आदेश करें, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाऐं भी जुड़ीं हुईं हैं।

12.03.2020/1130/DT/HK-2

**अध्यक्षः** माननीय मुख्य मन्त्री महोदय।

**मुख्य मन्त्रीः** माननीय अध्यक्ष महोद, मैं पहले भी यह कह चुका हूं कि सैट्टलमेन्ट उसी काम के लिए किया जाता है जिसमें लोगों के डिसप्यूट सैट्टल हों न कि डिसप्यूट आपस में बढ़ें। जैसा की माननीय सदस्य ने कहा कि इस दिशा में ऐसा करना उचित रहेगा, हम उस बात को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर एग्जामिन करेंगे। रेवन्यू के रिकार्ड का मिलान करना अत्यावश्यक है। यह रिकार्ड जब तक ठीक नहीं किया जायेगा तब तक कोई भी चीज कहने से सैट्टल नहीं हों पायेंगी। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर हम विचार करेंगे।

12.03.2020/1130/DT/HK-3

**प्रश्न संख्या 2661**

**विक्रमादित्य सिंहः** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस प्रश्न का आधा आंकड़ा पहले शीतकालीन प्रवास पर दे चुके हैं। अभी यह कह रहें हैं कि सुचना एकत्रित की जा रही है तीन महीने से अभी सूचना ही एकत्रित की जा रही है।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, जब उत्तर आ गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है, ठीक है कोई बात नही आप बैठ जाईये।

**मुकेश अग्निहोत्रीः** अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा नाम भी है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि सूचना एकात्रित की जा रही है।

**मुकेश अग्निहोत्रीः** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कह दिया तो क्या हुआ।

**अध्यक्षः** इन्होंने कह दिया है तो वह यहां स्वीकार्य है।

**मुकेश अग्निहोत्री :** इन्होंने कह दिया है तो क्या सृष्टि खत्म हो गई।

**अध्यक्षः** आप बैठ जाईए। सृष्टि खत्म नहीं हुई।

**मुकेश अग्निहोत्रीः** माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि आप इस प्रश्न को आगे लगा दो।

**अध्यक्षः** बिल्कुल, यह आगे चलेगा।

**मुकेश अग्निहोत्रीः** नहीं नहीं ऐसा नही चलेगा। ...(व्यवधान) आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जायें। मैं आप की बात भी सुन रहा हूं जब माननीय मन्त्री महोदय ने कह दिया कि सूचना एकात्रित की जा रही है...(व्यवधान)

**12.03.2020/1130/DT/HK-4**

**मुकेश अग्निहोत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नही होना चाहिए। यह प्रश्न हम तीन लोगों ने पूछा है, आपको हमारी बात सुननी चाहिए।

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी**

**12-03-2020/1135/एच.के.-एन.जी./1**

**प्रश्न संख्या 2661 जारी.....**

**श्री मुकेश अग्निहोत्री के पश्चात.....**

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न किया उसका विभाग व सरकार की तरफ से उत्तर आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सृष्टि खतम नहीं हो रही है आपको उत्तर मिल जाएगा।...(व्यवधान)

**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः** माननीय मंत्री जी ने जो कहा क्या वह फाइनल हो गया?

**अध्यक्षः** यहां पर परमपरा तो यही है कि यदि सूचना एकत्रित की जा रही है तो उसका उत्तर बाद में दिया जाएगा। माननीय सदस्य आप बैठ जाएं क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं।...(व्यवधान)

**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं कि सूचना एकत्रित करने में क्या दिक्कत है?

**अध्यक्षः** माननीय उद्योग मंत्री जी आपने चेयर को सम्बोधित करके बताया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इसलिए इस पर आगे चर्चा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

**उद्योग मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्रश्न इन्होंने किया है उसके उत्तर की बहुत लम्बी डीटेल है जिसे हम इकट्ठा कर रहे हैं। कैम्पस इंटरव्यू 15-15 दिन बाद हो रहे हैं उन सभी की सारी डीटेल 31 मार्च तक आ जाएगी। हम उन सब सूचनाओं को सभा पटल पर अवश्य रखेंगे क्योंकि उसमें कोई भी छुपाने वाला विषय नहीं है। ये लोग बिना मतलब के सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। जब आपने प्रश्न किया और उसका उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है...(व्यवधान)

**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः** हम कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं।

**उद्योग मंत्रीः** आपका कुछ और काम ही नहीं है आपका काम केवल सेंसेशन क्रिएट करना है। आपके प्रश्न की सारी सूचना एकत्रित करके आपको पूरी तसल्ली के साथ जवाब देंगे। इसमें छुपाने वाला कोई विषय नहीं है।

**12-03-2020/1135/एच.के.-एन.जी./3**

**प्रश्न संख्या - 2662**

**श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल)**ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुपवी क्षेत्र बहुत ही दूर-दराज और पिछड़ा क्षेत्र है। कुपवी ब्लॉक में कुल 14 पंचायतें हैं जिनमें से 9 पंचायतें पिछड़ी हुई हैं और 5 पंचायतें गैर-पिछड़ी हैं। 14 पंचायतों के हिसाब से 9 पंचायतों का पिछड़ा होना 70 प्रतिशत बनता है। पंचायती राज एक्ट के अनुसार किसी एक ब्लॉक में यदि 50 प्रतिशत से अधिक पंचायतें पिछड़ी हों तो सारा ब्लॉक ही पिछड़ा घोषित किया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या आप कुपवी ब्लॉक को पिछड़ा घोषित करेंगे?

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड कुपवी में 5 पंचायतें क्रमशः जुडू शिलाल, धौताली, मालत, कुलग और नौरा-बौरा गैर पिछड़ी पंचायतें हैं। इसी प्रश्न के उत्तर के 'ख' भाग में मैंने कहा है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस विकास खण्ड में 50 प्रतिशत से अधिक पंचायतें पिछड़ी हों, वह पूरा विकास खण्ड पिछड़ा घोषित करने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, 14 पंचायतों में से 9 पंचायतें पिछड़ी हुई हैं और 5 पंचायतें पिछड़ी हुई घोषित नहीं की गई हैं। नॉर्मज़ के अनुसार जिस ब्लॉक में 50 प्रतिशत पंचायतें पिछड़ी हुई होती हैं तो वह सारा ब्लॉक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाता है। **अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आप प्रस्ताव भेजें और उसके बाद हम नॉर्मज़ के अनुसार पूरे ब्लॉक को पिछड़ा घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।**

अगला प्रश्न, श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

**12/03/2020/1140/MS/YK/1**

**प्रश्न संख्याः 2663**

**श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना दी गई है इसमें यह दर्शाया गया है कि लगभग 1,22000,00/-रुपये रिपेयर का पैसा है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी लगना है। मैं समझता हूं कि यह काफी पैसा है और रिपेयर का मामला है। यह कोई बड़ा काम नहीं है इसलिए इन कामों में तेजी लाई जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, यह भी देखा गया है कि जिस तेजी से लोक निर्माण विभाग को काम करना चाहिए वैसा काम वहां पर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां से ऐसे आदेश जाएं कि यह पैसा जल्दी लगे। इसके अलावा खासतौर पर मैंने दो स्कूल्ज जो कि गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल किंजा और गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल जरी हैं, का इसमें वर्णन किया था। अध्यक्ष जी, मात्र इस वजह से वहां फण्ड्ज यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं क्योंकि उस बिल्डिंग को गिराया जाना है और यह मामला कोई एक-दो वर्षों का नहीं बल्कि कई वर्षों से लटका हुआ है। मैं समझता हूं कि जिला स्तर पर जो कमेटी इसकी एप्रूवल देती है जिसमें खासतौर से शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन हैं, इनको मिलकर यह फैसला लेना होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इसके लिए समयावधि तय करेंगे? वास्तव में इन दोनों स्कूलों का यह मामला कई वर्षों से पैंडिंग है और वहां पर एकॉमोडेशन की कमी है इसलिए कृपा करके कोई समयावधि तय हो, यह मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

**शिक्षा मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, कुल्लू विधान सभा क्षेत्र जिसे माननीय सदस्य रिप्रेजैंट करते हैं, उसमें इन्होंने स्वयं भी कहा है कि काफी पैसा स्कूलवाइज भेजा हुआ है। एलीमेंट्री डिपार्टमैंट द्वारा 1,2200,339/-रुपये और साथ में हायर एजुकेशन की जो अन्य आठ बिल्डिंग्ज हैं, उनके लिए हमने लगभग अढ़ाई करोड़ रुपये से अधिक फण्ड्ज प्रोवाइड किए हुए हैं। ये फण्ड्ज कुछ लोक निर्माण विभाग को जाते हैं और कुछ छोटी-छोटी रिपेयर्ज के लिए स्कूल्ज/ एस0एम0सी0 जो स्वयं करते हैं, उनके लिए जाते हैं। इसके

बारे में माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। हम विभाग से इसकी रिपोर्ट लेंगे और आपको भी भेज देंगे कि किस-किस जगह पर काम क्यों

**12/03/2020/1140/MS/YK/2**

नहीं हो रहा है, यदि लोक निर्माण विभाग को पैसा गया है। इसके अलावा जो दो स्कूलों की आपने बात की है, उसमें से एक स्कूल किंजा है जिसके लिए 47,000,00/-रुपये हम पहले ही दे चुके हैं लेकिन लोक निर्माण विभाग के नॉर्म्ज हैं कि यदि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल का 30 परसेंट पैसा मिल जाए, तब वे काम शुरू करते हैं हालांकि इसमें 3-4 लाख रुपये कम रह गये हैं। लेकिन इस बार हमने इसके लिए बजट में प्रोविजन किया है और तुरन्त यह काम बजट के बाद शुरू कर देंगे। दूसरा, जो ज़री स्कूल है उसमें भी पहले ही 27,000,00/-रुपये दिए हुए हैं। उसमें आपने जैसे बताया है कि बिल्डिंग डेमोलिश होनी है तो अगर उसमें डेमोलिशन भी करना है तो उसमें लैण्ड नहीं है। आपने सही कहा है कि डेमोलिशन के लिए काफी समय से चर्चा चल रही है। इसमें वाणी अनसेफ बिल्डिंग है जिसको डेमोलिश करना है लेकिन बच्चों की वहां पर पढ़ाई हो सके इसके लिए अलटरनेट साइट नहीं मिल पाई है और इस कारण से डिले हुआ है। लेकिन इसमें भी 27,000,00/-रुपये के अलावा और पैसा भेजेंगे। डेमोलिशन के लिए हम भी एस0डी0एम0 कुल्लू को कहेंगे और आप भी मैटर को परस्यू कीजिए। इसके अलावा हम अपने डिप्टी डायरेक्टर को भी कहेंगे कि वह जिला प्रशासन से बात करके इसको डेमोलिश करे।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, आपके प्रश्न का काफी विस्तार से उत्तर आ गया है।

**श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः** अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी ने दो बिल्डिंग्ज के बारे में कहा, वह ठीक है। मेरी जानकारी के मुताबिक कुल्लू विधान सभा क्षेत्र से दूसरे विधान सभा क्षेत्रों के लिए इस वर्ष फण्ड्ज डायवर्ट किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी यह जानना चाहता हूं कि,

**जारी जे0के0 द्वारा**---

**12.03.2020/1145/JK/YK/1**

**प्रश्न संख्याः 2663**:------**जारी**------

**श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा, वह ठीक कहा, इन्होंने दो बिल्डिंग्ज के बारे में कहा और मेरी जानकारी के मुताबिक कुल्लू विधान सभा क्षेत्र से इस वर्ष में फंडज़ डाइवर्ट दूसरे विधान सभा क्षेत्र के लिए किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कितना पैसा किन-किन क्षेत्रों के लिए कुल्लू विधान सभा से under Building Head for Schools जो पैसा मुहैया किया गया था, उसको ट्रांसफर क्यों किया गया, उसके क्या कारण थे?

**शिक्षा मंत्रीः** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय सदस्य ने मांगी थी उन स्कूलों में से कोई डाइवर्शन नहीं हुई है। टोटल 161 प्राइमरी स्कूलों की लिस्ट माननीय सदस्य को दी है, इनमें से कोई डाइवर्शन नहीं हुई है। जो दो दूसरे स्कूल हैं उनके लिए 47 लाख और 27 लाख दे रखे हैं लेकिन वह 30 प्रतिशत से कम पैसा है। **इस बार हम उसको पूरा 30 प्रतिशत कर देंगे और काम आरम्भ कर देंगे।** अगर इनमें से कोई पैसा डाइवर्ट हुआ होगा तो माननीय सदस्य को उसकी जानकारी दे देंगे लेकिन छोटे-छोटे अमाउंट हैं, उनका डाइवर्ट होने का सवाल ही नहीं है। लोक निर्माण विभाग के पास जब पैसा रहता है और काम नहीं करते हैं तो अपने आप ये पैसे का यूटेलाइजेशन कहीं दूसरी जगह कर देते होंगे लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है, परन्तु शिक्षा विभाग ने वह पैसा डाइवर्ट नहीं किया है। **अगर इस पैसे का डाइवर्शन हुआ होगा तो उसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दी जाएगी।**

**12.03.2020/1145/JK/YK/2**

**प्रश्न संख्याः 2664**

**श्री राकेश जम्वालः** अनुपस्थित।

12.03.2020/1145/JK/YK/3

**प्रश्न संख्याः 2665**

**श्री सुख रामः** अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में 2272 विद्यार्थी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में कितने कक्षा कक्ष इस महाविद्यालय में हैं और 2272 विद्यार्थियों के लिए कितने कक्षा कक्ष चाहिए? क्या चरणबद्ध तरीके से इस कमी को आदरणीय मंत्री जी पूरा करेंगे?

**शिक्षा मंत्रीः** माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में कितने कक्षा कक्ष हैं, उनकी सारी-की-सारी डिटेल माननीय सदस्य को लिखित में दे दी है। लेकिन यह बात सही है कि कॉमर्स के लिए और ऑर्टस के लिए 6 कक्षा कक्ष अभी कम हैं। जब यहां पर यह कॉलेज शुरू हुआ उसके बाद कुछ बिल्डिंग बनी, जिसमें साइंस ब्लॉक दो बनें हैं और जल शक्ति विभाग से भी एक बिल्डिंग कॉलेज के लिए दी गई, उसी में कुछ कक्षा कक्ष बनाए गए हैं। लेकिन कुछ कमी अभी भी रहती है उसमें 6 कक्षा कक्षों का निर्माण पहले से ही चल रहा है **लेकिन 6 कक्षा कक्ष अभी और कम हैं उनकी पूर्ती भी शीघ्र कर दी जाएगी। जैसे-जैसे फंडज़ की उपलब्धता होगी हम उनको पूरा कर देंगे।**

12.03.2020/1145/JK/YK/4

**प्रश्न संख्याः 2626**

No Supplementary.

12.03.2020/1145/JK/YK/5

**प्रश्न संख्याः 2667**

**श्री विशाल नेहरिया:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें बताया गया कि वर्ष 2014 में इन शिक्षण संस्थानों में चुनावों के प्रति प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। पूरे प्रदेश में एक या दो ही ऐसे शिक्षण संस्थान थे जहां पर ऐसी कानूनी व्यवस्था बिगड़ी थी।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

**12.03.2020/1150/SS-AG/1**

**प्रश्न संख्या : 2667 क्रमागत**

**श्री विशाल नैहरिया क्रमागत :**

मुझे लगता है कि छात्र राजनीति में छात्र संघ चुनावों के माध्यम से कई बार हमारे इस माननीय सदन को भी अच्छे वक्ता या नेता मिले हैं। भविष्य में भी ऐसे अच्छे वक्ता सदन को मिलें इसलिए मेरा कहना है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिएं। यही मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है।

**शिक्षा मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में हमने विस्तृत जानकारी दी है। 2014 से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में स्टूडैंट्स सैंट्रल एसोसियेशन का गठन हो रहा है। लेकिन वे मैरिट के आधार पर छात्र आते हैं और उन्हीं को चुन करके स्टूडैंट्स सैंट्रल एसोसियेशन (SCA) का पदाधिकारी बनाया जाता है। जब उस समय की सरकार ने छात्र संघों के चुनाव बंद किये थे तब ऐसा बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण किया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार तय नहीं करती है कि छात्र संघों के चुनाव हों या न हों। इसका निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और उनके जो निकाय हैं वे ही करते हैं। लिंगदोह कमेटी की जो सिफारिशें हैं जोकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई थी, वे हिन्दुस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसने सिफारिशें की थीं। उसके अनुसार जिस प्रकार से ई0सी0 में सदस्य बनते हैं उस हिसाब से हम मनोनयन करते हैं। **विश्वविद्यालय की**

**कार्यकारिणी जो तय कर देगी, वे जो सिफारिश करेंगे तो उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी।**

**12.03.2020/1150/SS-AG/2**

**प्रश्न संख्या : 2668**

**श्री पवन नैय्यर :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि M/s Govind Raj Project Pvt. Ltd. कम्पनी ने कह दिया है कि यह 31.3.2020 तक है परन्तु इन्होंने यह नहीं कहा है कि ये कब से भूरी सिंह पावर हाउस चला रहे हैं। इन्होंने जितने इम्प्लॉईज बताए हैं न उनकी इंश्योरैंस करवाई है और न इन्होंने उनका ई0पी0एफ0 नम्बर बताया है। अध्यक्ष महोदय, ई0पी0एफ0 में इम्प्लॉईज शेयर अलग होता है और प्रिंसीपली इम्प्लॉयर शेयर अलग होता है। यह 25.36 परसैंट जमा होना चाहिए। परन्तु जो मेरी नॉलेज है उसके अनुसार यह इम्प्लॉईज के खाते जमा नहीं हुआ है। यह मैंने अभी असैम्बली क्वैश्चन किया तब तो इन्होंने पेमैंट डाल दी और पेमैंट भी ऑनलाइन होनी चाहिए। जब से यह प्रोजैक्ट गोविन्द राज के पास है इन्होंने कोई भी पेमैंट ऑनलाइन नहीं डाली हुई है। जितने भी इम्प्लॉईज इन्होंने बताए हैं, यह भी बताया जाए कि ये कब से लगे हुए हैं?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने उत्तर बहुत विस्तार से दिया है। मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक अगर मैं बात कहूं कि तो जो आप सैलरी का ज़िक्र कर रहे हैं सैलरी एक बार फरवरी के महीने में देरी से दी गई थी अन्यथा 7 तारीख से पहले हर महीने की सैलरी दी जा रही है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय जो इनके पास 14 कर्मचारी हैं उनमें से 11 कर्मचारी चम्बा जिला से हैं। एक कांगड़ा है, एक पंजाब है और एक बिहार से है। यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध है कि जो तीन लोग बाहर से हैं वे टेक्निकल साइड से हैं। कम्पनी को वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाए तो कम्पनी का कहना है कि तब इनको बाहर से लिया गया है।

जहां तक माननीय सदस्य कंट्रैक्ट की बात कह रहे हैं तो यह वर्ष 2015 से उनके पास कंट्रैक्ट है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट नहीं है बल्कि एक छोटा-सा प्रोजैक्ट है

जारी श्रीमती के0एस0

**12.03.2020/1155/केएस/एजी/1**

**प्रश्न संख्या2668 जारी**---

**मुख्य मंत्री जारी**---

और यह प्रोजैक्ट 450 किलोवाट का है। डिटेल में जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, उसके बारे में मैं यह इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं कि प्रारम्भ में चम्बा के भूरी सिंह पावर हाउस के सिविल व इलैक्ट्रिकल कार्यों में कैपिटल इन्वैस्टमैंट मैंटिनेंस व परिचालन के कार्यों के अवार्ड की अधिसूचना 20.07.2012 को फर्म मैसर्ज़ एस.एस.जी. ट्रांसइरैक्टर को जारी की गई जो मैसर्ज़ गोविंद राज प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम में थी। नोटिस के माध्यम से बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी मैसर्ज एस.एस.जी. ट्रांसइरैक्टर अनुबन्ध की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। मैसर्ज़ एस.एस.जी. ट्रांसइरैक्टर द्वारा अनुबंधित शर्तों को पूरा न करने और अनुबन्ध के अनुसार मु0 2 करोड़ रुपये की कैपिटल इन्वैस्टमैंट में विफलता के मध्यनज़र हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम ने दूसरे सांझीदार यानि मैसर्ज़ गोविंद राज प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड से अनुबन्ध की शर्तों को पूरा करने के लिए व 2 करोड़ रु0 के निवेश के लिए कहा। उपरोक्त के मध्यनज़र मैसर्ज़ एस.एस.जी. ट्रांसइरैक्टर और मैसर्ज़ गोविंद राज प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वैंचर टेकओवर एग्रीमेंट दिनांक 17.10.2015 को किया गया। जहां मैसर्ज एस.एस.जी. ट्रांसइरैक्टर सांझेदारी से अलग हो गई। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वर्तमान मैसर्ज़ गोविंद राज प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड अनुबन्ध निष्पादित कर रहा है जो कि दिनांक 30.06.2021 तक पूरा हो जाएगा तथा मैसर्ज़ गोविंद राज प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटिड पहले ही पूंजी रख-रखाव कार्यों के लिए मु0 2 करोड़ रूपये निवेश कर चुका है।

अध्यक्ष महोदय, भूरी सिंह पावर हाउस में 11 कर्मचारी चम्बा जिला से, 1 कर्मचारी कांगड़ा से, 2 कर्मचारी बिहार तथा पंजाब से कार्यरत्त हैं। इन कर्मचारियों के वेतन का ब्योरा **अनुलग्नक-क** पर संलग्न है। सभी कर्मचारियों को सामान्य रूप से हर महीने 7 तारीख़ को वेतन दिया जाता है परन्तु किसी कारणवश माह फरवरी 13 तारीख़ को वेतन दिया गया। यह एक बार हुआ था। सभी कर्मचारी कम्पनी के



वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी (WCP)नं0 401501411910000016 के अंतर्गत इन्श्योर्ड हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन EPFO NO. HP-5766 के अंतर्गत हुई है।

अध्यक्ष महोदय, खोली पावर हाउस के दूसरे पोर्शन के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी डिटेल माननीय सदस्य के पास पहले ही है।

**श्री पवन नैय्यरः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो ई.पी.एफ. नम्बर बताया, यह कम्पनी ने अपना बताया। जो ये 14 आदमी हैं, इनका ई.पी.एफ. नम्बर अलग होगा और यह सारा पैसा इनके अकाउंट में जाएगा। न इन्होंने इसकी इन्श्योरेंस करवाई है। मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 से इन्होंने पावर हाउस की भी इंश्योरेंस भी नहीं करवाई हुई है। अगर पावर हाउस को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक और प्रार्थना है कि इसको एक्सटैंशन न दी जाए। ये अभी के इम्प्लॉइज़ हैं। अगर वर्ष 2015 से देखेंगे तो कोई और इम्प्लाईज़ थे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको एक्सटैंशन न दी जाए, कोई और पार्टी देखी जाए और पेमेंट भी ऑन लाइन होनी चाहिए।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो तथ्य हमारे ध्यान में लाए हैं, सारे तथ्यों की जानकारी लेकर हम आपको भी उपलब्ध करवा देंगे। हम किसी भी तरह से गलत नहीं

होने देंगे और जो कर्मचारी हैं, उनके अकाउंट में पैसा जाए, सैलरी समय पर जाए, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे।

प्रश्न समाप्त

अगला प्रश्न अ0व0 की बारी में---

**12.03.2020/1200/av-as/1**

**प्रश्न संख्या 2669**

**श्री सुभाष ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैं बस अड्डा बिलासपुर के लिए मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका कार्य कब तक शुरू किया जायेगा? बिलासपुर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से बिलासपुर आने वाली बस में हमारे लोगों को बिठाया नहीं जाता इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस रूट पर एक नई बस चलाई जाए।

**(प्रश्न काल समाप्त)**

**12.03.2020/1200/av-as/2**

**कागज़ात सभा पटल पर**

**अध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) कनिष्ठ वेतनमान

आशुलिपिक, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः पर (एस ए एस-1)ए(3)-1/2018 दिनांक 18.12.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.12.2019 को प्रकाशित; और

ii. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जैव विविधता नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः एसटीई-ए(3)-1/2004-लूज़ दिनांक 22.11.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2019 को प्रकाशित ।

**12.03.2020/1200/av-as/3**

**अध्यक्ष :** अब माननीय शिक्षा मन्त्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम,2019 जोकि अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.-बी.-बी(16)-11/2019 दिनांक 19.08.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.09.2019 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

**शिक्षा मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम,2019 जोकि अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.-बी.-बी(16)-11/2019 दिनांक 19.08.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.09.2019 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

**12.03.2020/1200/av-as/4**

## सदन की समितियों के प्रतिवेदन

**अध्यक्ष :** अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2019-20), समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत 'बेटी है अनमोल योजना' से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

**श्री सुख राम :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2019-20) का 22वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत 'बेटी है अनमोल योजना' से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

**अध्यक्ष :** अब श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति (वर्ष 2019-20), समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के अष्टम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

**श्री हीरा लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति (वर्ष 2019-20) का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के अष्टम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

**12.03.2020/1200/av-as/5**

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

**अध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मंत्री 'कोविड' यानी कोरोना वायरस के ऊपर अपना वक्तव्य देंगे और तदोपरान्त 'यस बैंक' के बारे में भी इस माननीय सदन में वक्तव्य देंगे।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, आजकल पूरे विश्व में इस विषय पर बहुत चिंता जाहिर की जा रही है। अगर मैं यह कहूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना वायरस की वजह से एक हड़कंप की परिस्थिति बनी हुई है और हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। इसको डब्ल्यू0एच0ओ0 ने ऐपिडैमिक घोषित कर दिया है। हमारी केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी को सख्ती से लागू करने के संदर्भ में भी बार-बार आग्रह किया जा रहा है। मैं आज सुबह भी टेलीविज़न पर देख रहा था कि बहुत सारे देशों के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। हमारे देश से कोरिया की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। यहां तक कि जिन देशों में कोरोना वायरस का ज्यादा इंपैक्ट है वहां के लिए लोगों द्वारा बनाये गये ट्रैवलिंग वीजा भी रद्द कर दिए हैं । मैं इस माननीय सदन और प्रदेश की जनता को अवगत करवाना चाहता हूं कि बहुत दहशत का माहौल खड़ा करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिनअहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि यदि कहीं एक भी ऐसा मामला सामने आ जाता है तो उससे पूरे समाज में एक चिंता और दहशत का माहौल खड़ा हो सकता है।

**टी सी द्वारा जारी**

**12.03.2020/1205/TCV/AS-1**

**मुख्य मंत्री... जारी**

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ बातें अपनी स्टेटमैंट के माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस के ख़तरे से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पूरी तरह से तैयार हैं। प्रदेशवासियों को इस महामारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपितु सचेत एवं सजग रहने की आवश्यकता है। अभी तक प्रदेश में कुल 428 लोग जो कि कोरोना प्रभावित देशों से आये हैं की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें से 268 लोगों की सूचना भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन से प्राप्त हुई तथा 160 लोगों ने स्वंय इन प्रभावित देशों से आने की सूचना दी है। इनमें से 4 लोगों में खांसी,

जुखाम, बुखार आदि के लक्षण पाये जाने के उपरान्त जांच के लिए नमूने लिए गये थे जिसे **AIIMS,**नई दिल्ली में जाचं के लिए भेजा गया था तथा सभी नमूने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के प्रति नकारात्मक पाये गये हैं। इनकी जो रिपोर्ट आई है, वह नेगेटिव आई है। यह हमारे लिए बड़े संतोष की बात है। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 5 मार्च, 2020 को एक एडवाइजरी जारी की है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सामूहिक सभाओं से बचना चाहिए और इन सभाओं को जहां तक संभव हो स्थगित कर देना चाहिए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। यदि ऐसी सभाएं अति-आवश्यक हों तो सभी उचित बचाव के तरीके अपनाए जाने चाहिए। इसी के संदर्भ में प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों को दिनांक 6 मार्च, 2020 को एडवाइजरी जारी की है कि सभी सार्वजनिक सभाओं, समारोहों को यथा-संभव स्थगित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी सार्वजनिक सभाएं अति-आवश्यक हों तो वहां पर लोगों को अपने बचाव के प्रति सावधानी बरतनें के लिए जागरुक करें तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वहां पर सभी उचित उपाय सुनिश्चित करें। WHO ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया है एवं भारत सरकार ने भी इसके मद्देनज़र विदेशों से आने वाले सभी आगंतुकों का वीज़ा 15 अप्रैल, 2020 तक रद्द कर दिया है। मैं हिमाचल प्रदेश में भी सभी सामूहिक जन-सभाओं, समारोहों आदि रोकने का आह्वान करता हूं तथा सभी प्रदेशवासियों से इस महामारी से

**12.03.2020/1205/TCV/AS-2**

निपटने के लिए सहयोग की अपेक्षा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इसमें बहुत आतंकित या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं परंतु एहतियात के तौर पर सावधानी बरतना आवश्यक है। यह एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहां का तापमान काफी डाउन है। इस बार सर्दी के मौसम का शैड्यूल भी काफी लम्बा रहा है। इस तापमान में यदि यह वायरस हो जाता है तो काफी परेशानी कर सकता है। इसलिए हमने जो जानकारियां दी हैं, उन पर अमल किया जाये ताकि इस वायरस से बचा जा सकें। यह एक महत्वपूर्ण विषय था जिसको मुझे माननीय सदन से सांझा करना था। इसके अलावा हमारी सरकार ने

पिछले कल Epidemic Disease Act 1897 के तहत H.P. Epidemic Disease COVID-19 Regulation भी अधिसूचित किया है जिसके तहत

**श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी ।**

12.03.2020/1210/RKS/DC-1

मुख्य मंत्री... जारी

modalities at home, जो घर के अंदर, परिवार के बीच आइसोलेशन संबंधित सारी जानकारी उसमें उपलब्ध करवाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारियों को पूर्ण जानकारी दी गई है और उन्हें सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। ...(व्यवधान) माननीय मुकेश जी, जो हमारे पास सूची उपलब्ध है उसके मुताबिक बाहर से आए हुए लोगों में इस तरह के लक्षण नहीं पाए गए हैं। हमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से 2066 लोगों की सूचना प्राप्त हुई थी जिनमें खांसी ,जुखाम और बुखार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। जिन चार लोगों को ये बीमारियां थी उनकी जांच करने के बाद सैंपल AIIMS को भेजे गये थे और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

पिछले कल नेता प्रतिपक्ष ने यस बैंक से संबंधित कुछ बातों का जिक्र किया था कि इनको कौन प्रमोट कर रहे हैं? जो राशि उस बैंक में जमा है, उसका क्या होगा? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाह रहा हूंः-

यस बैंक द्वारा दी जा रही ऊंची ब्याज दरों के कारण राज्य सरकार एवं सामान्य जनता ने अपना धन काफी मात्रा में यस बैक में जमा कर रखा था। यह प्रक्रिया काफी समय से चली आ रही थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 05.03.2020 तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न निवेशकों/ जमाकर्ताओं द्वारा यस बैंक की कुल नौ शाखाओं में 32,,000 खातों के माध्यम से कुल 1909.00 करोड़ रुपये की धनराशि जमा की गई थी। विपक्ष के माननीय नेता द्वारा यस बैंक में राज्य सरकार द्वारा जमा राशियों के बारे में जानना चाहा गया है।

प्रदेश सरकार की कुछ प्रमुख संस्थाओं द्वारा उपरोक्त बैंक में निम्नलिखित राशियां पिछली व वर्तमान सरकार के कार्यकाल में निवेशित की गईः-

12.03.2020/1210/RKS/DC-2

| संस्था का नाम | दिनांक 31.12.2017 से पूर्व निवेशित राशि (करोड़ रुपये में) | दिनांक 31.12.2017 के पश्चात् निवेशित राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लि0 | 750.00 | 625.00 |
| कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लि0 | 179.00 | 320.00 |
| एच.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम | 200.00 | 104.00 |
| एच.पी. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि0 | 11.80 | 25.00 |
| धर्मशाला स्मार्ट सिटी | 209.00 | 170.00 |

इसी तरह से 31.12.2017 से पहले 1349 करोड़ रुपये और उसके बाद जो राशि जमा हुई है उसमें 100 करोड़ रुपये कम है।

12.03.2020/1215/बी.एस./डी.सी./-1

**मुख्य मंत्री जारी...**

और यह राशि 1244 करोड़ रुपए है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी को येस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया येस बैंक में कम से कम 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा जिसे कि 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। मूल्यांकन के अनुसार यह धन राशि लगभग् 2500 करोउु रुपए तक बनती है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि उनका धन सुरक्षित रहेगा व एक सप्ताह के अन्दर-

अन्दर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इस संबंध में येस बैंक को पुनः इस संकट से उबारने हेतु योजना तैयार करेगा। ।

अध्यक्ष महोदय यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु Insolvency & Code-2016 (IBC-2016) लागू किया गया है, जिसका उदेश्य बैंकिग क्षेत्र में विशेषतः NPAs के संबंध में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना है। IBC-2016 कोड के लागू होने से पूर्व अधिकतर Bad Loan/NPA को बैंकों द्वारा गलत तरीके से सारणीबद्ध करके छुपाया जाता था। परन्तु IBC-2016 के लागू होने के बाद सभी बैंको द्वारा इस तरह के कार्य सार्वजनिक हो जाते हैं।

अतः मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हमें किसी भी प्रकार भय या चिन्ता को त्याग कर धैर्य बनाए रखना होगा। भारत सरकार सभी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बार-बार पिछले कल विपक्ष के नेता जी कह रहे थे और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था ये पूछ रहे थे कि इनका प्रमोटर कौन है। मैं इस संदर्भ में अवश्य यह कहना चाहता हूं कि यह प्रमोटर का विषय नहीं है। इस बैंक की इन्ट्रस्ट की बहुत ही आकर्षक स्कीमें निकाली थी और स्वाभाविक है कि लोगों ने सोचा कि यहां पैसा जमा करने से ब्याज के रूप में हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही में अखबार में छपे पत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं जिसके अनुसार श्रीमती प्रियंका गांधी द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग को तत्कालीन येस बैंक के संस्थापक, प्रबंधक, निदेश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, श्री राणा कपूर द्वारा 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया

12.03.2020/1215/बी.एस./डी.सी./-2

था। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से पूर्व के केन्द्र में सत्तासीन यू.पी.ए. सरकार द्वारा crony capitalism आरम्भ किया गया है। जिसका उत्तम उदाहरण पिछली यू.पी.ए. सरकार द्वारा वीडियोकॉन, डी.एच.एफ.एल.बोडा फोन जैसी कंपनियों को दिए गए ऋण हैं। जोकि निर्धारित प्रक्रिया तथा सतर्कता अपनाए बिना सत्तासीन लोगों के निकट लोगों को प्रदान किए गए। जो 2 करोड़ रुपए का चैक दिया गया हैं मेरे पास उस चैक की छाया

प्रति भी है। अतः ऐसे वे वजह के प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। आपने कल बहुत बोला इसलिए मैंने फैक्ट्स को स्पष्ट करने की कोशिश की है। पूरे देश में यह भी विषय बना हुआ है कि यह 2 करोड़ रुपए का चैक किस तरह से प्रदान किया गया? येस बैंक से संबंधित जो इंफोरमेशन चाहिए थी वह मैंने विस्तार से इस माननीय सदन में रखी है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, जब पिछले कल यहां चर्चा में हिस्सा ले रहे थे तो येस बैंक से संबंधित ये कुछ बिंदु आए थे। उसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमैंट दी है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी चर्चा के लिए माननीय सदस्यों की लम्बी सूची है इसलिए समय का विशेष ध्यान रखा जाए।

**श्री मुकेश अग्निहोत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

**अध्यक्ष :** माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पस्टीकरण दे दिया है अब इसमें क्या क्लेरिफिकेशन होनी है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

12.03.2020/1220/DT/HK-1

**मुकेश अग्हिहोत्रीः** माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आप किसी धर्म संकट मे फंस गए हैं।

**अध्यक्षः** कौन सा धर्म संकट? मैं नियमों के तहत व्यवस्था दे रहा हूं। अगर आपको कुछ स्पष्टीकरण लेना है तो आप लिख कर दें। आज इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है। ...(व्यवधान) क्या यही महत्वपूर्ण है कि माननीय सदस्य इसमें हिसा लेंगे। ...(व्यवधान) जब माननीय सदस्य आशा कुमारी बजट में बोलेगी तो उस वक्त आप यह विषय रख दें।...(व्यवधान) माननीय सदस्य सबसे पहले बोल रही है।

**मुकेश अग्निहोत्री :** अगर आप नहीं चाहते की हम कोई बात करें तो हम सदन से चले जाते हैं।

**अध्यक्षः** आपने क्यों जाना है? ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय आपकी तरफ से चर्चा का शुभारंभ हो रहा है। माननीय आशा कुमारी जी बोल रही हैं और उस समय अपना विषय रख दें।

**मुकेश अग्निहोत्री :** अध्यक्ष महोदय, आप पार्टी क्यों बनते जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है हम उस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन आप हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, नियम व उप-नियमों में ही चर्चा हो सकती है।

**श्रीमती आशा कुमारीः** प्रियंका गांधी जी के बारे में चर्चा करना कौन-सा नियम है। ...(व्यवधान) फिर तो नीरव मोदी पर भी चर्चा होगी ...(व्यवधान)

**अध्यक्षः** अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे। ...(व्यवधान)

**मुख्य मंत्री :** ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको हमने एक घंटा सुना और 15 मिनट तक आप यस बैंक पर बोलें। ...(व्यवधान)

**अध्यक्षः** इस पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि मेरी बात सुनेंगे या इनकी सुनेंगे। यह प्रतिस्पर्धा का मामल नहीं है।

**मुकेश अग्निहोत्री :** अगर एक तरफ ही बोलना है, मुख्य मंत्री जी ही बोलेंगे तो ठीक है।...(व्यवधान)

12.03.2020/1220/DT/HK-2

**अघ्यक्षः** माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप 58 मिनट तक बोले हैं। आप इतनी गर्माहट मत लाया करो। कृपया आप संक्षेप में अपनी बात रखें।

**मुकेश अग्निहोत्रीः** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं की आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस प्रदेश के लोगों का लगभग 19सौ करोड़ रुपये यस बैक में लगा है। 12 सौ करोड़ रुपये सरकार का लगा है और 7 सौ करोड़ रुपये जनता का लगा है। आपने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की बात की कि वह

उसका शेयर ले रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी को किसी लैवल पर आश्वासन मिला है या आपके किसी अधिकारी ने बात की है की यह जो यस बैक में 12 सौ करोड़ रुपये है या जनता का 7 सौ करोड़ रुपये है, क्या यह पैसा सुरक्षित है। आपने कहा की धैर्य बनाए रखें तो इसके लिए यस बैंक के प्रबंधकों से या किसी स्तर पर डायलॉग हुआ है। जो आप सदन में कह रहे हैं तो क्या यह 19 सौ करोड़ रुपये टोटल सेफ है। दूसरा, इन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पेंटिंग को लेकर बात की। अब बात निकलेगी तो वह दूर तक जाएगी। मोदी जी का 10 करोड़ का सूट किस ने खरीदा? वह कहां गया? नीरव मोदी कहां गया? ...(व्यवधान)

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

**12-03-2020/1225/एच.के.-एन.जी./1**

**श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी.....**

...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो लोग 10-10 करोड़ का सूट डालते हैं उनकी बोलियां लगती हैं, जो लोग विदेश भाग जाते हैं उस नीरव मोदी की कोई बात नहीं करता है। माननीय मुख्य मंत्री जी हमें बताएं कि क्या 1,900 करोड़ रुपये सुरक्षित है? क्या लोगों को पैसा मिलेगा?

**अध्यक्षः** माननीय मुख्य मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोगों की बड़ी विचित्र परिस्थिति है। कल आप 15 मिनट इसी विषय पर बोले और अध्यक्ष महोदय, बार-बार इनका कहना होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता।...(व्यवधान)

**श्री विक्रमादित्य सिंहः** आप बता दीजिए कि सबसे बड़ा डिफाल्टर कौन है?

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य कृपया सुनें और बैठे-बैठे न बोलें। जब आपको मौका मिलेगा तब बोलना। बैठे-बैठे बोलना अच्छा नहीं है।

**मुख्य मंत्रीः** बैठे-बैठे न बोलिए आप सुनिए तो सही।...(व्यवधान)

**श्री विक्रमादित्य सिंहः** सबसे बड़ा डिफाल्टर कौन है आप बता दीजिए?

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य यह ठीक बात नहीं है।...(व्यवधान)

**मुख्य मंत्रीः** इसे लेकर मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं। आपने हमसे कल कहा कि आपने कुछ नहीं बोला, आप चुप रहे, प्रदेश के लोगों का, सरकार का इतना पैसा डूब रहा है और ऐसे में आप कुछ नहीं बोले। आज जब हम बोले तो आपको उसमें भी आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, हमने स्थिति को बहुत स्पष्ट करने की कोशिश की है और डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बार-बार कह रहे थे कि इसको प्रोमोट करने वाले कौन हैं?



जब मैंने प्रोमोट करने वाले का थोड़ा-सा जिक्र किया तो आप उसके लिए परेशान हो गए।...(व्यवधान)

**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः** एक साल से बैंक डूब रहा था तो आपने उसमें पैसा क्यों लगाया?

**मुख्य मंत्रीः** एक साल से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी स्टेटमैंट में बड़ा साफ कहा गया है कि सरकार द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा आतंकित माहौल खड़ा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने कोरोना वायरस पर इतना बोल दिया कि ऐसा लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं बचेगा।...(व्यवधान)

**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः** क्या कोरोना पर आप ही बोलेंगे, इधर से कोई नहीं बोलेगा।

**मुख्य मंत्रीः** आप लोगों ने कहा कि उस आदमी को घण्टों बाहर ही रखा गया तो मैंने वेरीफाई किया कि नोरमल रूटीन में कोरोना वायरस का मरीज आया और 8 से 10 मिनट में उसे गाड़ी से आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाया गया। ...(व्यवधान)

**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः** मुख्य मंत्री जी ऐसा कुछ नहीं हुआ।

**मुख्य मंत्रीः** झूठ मत बोलो। इतना झूठ मत बोलिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य सुनिए।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि प्रस्तावित योजना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यस बैंक में कम-से-कम 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा जिसे 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो स्कीम उस सारे मामले में होगी उसके लिए we are waiting for that की उसे कैसे सैटल करना है।

**12-03-2020/1225/एच.के.-एन.जी./3**

यह राज्य सरकार का विषय नहीं है, यस बैंक के मामले की सारी प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है। आर.बी.आई. ने इसमें प्रशासक नियुक्त किए हैं और यदि ऐसा कहा जाए कि राज्य सरकार इस मामले में दख़ल देगी तो ऐसा नहीं है। यह सही है कि इसमें हमारा पैसा जमा है और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जितना भी पैसा जमा था उसमें से पाई-पाई पैसा सरकार का भी और प्रदेश की जनता का भी वापिस मिले। लेकिन उसके लिए जो स्कीम आने वाली है हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इतना शोर मत डालिए। आप ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कोरोना भी भाजपा वालों ने लाया है और यस बैंक का घोटाला भी हमने किया हो...(व्यवधान) राजनीतिक मकसद से हर बात को कहना, हर बात को करना...(व्यवधान) कोरोना वायरस पर आप वॉकआऊट करके चले जाते हैं। ...(व्यवधान) माहौल को ख़राब मत कीजिए।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

12/03/2020/1230/MS/YK/1

**मुख्य मंत्री जारी**------

...(व्यवधान)-- अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बहुत संवेदनशील मसले होते हैं उनमें अनावश्यक रूप से राजनीति मत डालो और कोरोना में भी राजनीति मत डालो। आपने कल 15 मिनट यस बैंक के बारे में बोला और आप इस बात को लेकर हमें ही सुनाते रहे। आपने कहा कि कोरोना वायरस आ गया है। हमने कहा कि रिपोर्ट तो आने दो। आपने कहा कि अब प्रदेश में कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब तीनों मरीज़ों की रिपोर्ट आई तो वह निगेटिव आई। ऐसा माहौल ख़राब मत कीजिए, मैं यही कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

**अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, बैठिए।

**मुख्य मंत्रीः** ...(व्यवधान) जहां तक तैयारियों की बात है, हम बार-बार कह रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील विषय पर गलत और भ्रमित करने वाली जानकारी इस माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जनता तक सही बात पहुंचनी चाहिए। जो फैक्चुअल पोजिशन है वह बात हमने सरकार की ओर से कही है। हम सारे मामलों में गम्भीर हैं। जितने आप लोग गम्भीर हैं उतने ही गम्भीर हम लोग भी हैं बल्कि आपसे ज्यादा ही गम्भीर हैं लेकिन गलत जानकारी लोगों को देना और हर बात को लेकर राजनीति करना सही नहीं है।

12/03/2020/1230/MS/YK/2

**<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>**

**श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर):** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्षः** मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि...(व्यवधान) आप लोग बैठिए। मैं आप सबकी बात सुनूंगा। आज यहां पर बोलने वाले 20 सदस्य हैं और 12-15 मिनट एक सदस्य लेगा तो चर्चा 5 घण्टे तक चलेगी। इसलिए जो भी माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे, वे

समय का ध्यान रखें। माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर किया है, कृपया आप संक्षेप में बोलें।

**श्री जगत सिंह नेगीः** माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने नियम-323 के तहत मुझे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ करने का मौका दिया है।

अध्यक्ष जी, संसदीय प्रणाली में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर एक सदस्य का बहुत बड़ा अधिकार है। जो मुद्दे मैं इस नियम के तहत उठा रहा हूं वे बहुत ही महत्व के हैं और वे इस माननीय सदन के जो नियम बने हुए हैं, उसके संचालन से संबंधित हैं। इसमें मेरा पहला प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो भी पक्ष और विपक्ष से माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं, उनकी संख्या 900-1000 तक जा रही है। अध्यक्ष जी, जो तरीका यहां पर प्रश्नों को लगाये जाने का अपनाया जा रहा है, वह आपके सचिवालय में जो सैक्शन है, उनकी मर्जी पर पिक एण्ड चूज है। जबकि हमने विधान सभा को पेपरलैस बनाया हुआ है और यहां पर डिजिटल सिस्टम भी बनाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर प्रश्नों को तैयार करने का उन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा है और उसके माध्यम से वहां प्रश्न उठाए जाते हैं। उसमें फिर किसी की भी शिकायत नहीं रहती है कि मेरा प्रश्न पीछे लग गया और इनका प्रश्न आगे लग गया। इसलिए पारदर्शिता को रखने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि लोकसभा की प्रणाली के अनुसार ही यहां पर भी प्रश्नों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिया जाए। दूसरा मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि यहां पर नियम-101 के तहत हम अपने जो भी रेजोल्यूशन देते हैं, उसके लिए बैलेट होना अनिवार्य है। लेकिन आप हमें बुलाते ही नहीं है और आपने जो भी तरीका अपना रखा है, उसके हिसाब से रेजोल्यूशन लग जाता है। इससे हमारा रेजोल्यूशन देने का कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों ने रेजोल्यूशन दिए हैं अगर उनके बीच में सहमति बनती है जैसे नम्बर वन, टू, थ्री या फोर, वह अलग बात है

**12/03/2020/1230/MS/YK/3**

लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है तो बैलट लगना चाहिए। यह नियम माननीय सदन के बने हुए हैं और यह इन नियमों के तहत ही होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई माननीय

सदस्य बोलते हैं तो उसके भी नियम बने हुए हैं। माननीय सदस्य चाहे पक्ष के बोलें या विपक्ष के बोलें, बीच में खासकर मंत्रीगण इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरवीन करना है तो सदस्य के बोलने के बाद कर सकते हैं यानी मंत्री जी ने यदि कोई स्पष्टीकरण देना है तो वे आपकी अनुमति से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इस नियम को भी सख्ती से यहां पर लागू करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, मैं साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रिविलेज के केसिज आपके पास दिए हुए हैं, वे केस प्रिविलेज कमेटी को जाने चाहिए लेकिन वे कई-कई महीनों से प्रिविलेज कमेटी को नहीं जा रहे हैं। यह प्रिविलेज भी लोकतंत्र में खासकर सदस्यों का एक बहुत बड़ा अधिकार है और उसी अधिकार का अगर हमें मौक़ा न मिले या प्रिविलेज कमेटी उस पर फ़ैसला न करे तो इस प्रिविलेज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक निवेदन जो हम बार-बार पिछले दो सालों से आपसे कर रहे हैं, वह यह है कि आज के बदलते परिवेश में विधायकों की भूमिका के ऊपर चर्चा करने की बड़ी आवश्यकता है। बार-बार कहने के बावजूद विषय नहीं लगता है। मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरह के विषयों को यहां पर चर्चा के लिए लिया जाए। एक मेरा और निवेदन है कि जैसे हमारे प्रश्न रिजैक्ट हो जाते हैं; मान लो मैंने 50 प्रश्न दिए हैं जिसमें से 20 रिजैक्ट हो गए तो उसकी कम-से-कम मुझे सूचना तो मिलनी चाहिए कि मेरा प्रश्न क्यों रिजैक्ट हुआ है। हम सोचते हैं कि प्रश्न यहां आएगा-आएगा और समय निकल जाता है तथा वह प्रश्न ही नहीं लगता है। ये कुछ बातें मैं अध्यक्ष जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

अध्यक्ष जे0के0 द्वारा-----

**12.03.2020/1235/JK/YK/1**

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं पूरी तरह से आपको संरक्षण दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो यहां पर सुझाव दिए हैं, उन पर हम अवश्य गौर करेंगे। मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है क्योंकि वैसे यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बनता नहीं है लेकिन माननीय सदस्य इस प्रकार के विषयों पर आप चैम्बर में आ करके भी चर्चा कर सकते हैं। आपने जो चर्चा की है, उस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, इस बारे में मैं आपको आश्वस्त करवाना चाहता हूं।

अब वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों वार्षिक वित्तीय विवरण पर आगे चर्चा प्रारम्भ होगी। अब इस चर्चा में सर्वप्रथम आदरणीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी भाग लेंगी।

**12.03.2020/1235/JK/YK/2**

**श्रीमती आशा कुमारीः** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान जो मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 6 मार्च, 2020 को प्रस्तुत किए, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मुख्य मंत्री जी माननीय सदन से चले गए हैं। वे अपनी बात रख करके चले गए हैं। बहुत सारी बातें थी जिनमें शायद चर्चा नहीं भी करनी थी मगर आज जिस तरह का माहौल यहां पर बना है, शायद अब उन पर चर्चा करनी भी पड़े।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी भी यहां पर नहीं हैं। बड़े ही नाटकीय ढंग से, अच्छा अब राकेश पठानिया जी हाउस में आ गए, आपका स्वागत है। बड़े ही ड्रामैटिक तरीके से मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो भाषण दिया, उसका इन्होंने यहां पर विवरण किया। मैं तो कहती हूं कि आपको तो School of Drama में हैड इंस्पैक्टर होना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री जी तो डायरैक्टर होंगे। He will be the senior person. लेकिन आपका जो प्रेज़ैन्टेशन था ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दो मिनट पहले श्री जगत सिंह नेगी जी ने आपको रूल याद दिलाया और श्री सुरेश भारद्वाज जी संसदीय कार्य मंत्री हैं,वैसे सदस्य बैठ करके नहीं बोलते हैं, मंत्री तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं और ये बोलने से बाज ही नहीं आते हैं। मेरे तो ये मामा भी हैं, ये बाज ही नहीं आते हैं। अभी भी ये बोल ही रहे हैं। इनका हम क्या करें? माननीय अध्यक्ष महोदय इन मामों का क्या करूं। एक अच्छे मामा (श्री नरेन्द्र बरागटा जी की ओर इशारा करते हुए) इधर बैठे हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो बहुत सारी बातें कीं, वे यहां पर आंकड़ों को लेकर रख दी हैं लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहती क्योंकि आपके पास समय भी

सीमित है। मुख्य मंत्री जी ने जो यह अभिभाषण दिया है, जो इस साल हिमाचल प्रदेश के 50 साल स्टेटहुड के हुए हैं, उसको लेकर चालू होता है। मैं इसमें थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी कि यह स्टेट हुड का सफ़र तब चालू हुआ था जब हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ। हिमाचल प्रदेश जिसको हम पुराना हिमाचल कहते हैं, पहले वह एक चीफ कमिशनर प्रोविंसिज बना। उसके बाद 15 अप्रैल, 1948 को सी-पार्ट स्टेट बना। फिर आदरणीय राम लाल ठाकुर जी और श्री सुभाष ठाकुर जी जहां से आते हैं, बिलासपुर आखिरी रूल्ड स्टेट

**12.03.2020/1235/JK/YK/3**

था, दिनांक 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर भी ओल्ड हिमाचल में मर्ज़ हो गया, उसके बाद रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन बना, उसमें यह फैसला करना था कि यह जो छोटे स्टेट्स हैं, उनके साथ क्या किया जाए? जो मेजोरिटी ऑफ मैम्बर्ज़ थे, उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसको पंजाब में मर्ज़ कर देना चाहिए। मगर एक माइनोरिटी मैम्बर,जस्टिस फैज़ल अली ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि हिमाचल को स्वतंत्र रखना चाहिए, इसको पंजाब के साथ नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि इसका कल्चर अलग है, इसका अपना एक अस्तित्व है, इसको खत्म नहीं करना चाहिए।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

**12.03.2020/1240/SS-AG/1**

**श्रीमती आशा कुमारी क्रमागत :**

और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस माइनॉरिटि रिपोर्ट को एक्सैप्ट करके हिमाचल प्रदेश को as Union Territory कायम किया। उसके बाद 1 नवम्बर, 1966 को पंजाब का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ। पंजाब के रिऑर्गेनाइजेशन में जो पहाड़ी क्षेत्र थे वे हमारे में आए। राकेश पठानिया जी आज हमारे साथ इसीलिए मौजूद हैं। मुकेश जी भी आए, सारे पहाड़ी इलाके आए। अध्यक्ष महोदय, आपका इलाका भी आया। लाहौल, कुल्लू और ये सारे इलाके आये तथा जो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है वह अस्तित्व में आया। मगर उस वक्त

हमें Union Territory का दर्जा प्राप्त था। उसके बाद 19 दिसम्बर, 1970 हिमाचल प्रदेश के लिए पार्लियामैंट में एक ऐतिहासिक दिन था। पार्लियामैंट में 'The State of Himachal Pradesh Act' को पारित किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब उस बिल पर चर्चा हो रही थी तो एक माननीय सदस्य जो यहां अभी भी सदस्य हैं उस वक्त युवा सांसद हुआ करते थे। उन्होंने उस चर्चा में भाग लिया जोकि बाद में छः बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। उस वक्त हिमाचल प्रदेश को विधान सभा की 48 सीट्स दी जा रही थीं, इन्होंने लड़ाई लड़ी और रात के 2.00 बजे पार्लियामैंट में यह ऐक्ट पारित हुआ। इनकी अमैंडमैंट 70 सीटों के लिए थी मगर 68 सीट्स हिमाचल प्रदेश के लिए मानी गईं। आज जो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है और जो हिमाचल प्रदेश स्टेट ऐक्ट बना उसमें राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉ0 यशवंत सिंह परमार का बहुत बड़ा योगदान है। 25 जनवरी, 1971 को रिज के मैदान पर बर्फ पड़ रही थी। पड़ती बर्फ में इंदिरा गांधी जी यहां आईं और उन्होंने हमें पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दिया। डॉ0 यशवंत सिंह परमार, वीरभद्र सिंह जी और ठाकुर राम लाल जी वहां उपस्थित थे और इन सब लोगों की वजह से हमारा प्रदेश अपने इस अस्तित्व में आया। फिर मैं कहना नहीं चाहती कि उस वक्त एक पार्टी थी जो कहती थी कि स्टेटहुड मारो ठुड। परन्तु यह बार-बार याद दिलाना पड़ता है। इस हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने के लिए, इसको स्टेटहुड दिलाने के लिए पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी, जवाहर लाल नेहरू, यशवंत सिंह परमार और वीरभद्र सिंह जी को जाता है। आप लोगों का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ...(व्यवधान) बजट पर ही बोल रही हूं। आप ही ने लिखा है। आप (माननीय जल शक्ति मंत्री से) अस्तित्व के ही विरोधी हैं। आपका क्या किया जाए?

**12.03.2020/1240/SS-AG/2**

अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने इस साल का कुल बजट 49131 करोड़ रुपये पेश किया है उसमें राजस्व प्राप्तियां 38439 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 39123 करोड़ रुपये अनुमनित है। कुल राजस्व घाटा 684 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 7272 करोड़ रुपये अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, यह अनुमानित है जो यहां पर पेश किया गया है परन्तु मुझे लगता है कि यह अनुमान से बहुत परे है। वास्तविकता कहीं और जायेगी क्योंकि जो ये रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहे हैं, these are based on grants from Government

of India. हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह सब के सामने है। आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें यह बात सामने आई कि आपका agriculture, forestry, fisheries, mining, quarry, manufacturing, electricity, gas, water supply, other utility services, trade, hotels, broadcasting etc., public administration and defence इन सब सैक्टर्ज़ में गिरावट आई है। यह मैं नहीं कह रही हूं क्योंकि महेन्द्र सिंह जी बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि फिगर्ज़ कहां से लाए तो यह आपका आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। ...(व्यवधान) चलो मुझे खुशी है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। सिर्फ दो सैक्टर्ज - कंस्ट्रक्शन और रीयल एस्टेट हैं जहां पर ग्रोथ हुई है। जब हम कहते हैं कि "Himachal for sale" तो हम गलत नहीं कहते हैं। कंस्ट्रक्शन सैक्टर एक ऐसा सैक्टर है जहां पर बढ़ोत्तरी आई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ज़मीनें बेचने के तरह-तरह के तरीके और धारा-118 को subvert करने के तरह-तरह के तरीके निकाले जा रहे हैं। यह मैं नहीं कह रही हूं यह आपका आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है।

जारी श्रीमती के0एस0

**12.03.2020/1245/केएस/एजी/1**

**श्रीमती आशा कुमारी जारी**---

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से the State GDP has fallen to 5.6 per cent. यह सब अनुमानित है। अभी फाइनल फीगर्ज़ तो बाद में ही आएंगे। मुझे लगता है कि अगले साल की भी आपकी जी.डी.पी., जो आपने प्रेडिक्शन की है, वह आपकी रहने वाली नहीं है। इसका कारण मैं समझती हूं, मैं कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं मगर यह पूरा विश्व देख रहा है और हम भी देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चर्मरा गई है, तार-तार हो गई है। आज हिन्दुस्तान का जी.डी.पी. 4. कुछ है। आज सुबह rupee to a dollar Rs.74.50 हो गया। फिर मैं सुषमा स्वराज जी को याद करुंगी जो कहती थीं कि जैसे-जैसे रुपया गिरता है, वैसे-वैसे हिन्दुस्तान की साख गिरती है, तो कितनी और गिराओगे? आप जानते हैं, मैं यह नहीं कहती कि यह आपकी गलती है परन्तु मैं यह कह रही हूं कि वास्तविकता की तरफ़ देखो कि आज ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल है? आज सैंसेक्स लोएस्ट पर है। निफ्टी गिर चुकी है। हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है जो आज से लगभग 45 साल पहले रही होगी। इतना बुरा हाल है।

अध्यक्ष महोदय, जैसे मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी स्पीच में कहा था कि जो एक्सपैक्टिड रेवन्यू है, वह आपने दिखाया है कि वह भारत सरकार से आएगा। भारत सरकार के पास अपने पास पैसा नहीं है, वह आपको कहां से देगी? They are defunct. उनकी जी.डी.पी. तो हमसे भी नीचे चली गई है। इतनी फाइनैंशियल मिस-मैनेजमैंट हिन्दुस्तान में नहीं हुई है जितनी आज की तारीख़ में है। इतने डिफॉल्टर्ज़ हिन्दुस्तान में नहीं हुए हैं जितने पिछले तीन साल में हुए हैं। इतने लोग, इतने करोड़ रुपये ले कर देश छोड़कर नहीं भागे हैं, जितना अभी हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी चले गए, मैं आपसे फिर से निवेदन करुंगी कि जो इस हाउस का सदस्य नहीं है, उसके बारे में हाउस में चर्चा नहीं होती। इन्होंने प्रियंका गांधी जी का नाम लिया। प्रियंका गांधी जी ने अपनी एक ही पेंटिंग नहीं, 10 पेंटिंग्ज़ ऑक्शन के लिए, बेचने के लिए रखीं। ...(interruption) Mr. Mantri, I know better than you.

**12.03.2020/1245/केएस/एजी/2**

एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्ज़ हैं। उनकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिके, it is nothing. ...(व्यवधान) आपका सूट 10 करोड़ रुपये में बिक गया, वह बहुत अच्छा था? वाह, वाह, फिर वही बात, तुम करो तो रास लीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। जल शक्ति मंत्री जी, 10 करोड़ में नीरव मोदी ने आपको ठगा, 37 हजार करोड़ ले कर भागा। ---(***)--- कहां की बातें करते हैं, आप बात करेंगे? ...(व्यवधान) कोट बेचने गए थे, सूट-बूट की सरकार हमसे बात करेगी?अध्यक्ष महोदय, अगर हम टूरिज्म सैक्टर में देखें, इसमें इतनी गिरावट आई है, आपका इकोनॉमिक सर्वे का टेबल कहता है कि वर्ष 2017 में विदेशी और भारतीय टूरिस्ट मिलाकर 196.02 lac people came to Himachal Pradesh. और यह फीगर वर्ष 2019 में घटकर 172.12 हो गई है। लगभग 24 लाख टूरिस्ट आपका कम हो गया है, इसका कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा-सीधा कारण है डिमॉनेटाइजेशन। जब से डिमॉनेटाइजेशन हुआ है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो स्वभाविक है कि उनके पास घूमने-फिरने के लिए भी पैसा नहीं है। इसका सीधा

असर हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो रहा है। This is not a good sign at all.अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज़ के लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती थी परन्तु वे चले गए इसलिए जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद कर देती हूं कि आपने जो छोटे-छोटे तीन लोलीपॉप हमें दिए हैं, एक आपने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत डेढ़ करोड़ रुपये से 1.75 करोड़ कर दिए तथा विवेक अनुदान 10 लाख कर दिया, यह ठीक है ओर नाबार्ड 105 से 120 कर दिया, मुझे लगता है कि नाबार्ड का पैसा और ज्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास अपनी फंडिंग है नहीं, आपको लोन ही लेना है तो नाबार्ड से लीजिए। NABARD is a better agency. NABARD is not so much of a fraud agency.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

---

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

**12.03.2020/1250/av-as/1**

**श्रीमती आशा कुमार क्रमागत**

मैं समझती हूं कि इसको अगर डेढ़ सौ करोड़ रुपये भी कर दिया जाए, ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्या, कृपया समय का ध्यान रखें।

**श्रीमती आशा कुमारी :** अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलूंगी और मैंने आपको पिछले कल ही बोल दिया था कि मैं भी आधा घंटा बोलूंगी। जितना समय श्री राकेश पठानिया जी ने लिया है; मैं भी उतना ही समय लूंगी। मैंने समय नोट करके रखा हुआ है और राकेश पठानिया जी ने 30 मिनट का समय लिया था।

आपने लिखा है कि कानून-व्यवस्था बहुत बढ़िया चली हुई है। मैं यहां पर आंकड़े रखना चाहूंगी कि पिछले साल 172 मर्डर, 114 अटैंप्ट टू मर्डर, 718 रेप, 971 चाइल्ड एब्यूज, तथा 440 क्रूअल्टी टू वीमैन; मंत्री महोदया, इसमें तो आप हमारा साथ देगी। मण्डी का एक केस था,जहां पर लोगों ने एक वृद्ध महिला को घसीट कर मारा-पीटा था। इस तरह के मामले जो पहले कभी नहीं देखे; आज प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। The Molestation cases have been reached to 1050, this is a shocking figure. एन0डी0पी0एस0 व दूसरे रिलेटिड मामलों में 2954 एफ0आई0आर्ज0 दर्ज़ हुई हैं और इसके अंतर्गत 10 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया। *Chitta* is a synthetic drug. हम बार-बार कह रहे हैं कि ड्रग्ज के ऊपर हमारा जितना कंट्रोल होना चाहिए; वह नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है मगर जिस तरह से पंजाब सरकार ने एस0टी0एफ0 बनाई है जो सिर्फ ड्रग्ज मीनेंस को ही डील करती है; उस तरह से सोचने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त रीहैबिलिटेशन सैंटर्ज को प्रोपर्ली चलाने की ज़रूरत है। हमारे पास शायद दो रीहैबिलिटेशन सैंटर्ज हैं और मुझे लगता है कि वे भी डीफंक्ट हैं। उसके लिए ट्रेन्ड डॉक्टर्ज की ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी कोरोना वायरस पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि विपक्ष ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं यह कहना चाहती हूं कि विपक्ष नहीं दिखा रहा बल्कि डब्ल्यू0एच0ओ0 ने इसको एपिडैमिक घोषित किया है

**12.03.2020/1250/av-as/2**

and The World Health Organization is not the Opposition. इस संस्था को आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। यह वह संस्था है जो कि विश्व की स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिंता करती है। यहां पर जैसे बात रखी है कि कोविड-19 Corona Virus is an old virus जिसका नया स्ट्रेन अभी डिस्कवर हुआ है COVID-19, it is a heavier virus जो कि ज़मीन पर रहता है तथा सांस के द्वारा कंटेजियस नहीं होता है। इसके लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है और अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं तो कौन-सी बुरी बात है? मगर इसमें मैं कुछ और कहना चाहती हूं, इस कोरोना वायरस की वजह से हमें सारे बीजा कैंसिल करने पड़े और हिन्दुस्तान को भी बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल

करनी पड़ी; जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा। आपने कभी यह सोचा कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? आपने यह सोचा है कि यहां पर जो लोग इंवैस्ट करने आ रहे थे या आना चाह रहे थे; वह सब रुक जायेगा तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? Should we not worry about it? Opposition आपके साथ-साथ ताली बजाये कि बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है उसको जरूर बरतना चाहिए; मैं आपसे सहमत हूं कि इसके लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल एहतियात बरतने की आवश्यकता है परंतु साथ में इसके इंपैक्ट असैस करने की भी ज़रूरत है। आपके यहां जो इंवैस्टर्ज और टूरिस्ट्स आयेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब आगे टूरिस्ट सीजन आने वाला है। यहां पर माननीय सुन्दर सिंह जी बैठे हैं और कुल्लू-मनाली का मैक्सिमम टूरिस्ट सीजन मई-जून के दौरान होता है। आपके यहां जब तक तापमान 30 से 35 डिग्री सैल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ेगा यह वायरस खत्म नहीं होगा। 30 to 35 whatever it is, but it will take some time to finish also. -यह महामारी इतनी फैल चुकी है कि युनाइटेड किंगडम की हैल्थ मिनिस्टर she has been tested positive for Corona Virus. तो कोई यह न समझे कि मुझे नहीं हो सकता। यह महामारी है, अभी होली की छुट्टियों की वजह से आपकी युनिवर्सिटीज बंद हैं। ओह! मुझे बलबीर सिंह वर्मा जी दिख गये, मैं कल आपका भाषण सुन रही थी। मुझे याद आया कि जब ये पांच साल पहले भाषण दिया करते थे तो ऐसा ही भाषण देते थे। इन्होंने अपने भाषण में केवल कुछ शब्दों को बदला जैसे पहले राजा साहब बोलते थे और अब जय राम ठाकुर बोला। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने भाषण में एक भी शब्द नहीं बदला।

टी सी द्वारा जारी

**12.03.2020/1255/TCV/AS-1**

**श्रीमती आशा कुमारी... जारी**

मैं 5 साल से सुनती आ रही हूं। अध्यक्ष महोदय, ये जो यूनिवर्सिटीज खुलेंगी not only Himachal Pradesh University, Shimla हिमाचल प्रदेश में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां बाहर से भी बच्चे आते हैं लेकिन कौन कहां से आएगा, उनकी चैकिंग के लिए हमारे पास

व्यवस्था नहीं है whether they are positive or negative हमें ये तैयारियां करनी चाहिए यह हमारा कंसर्न है। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि माइनिंग सैक्टर में गिरावट आई है। माइनिंग सैक्टर में गिरावट आई है, या खनन की आय में गिरावट आई है। माननीय मंत्री जी यहां बैठें हैं, मैं इलीगल माइनिंग पर नहीं बोलना चाहती हूं क्योंकि इलीगल माइनिंग एक चीज हैं और ओवर लोडिंग अलग चीज़ है। आप जानते हैं कि आप मैक्सिमम एम-फॉर्म 9 टन्स का देते हैं, am I correct? लेकिन जो गाड़ियां लोड हो रही हैं, वे 50-60 टन्स लोड हो रही हैं। आप हर टन पर 3000 रुपये की रायल्टी कलैक्ट नहीं कर रहे हैं। आप कम-से-कम ओवर लोडिंग को तो बन्द करवाइये। इससे प्रदेश की आय बढ़ेगी और जो आय में भारी गिरावट आई है, इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यहां चम्बा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का ज़िक्र आया। ये अच्छा हुआ कि एक ही लाइन में आया क्योंकि उस एक लाइन के अलावा चम्बा में हुआ ही कुछ नहीं। सिर्फ़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसके आगे कोई चर्चा नहीं है क्योंकि चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सिर्फ़ डिक्लेयर किया गया है और माननीय सदस्य जो कि हमारे साथ यहां पर उपाध्यक्ष हैं, ये भी इसमें मेरा साथ देंगे। हमारे जिले के लिए इस स्कीम के तहत कुछ नहीं आया है। सबसे मेज़र इश्यू हमारा अन-इम्प्लायमैंट है, आज माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी का प्रश्न लगा था। हम अन-इम्प्लायमैंट की आंकड़े देने में घबरा क्यों रहे हैं? जब हम कह रहे कि हम नौकरियां दे रहे हैं तो अन-इम्प्लायमैंट की आंकड़ों में भी कमी आनी चाहिए थीं। यह कमी क्यों नहीं आ रही है?

**12.03.2020/1255/TCV/AS-2**

What is the reason? श्री विक्रमादित्य सिंह जी बोल रहे थे, इनके प्रश्न के जवाब में आया था कि हिमाचल प्रदेश में 14,00,000 बेरोज़गार हैं। ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं? जो आपके so called Global Investors Meet और आपके जो मेलें हैं जिसमें आपने इम्प्लायमैंट दी, वहां

कोई इम्प्लॉयमैंट नहीं मिल रही है और जिनको मिल भी रही है, वे छोड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कंडीशन्ज बहुत ख़राब है।

अध्यक्ष महोदय, एयरपोर्ट्स के लिए 1013 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। हम तो सोच रहे थे कि यह मण्डी के लिए रखा है लेकिन आपने यहां बताया कि यह सबके लिए है। यदि यह सबके लिए है तब तो यह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। एक मण्डी के एयरपोर्ट के लिए 5000 करोड़ रुपये चाहिए। पिछले कल मुख्य मंत्री जी स्वयं बोल रहे थे कि अगर कुल्लू के एयरपोर्ट को चैनलाइज करना है तो 7000 करोड़ रुपये तो चैनलाइजेशन के लिए चाहिए। एयरपोर्ट एक्सपैंशन के लिए तो पता नहीं कितने और चाहिए। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन के लिए भी पैसा चाहिए और इस 1013 करोड़ रुपये में ही हेलीपोर्ट्स भी इसी में बनने हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि यह पर्याप्त है या वास्तविक है, ये सिर्फ़ सांकेतिक हैं। आप इनको बनाएंगे तो हम आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुकेश अग्निहोत्री जी ने एक पर्टिनैंट प्वाइंट रेज किया था कि 7वें वित्तायोग की सिफ़ारिशें अभी आनी है। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। वह वित्तीय बोझ आप पर पड़ना ही है। अभी शायद 15वें वित्तायोग की पूरी सिफ़ारिशें नहीं आई हैं। ये सिर्फ़ एक साल की आई हैं, इसके बारे में इनका क्या इरादा है, यह भी स्पष्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यस बैंक पर चर्चा नहीं करनी थी और जो मेरे प्वाइंट्स हैं, उनमें भी यह कोई प्वाइंट नहीं था।

**श्री आर0के0एस0 द्वारा... जारी**

12.03.2020/1300/RKS/DC-1

श्रीमती आशा कुमारी.... जारी

मुख्य मंत्री महोदय ने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। यस बैंक की सच्चाई क्या है? यस बैंक एक फलता-फूलता बैंक था। ---(***)--- उन सभी कम्पनीज के नाम दखिए, उनमें कॉमन स्ट्रेन क्या है? अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम न लिया होता तो मैं यह चर्चा बिल्कुल नहीं करती । इसमें कॉमन यह है कि

---(***)--- आप क्या बात कर रहे थे? आपने यह बैंक खुद डुबोया है और उसमें हम भी फंस गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा था कि बैंकिंग में इन्वैस्टमैंट तब होती है जब आपको बैंक के टर्म्ज एंड कंडिशन्ज अट्रैक्टिव लगते हैं। टर्म्ज एंड कंडिशन्ज भी अट्रैक्टिव थे और बैंक भी स्टेडी चला था। मगर आपने लॉन्स दिलवाए, एन.पी.ए. करवाया और उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं किया। आप आर.बी.आई. से इसलिए चर्चा कर रहे थे क्योंकि आपको फंडिंग मिल रही थी। ...(व्यवधान)

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप करें।

**श्री राकेश पठानियाः** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो नाम लिए हैं और जो फंड से संबंधित बात की है उसे एक्सपंज किया जाए।...(व्यवधान)

**अध्यक्षः** ठीक है, हम इसे दखेंगे और इस प्रकार के शब्द होंगे तो उन्हें एक्सपंज किया जाएगा।

---

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

12.03.2020/1300/RKS/DC-2

**श्रीमती आशा कुमारीः** अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल डिलीट नहीं होंगे।...(व्यवधान) Every agency has reported this....(interruption) Speaker Sir, I am talking to you. ....( interruption) every agency is reporting this, मैंने नहीं रिपोर्ट किया है।...(व्यवधान) आप फाइनैंसियल एजैंसी का पढ़िए, आप वित्त मंत्री का पढ़ लीजिए। ...(व्यवधान) आपको कुछ पता नहीं है। ...(व्यवधान) आपने बैंक को डुबोया है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप करें। आपका समय 27 मिनट से ऊपर हो गया है, कृपया वाइंड-अप करें।

**श्रीमती आशा कुमारीः** अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें चुप करवाइए। ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि यस बैंक में जो कुछ हुआ है वह भारत सरकार की बैड फाइनैंसियल मैनेजमैंट से हुआ है मगर उसका असर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करें कि जो 1919 करोड़ रुपये हिमाचलवासियों और हिमाचल सरकार का है उसको सुरक्षित किया जाएगा। ...(व्यवधान) इस बजट अनुमान का समर्थन करने के लिए कुछ नहीं है। यह बजट ऐसा है जैसे एक गृहिणी खाना बनाती है और देखती है कि यह खाना स्वाद नहीं बना है तो उसमें बहुत सारी सजावट कर देती है। यह बजट भी सजावट करके पेश किया गया है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसका समर्थन किया जाए इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद।

**अध्यक्षः** माननीय जल शक्ति मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

**जल शक्ति मंत्रीः** माननीय अध्यक्ष जी, जो बहन आशा कुमारी जी ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, गलत नाम लिए हैं, कृपया उनको एक्सपंज किया जाए।

**अध्यक्षः** माननीय मंत्री जी, ठीक है, हम इन शब्दों को एक्सपंज करवा देंगे। अब माननीय सदस्य श्री हंस राज जी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

12.03.2020/1305/बी.एस./डी.सी./-1

**अध्यक्ष :** अब माननीय हंस राज, उपाध्यक्ष चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री हंस राज (उपाध्यक्ष) :** माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर चर्चा हेतु आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी का और माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र बरागटा जी का भी आभारी हूं। मेरी कुछ समस्या थी इसलिए मैं पहले चर्चा में भाग नहीं ले पाया था। बजट पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। क्या घाटे में है क्या बाधे में है, इस पर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही

कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस विजन के साथ मुख्य मंत्री बने थे और जिस तरह से उन्होंने सपथ ली थी उस दिन के बाद जिस जनमंच की विपक्ष द्वारा बड़ी आलोचना होती है या जिस जनमंच की बड़ी परिचर्चा होती है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जो सरकार अपना कार्यभार संभालते ही सीधे अपनी जनता के बीच में चली जाए और जवाबदेह सरकार बने तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं और जो आशा, आकांक्षा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके जनता ने दी थी उस पर खरा उतरने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से 47,848 शिकायतें आती हैं और उनमें से 44,000 शिकायतों को आप कवर कर देते हैं, उसका निष्पादन कर देते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। मैं इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद माननीय मुख्य मंत्री जी को, इनकी टीम को और हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार को देना चाहता हूं।

मैं विशेषतौर से कृषि, बागवानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं। बजट की व्यवस्था भी की है फिग्र्ज में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का भी अभाव है सभी लोगों ने अभी भोजन भी करना है, भोजन का समय भी हो चुका है और अभी माननीय सदस्यों का सामूहिक चित्र भी होना है। इसलिए माननीय वीरभद्र सिंह जी भी आए हुए हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा लेकिन मुझे व्यक्तिगत जो लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा किया है।

12.03.2020/1305/बी.एस./डी.सी./-2

जिस तरह से कलस्टर यूनिवर्सिटी की भी चर्चा हुई है और व्यापक चर्चा हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब एस.एम.सी थी तो बहुत से स्कूलों के पद भर दिए जाते थे। हमने बहुत सारी पोस्टें भरी भी हैं परंतु हमारी बहुत सारे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जिनमें आयल, चीली और बैरागढ़ है इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर पद भरे नहीं जा रहे हैं। हम भरने की कोशिश कर रहे हैं परंतु लोग

ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि उसके लिए हमें विज्ञापन उसी स्कूल का निकालना पड़ेगा जहां पर पोस्ट को भरा जाना है और उसके लिए ही हम आवने मांगे। तब जा करके माननीय अध्यक्ष जी ये पद भरे जाएंगे क्योंकि मेरी चिंता और लोगों की भी चिंता है कि 3-4 सालों से ये पद खाली पड़े हैं।

दूसरा मेरा विषय एस.पी.ओ. का है। पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने आर्शीवाद दिया था। 18-20 वर्ष तक काम करने के बाद ये बजट में शामिल हुए थे। इस बार भी उन्हें बहुत उम्मीद थी कि हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरह से आशा वर्कर्ज, आंकनबाड़ी, लम्बरदार और चौकीदार को मिला है वैसे उन्हें भी राहत मिलेगी। यह एक विषय छूटा है इसलिए मेरा आग्रह रहेगा जब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे तो उन्हें भी राहत प्रदान करेंगे।

नई मंजिल नई राहें इसमें बहुत सारे स्कोप निकलें हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं। चंबा जिला क्योंकि हमारी ही सरकार ने aspirational district घोषित किया है। हम पिछड़े थे कोई इस बारे में चर्चा नहीं करता था। लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी की पहली सरकार थी और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से हम aspirational district घोषित हुए हैं। इसमें हमने प्रयास किया है कि उचित फंड के स्वास्थ्य और शिक्षा में हम लोग दो पैरामीट्र्ज में पीछे थे। लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि अगर हमें भारत माला में नेशनल हाई-वे मिल जाता है। पठानकोट-चम्बा और तीसा-पांगी और वहां से लेह के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि हम वाया मण्डी-मनाली से जाएं तो वह 947 किलोमीटर का बनता है और वहां से 442 किलोमीटर है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी से

12.03.2020/1305/बी.एस./डी.सी./-3

भी इस विषय में मिल चुका हूं और उन्होंने कहा था कि हमें एक कैबिनेट का नोट चाहिए हम इसको अपियर करवा देंगे। इस संबंध में मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष निवेदन

रहेगा क्योंकि यह छूट गया था। यदि आप इस कार्य को कर देते हैं तो जो चम्बा पिछड़ा हुआ जिला रोज भाषणों में बताया जाता है और हर सरकार हमें उलाहना देती हैं उससे राहत मिल जाएगी। मैडम आशा जी कह रही थी कि aspirational में कुछ नहीं हुआ है। जिन नेताओं और जिन सरकारों ने चम्बा के लिए कुछ किया है उनका धन्यवाद है लेकिन ज्यादातर लोगों ने चम्बा को छोड़ा है या उसे बिसारा है। इसलिए मैं किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहता। यदि करने पर आ जाएं तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आएंगी। इतना समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो समय दिया है उसमें मैं दो विषय पर अवश्य चर्चा करूंगा। एक तो एस.पी.ओ. वाला विषय बहुत गंभीर है दूसरा स्कूलों में जो अध्यापक ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि तथाकथित वे लोग हम से ही नोट-वोट ले करके वे पीछे ही रह जाते हैं। अगर rationalization की जानी है तो उसे भी किया जाए।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

**12.03.2020/1310/DT/HK-1**

**उपाध्यक्ष क्रमागत**

और कैसे भी हो उन स्कूलों के पद भरें जायें। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय श्रीमती आशा कुमारी जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए तीन-तीन कॉलेज तो ले ही लिये थे लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 किलो मीटर के दायरे में एक ही कॉलेज है। अगर माननीय मुख्य मन्त्री हमें अपना आशीर्वाद दें और निकट भविष्य में मशरूंड नामक स्थान में में या कहीं बीच में एक कॉलेज मिल जाये तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की बड़ी मेहरबानी होगी। पूर्व सरकार में मेरे जो डिवीजन गये थे, मैं यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी के साथ-साथ माननीय जल शक्ति मन्त्री महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने हमें जल शक्ति का एक नया डिवीजन दिया। मैं माननीय जल शक्ति मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे दो

डिवीजन और गये थे अगर आप उन्हें भी हमें दे देते तो हम आपके धन्यवादी रहेंगे क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल-स्पिति के बाद मेरा ही चुनाव क्षेत्र है और अगर ये दो डिवीजन आ जायें तो इससे मेरा डिवीजन पूरा हो जायेगा। एक पी.डब्ल्यू.डी. का डिविजन पूर्व सरकार में हमे मिल गया था लेकिन उस डिविजन को हम लोगों ने ही स्ट्रेन्थन किया था। यह डिविजन तब बना था जब मैं विधायक बना। इस डिविजन को भी चम्बा या सलूणी ले जाया जा रहा था। मैडम पावरफुल रही है यह कभी ले जा सकती हैं। एक फोरेस्ट डिविजन चुराह के नाम से है जो सलूणी में चल रहा है उस डिविजन को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वापिस दिया जाए। एक तीसा में एक एक्सचेंज थी उस एक्सचेंज को भी श्रीमती आशा कुमारी मैडम सुरगाणी लेकर गए हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र में काफी जगह है वह एक्सचेंज मुझे वापिस दी जाये, यह मेरा आग्रह है। जो कांग्रेस के समय मेरे चुनाव क्षेत्र से डिवीजन चले गये थे वो तो हमनें वापिस ले लिये हैं। क्योंकि कांग्रेस की सत्ता ज्यादा समय रही है इसलिए दोष तो कांग्रेस का ही है। एक बार तो मेरे चुनाव क्षेत्र का एस0डी0एम0 आफिस भी वहां से हटाया जा रहा था। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय आपका अपार स्नेह हमें मिला है हैली टेक्सि सेवा इस बार चम्बा जिले को भी मिलेगी, ऐसा आपने बजट में प्रावधान किया है, आपने एक तरह से चंबा वासियों पर एहसान किया है। मैं

12.03.2020/1310/DT/HK-2

माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि नई मंजिल, नई राहें जो योजना है इसमें चंबा जिले में पर्यटन के क्षेत्र में काफी स्कोप है चाहे वह हमारा भरमौर का क्षेत्र हो कुकति से लेकर पांगी का क्षेत्र हो, चाहे भटियात का क्षेत्र हो, चाहे वह जोत का क्षेत्र हो। जम्मू कश्मीर वाले पदरी में एनक्रोचमेन्ट कर रहें हैं मैं हर बार यह बात कहता हूं। उन्होंने पर्यटन के हिसाब से वहां पर हट्स बना लिये हैं। वहां अपना सब कुछ स्थापित कर लिया परन्तु हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि नैशनल हाइवे हमारी तरफ से भी चला गया है। मुझे पर्यटन का एक बड़ा

स्कोप वहां नजर आता है उसे विकसित करना चाहिए। हमारा डलहौजी या खजियार तो पर्यटन स्थल हैं ही उसके साथ-साथ चंबा में साहो और कुछ स्थान है जहां पर पर्यटन की आपार सम्भावानाऐं हैं। पर्यटन की दृष्टि से चम्बा ज़िले में जो क्षेत्र उभर के आया है वह साचपास का इलाका और पांगी का इलाका। साजपास में हर साल 35 से 40 हज़ार गाड़ियां विजिट कर रहीं हैं जबकि वहां पर रोड के अतिरिक्त कोई और सुविधा हम वहां आने वाले लोगों को नहीं दे पा रहें हैं। तो मैं पर्यटन विभाग से और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग की ओर से कोई ऐसा भवन या कोई होटल जो हम वहां हम स्थापित कर सकें हमें करना चाहिए। क्योंकि रोड को तो हम चौड़ा कर ही रहें हैं। जो हमें स्टेट हाईवे का दर्जा मिला भी था पिछली सरकार ने अपनों को ठेके देने के चक्करों में उसे डी-नोटिफाई कर कर उसे लोकल रोड बना दिया। अब हमने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से आग्रह किया है कि यह रोड अब नैशनल हाईवे में यह एपियर हो जाये तो हम माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के आभारी रहेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय आपके आशीर्वाद से हमें 100 बेडिड चिकित्सालय मिला है और सभी पी0एच0सीज़ में डाक्टर भी हैं। इसके लिए भी माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी का विशेष आभार है की आपके टाइम में यह 100 बेडिड हुआ। इस चिकित्सालय में डाक्टरज़ तो आ गये हैं पर स्पैलिस्ट नहीं हैं और एस0आर0एल0 की व्यवस्था जो हो रही है वह हो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज सुबह लगा हुआ था पेट-स्केन के विषय में, मैंने तो यह खुद भुगता है और जो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने डिटेल दी है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। पहले

12.03.2020/1310/DT/HK-3

मुझे मेडिकल भाषा का पता नहीं था अब थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगी है, क्योंकि जब अपने पर बीतती है तो व्यक्ति को पता चलता है कि पेट-स्केन क्या होता है और केन्सर

क्या होता है। मैं तो स्वयं आई0जी0एम0सी0 और पी0जी0आई0 के चक्कर लगाता रहा हूं, अतः मेरा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि अगर आप पेट स्केम की व्यवस्था कर सकते हैं तो करनी चाहिए। यह जो फिगर सुबह दी गई है और जो मैंने डाक्टरज़ से कर्न्सन की थी, लगभग 7,500 नये पेशेन्ट हर साल अपीयर हो रहें हैं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

**12-03-2020/1315/एच.के.-एन.जी./1**

**उपाध्यक्ष जारी.....**

हमें हर रोज़ 8 से 10 आदमी पैट स्कैन के लिए पी.जी.आई. रेकमेंड करने पड़ते हैं, यह आंकड़ा मैंने वहां के डाक्टरों से लिया है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है क्योंकि इसके बारे में हमें अरली एज में पता नहीं चलता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उसके लिए मैं चाहूंगा कि उसे हम जितना जल्दी पूरा कर सके उतना अच्छा होगा ताकि इस बीमारी के बारे में हमें अरली एज में पता लग जाए। माननीय सदस्य श्री बुटेल जी ने ठीक कहा कि टाटा मेमोरियल यदि पी.जी.आई. में लैब खोल रहा है तो हमें भी उनसे निवेदन करना चाहिए कि हमारे यहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था हो सके। यह बहुत हाईटेक काम होता है और टाटा मेमोरियाल का ब्रेकी में बहुत एडवांस काम है। मेरा आप से इतना ही निवेदन है और मुझे इतना ही कहना था। वैसे तो सभी माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे लेकिन मेरा निवदेन केवल इतना ही है कि चुराह और चम्बा बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी माननीय मंत्रियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता सम्भाली है तब से हमने एक नए चुराह को बनते हुए देखा है। चुराह में 18-18 करोड़ रुपये तो केवल बस अड्डे को मिल रहा है। मैंने यह अनुभव किया है कि हमें यदि इस तरह के मुख्य मंत्री पहले मिलते जैसे मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी हैं तो चुराह में विकास की कोई कमी न होती। श्री जय राम ठाकुर जी पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले मेरी विधान सभा में विज़िट किया,

इससे पहले तो कोई विज़िट भी नहीं करता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही उत्कृष्ट और उत्तम बजट माननीय सदन में रखा है। मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**अध्यक्षः** इससे पहले की मैं दोपहर की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए 02.15 तक स्थगित करूं मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सभी सामुहिक चित्र के लिए अभी तुरन्त गेट नम्बर-1 पर उपस्थित होने की कृपा करें। धन्यवाद। अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 02.15 बजे तक स्थगित की जाती है।

**12/03/2020/1425/MS/YK/1**

**(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.25 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)**

**अध्यक्षः** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी भाग लेंगे।
**श्री राम लाल ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में जो 6 मार्च को आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने बजट प्रस्तुत किया है..,
**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि वे अपने भाषण को 15 मिनट की समयावधि में अवश्य ही समाप्त कर दें। अभी बोलने वाले 17 सदस्य बाकी हैं। मुझे किसी को भी घण्टी न बजानी पड़ी, यह मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है।
**श्री राम लाल ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, आप बुरा न मानें, मैं एक बात कहना चाहता हूं।
**अध्यक्षः** बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है।
**श्री राम लाल ठाकुरः** अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि कई बार तो आप 30-30 मिनट तक घण्टी नहीं बजाते। हमारे साथ पिछली बार भी ऐसा ही किया। आप पहले ही हुक्मनामा जारी कर देते हैं कि 15 मिनट से ज्यादा आप नहीं बोल सकते हैं। यहां पर कई लोग आधे-आधे घण्टे तक भाषण देते रहे लेकिन उनको आपने कुछ नहीं कहा।
**अध्यक्षः** वास्तव में आज बोलने वालों की सूची काफी लम्बी है और इस सूची को आज ही पूरा करना है।

**श्री राम लाल ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, आपको सबको बराबर देखकर चलना पड़ेगा। जो मुख्य मंत्री जी ने 6 मार्च को बजट प्रस्तुत किया और उसको समराइज करके जो भाषण इन्होंने इस माननीय सदन में दिया है, मैं उसके ऊपर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी का भाषण "जनमंच" से शुरू हुआ और वहां से शुरू होते-होते इन्वैस्टर्ज मीट तक गया। उसके आगे जुड़ा कि
जारी जे0के0 द्वारा-----

**12.03.2020/1430/JK/YK/1**

**श्री राम लाल ठाकुरः**-----**जारी**-------

हमने आर्थिक प्रबन्ध कुशलतापूर्वक किया। उसके बारे में आगे बजट की आधारशीला इन्होंने रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अगर मान लो यह कहा जाए कि कुशल प्रबंधन आर्थिक ढांचे का है तो साथ में उन्होंने पेज नम्बर-7 के ऊपर अपने ही भाषण में कहा कि वर्ष 2020-21 में नई योजनाओं के लिए लोन एग्रीमैंट केन्द्र सरकार से हस्ताक्षरित किए जाएंगे। नई योजनाओं को लागू करने के लिए फॉरेन फंडिंग होगी, केन्द्र सरकार से लोन का सहारा लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या इस सारे को आप कुशल प्रबंधन की परिभाषा में लेकर आएंगे? मैं तो कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा न करके लोगों को सब्जबाग दिखा करके प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल का बजट देख लीजिए। इस साल के बजट को भी उठाएं और सारी जितनी भी स्कीमें हैं, उनका नामकरण तो हो गया। श्री महेन्द्र सिंह जी ने भी अपने अच्छे-अच्छे शब्दों में अपने डिपार्टमैंट के नामकरण में बड़े अच्छे-अच्छे शब्द डाल दिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में अगले साल के लिए देने हैं, उनके भी नामकरण करने का सहारा ले कर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। ये जो सारी बातें हो रही हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर आपका धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने स्वर्ण

जयंती इस साल मनाने का फैसला किया। प्रदेश को 50 साल हो गए, पूर्ण राज्य का दर्ज़ा हमारे हिमाचल प्रदेश को मिला। श्रीमती आशा कुमारी जी ने यहां पर विस्तार से बताया कि प्रदेश आगे कैसे अपने स्वरूप में आया, कुछ तारीखें इन्होंने ऐसी बताई कि हिमाचल प्रदेश में वे भी लोग थे जो मौजूदा स्वरूप में हिमाचल प्रदेश को नहीं देखना चाहते थे। वे लोग भी यहीं पर थे जब पूर्ण राज्य की बात होती थी, तब वे इसका विरोध करते थे। वे भी लोग यहां पर थे जिन्होंने पूर्ण राज्य तो क्या, उन्होंने तो यह कहा था कि हमें पंजाब में मिला दिया जाए, जब कांग्रेस पार्टी इसके लिए जद्दोजहद कर रही थी। आज हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1970 में पार्लियामैंट में यह बिल पास हुआ। 25 जनवरी, 1971 को श्रीमती इन्दिरा गांधी जी शिमला के रिज पर आईं और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का

**12.03.2020/1430/JK/YK/2**

दर्ज़ा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, दर्ज़ा ही नहीं दिया, हिमाचल प्रदेश को विशेष केटेगरी स्टेट में भी शामिल किया, जिसमें 90 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड केन्द्र सरकार की और 10 प्रतिशत भी प्रदेश की सरकारों ने नहीं दी, ये जो 10 प्रतिशत था यह सॉफ्ट लोन के तौर पर आया, मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मुख्य मंत्री रहें, जितनी भी सरकारें बनीं, उन्होंने वह 10 प्रतिशत भी नहीं दिया। हुआ यह कि हिमाचल प्रदेश को 100 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड श्रीमती इन्दिरा गांधी की घोषणा के बाद जब हिमाचल प्रदेश का स्वरूप बना, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों और हिमाचल प्रदेश की सरकार के माध्यम से चहुंमुखी विकास के लिए कदम उठाए गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पर शिक्षा विभाग के ऊपर आना चाहूंगा क्योंकि आपने 15 मिनट का समय दिया है। मैं 15 मिनट में ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा यदि 2-3 मिनट की मेहरबानी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी घंटी न बजे। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आने वाले साल के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो साथी हैं, पिछले जितने भी सैशन आए हों मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे मित्र अगली पंक्ति में भी हैं और

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

**12.03.2020/1435/SS-AG/1**

**श्री राम लाल ठाकुर क्रमागत :**

कुछ और पीछे भी हैं जो यह कहते थे कि वीरभद्र सिंह जी ने स्कूल खोल दिये लेकिन वहां पर अध्यापक नहीं लगाए। कइयों ने बोला कि स्कूल्ज़ की बिल्डिंग्ज नहीं बनीं। अध्यक्ष महोदय, जब स्कूल खुलते हैं तो बिल्डिंग्ज भी बनती हैं। जब स्कूल नोटिफाई होते हैं तो वहां पर स्टाफ की तैनाती भी होती है। जिन लोगों ने उस समय शिक्षा संस्थानों को खोलने का विरोध किया, जिन्होंने कहा कि बिना ज़रूरत के संस्थान खोल दिए और रोड़ियों के भाव से कॉलेज खोल दिये लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज खुशी इस बात की है कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी के अभिभाषण में यह बात है कि पूरे हिन्दुस्तान में कई बार शिक्षा विभाग को पुरस्कृत किया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तब पुरस्कृत हुआ जब हमने शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। जब हमने प्राईमरी एजुकेशन को अनिवार्य करने के लिए कदम उठाए। जब हिमाचल प्रदेश में 10+2 के सीनियर सकैंडरी स्कूल खुले। जब प्राईमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक सारा ढांचा तैयार हुआ तो उसका परिणाम यह निकला कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना। शिक्षा के क्षेत्र में कभी हम केरल से आगे होते थे और कभी केरल हमसे आगे होता था। यह लुका-छिपी हिमाचल प्रदेश और केरल के बीच में चली। लेकिन आज खुशी है कि जब हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है ...(व्यवधान) तो शिक्षा विभाग के मंत्री यहां नहीं हैं लेकिन उन्होंने यहां पर अलग से कार्यक्रम चलाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ये सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुईं।

उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का विस्तार हुआ। उस समय मुझे याद है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि मेरे बाद जो हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री

बने, उन्होंने माननीय सदन में और बाहर भी कहा कि राम लाल ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग में इतने यूनिट खोल दिये कि मुझे स्टाफ के मेम्बर्ज़ को पूरा करना, डॉक्टर्ज़ और पैरा-मेडिकल स्टाफ को लगाना मुश्किल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह काम करने की हिम्मत होती है। आयुर्वेदा विभाग भी आगे बढ़ा। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ा है आज उसका परिणाम यह है

**12.03.2020/1435/SS-AG/2**

कि पूरे हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले या दूसरे नम्बर पर हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके पास स्वास्थ्य विभाग रहा और आज आप माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कारण क्या है कि जो हिमकेयर योजना है हमने कई बार पूछा कि हिमकेयर योजना में कितनी दवाइयां खरीदी गईं, कितने लोगों को इसका फायदा हुआ, कितनी इसके ऊपर इंवैस्टमैंट हुई लेकिन सरकार उसका उत्तर सीधे तौर पर नहीं दे रही है। आज भी हमारा प्रश्न था, ध्वाला जी भी उसमें शामिल थे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसकी सूचना एकत्रित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सारे ऑफिसिज़ यहीं पर हैं। कितनी मशीनरी खरीदी गई, वह आपके हैड ऑफिस में है, कितनी दवाइयां खरीदी गईं, वह हैड ऑफिस, सैक्रेटरी ऑफिस और नीचे डायरेक्टर ऑफिस में सबको मालूम है कि कितनी दवाइयां कहां पर गईं। जैनेरिक दवाइयां कितनी चली गईं, कितने सैम्पल फेल हो गए, सब पता है। यहां मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि अभी तो सूचना एकत्रित हो रही है। सबको मालूम है। यहां तक कि जितनी भी अखबारें हैं चाहे वह अमर उजाला, पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल और दूसरी अखबारें हैं उन्होंने चार-चार कॉलम की न्यूजें छापीं कि क्या गड़बड़ स्वास्थ्य विभाग में हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठे थे। मैंने जब यह मसला उठाया तो आपने कहा कि the paper may be laid on the Table of the House. मैंने वे संबंधित पेपर यहां रखे। यहां पर जाली दवाइयां बनीं, यहां पर मरीज मर गए और मैंने वे पेपर सभापटल पर रखे। मैं आज माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो पेपर मैंने ले किये हैं उसका आगे क्या किया? उस समय के माननीय स्वास्थ्य मंत्री

जी ने मुझे कहा था कि पेपर ले कर दिये जाएं, मैं आज इस माननीय सदन में पूछना चाहूंगा कि जो मैंने पेपर ले किये थे और जो दवाइयां सब-स्टैंडर्ड खरीदी गई थीं जिनसे मरीज मर गए थे, मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने जो पेपर ले किये थे उसका आगे क्या किया? कहीं वे रद्दी की टोकरी में तो नहीं डाल दिये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं

जारी श्रीमती के0एस0

**12.03.2020/1440/केएस/एजी/1**

**श्री राम लाल ठाकुर जारी**---

मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि यहां पर चार कम्पनियां हैं, जिनकी सब-स्टैंडर्ड दवाइयां हैं, विभाग ही बोल रहा है, उनके सैम्पल फेल हो गए। उसके बारे में क्या हो रहा है? जितनी भी हमारी जैनरिक दवाइयां सब-स्टैंडर्ड निकलीं, उनके भी सैम्पल फेल हुए, उसके बारे में भी सरकार कुछ नहीं बता रही है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कृपा करके जो आप कहते हैं, और जो करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। यहां पर मंत्री भी कह देंगे, डिपार्टमैंट के लोग भी कह देंगे और साथ में मुख्य मंत्री जी ने भी अपना अभिभाषण दे दिया, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो हमने पिछले साल के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा किए, विद डॉक्युमेंट्री प्रूफ जो हमने इस माननीय सदन में ले किए, इस सरकार ने उसमें क्या किया?

अध्यक्ष महोदय, बजट बुक के पेज नं0 72 में लिखा है कि हमारी पंचायतें जिनमें सड़कें नहीं बनी हैं, उनकी संख्या 39 है और यह कहा कि इन पंचायतों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वहीं इसके पेज नं0 73 पर लिखा है कि जो 90 गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं, वे भी इस साल सड़क से जुड़ जाएंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह आंकड़ा 39 का सही है या 90 का सही है?

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया आप बैठें। मुख्य मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न का उत्तर समय पर नहीं पहुंच पाता है, उसका उत्तर बाद में देने की परम्परा आज से नहीं, वर्षों से है। उस दृष्टि से सूचना एकत्रित की जाएगी। इनका प्रश्न यह है कि गत तीन वर्षों में दिनांक 31.01.2020 तक किस-किस फर्म से कितनी-कितनी धनराशि की दवाइयां तथा उपकरण खरीदे गए? ब्यौरा खरीद की तिथि तथा फर्म के नाम और पते सहित दें, यह प्रश्न है। स्वभाविक रूप से यह लम्बी सूचना है, इसमें समय लगेगा। "हिम केयर योजना" के बारे में हमने तो बहुत विस्तार से कहा है, एक्चुअल फीगर्ज़ इस वक्त हमारे पास नहीं हैं लेकिन लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों का

**12.03.2020/1440/केएस/एजी/2**

"हिम केयर योजना" के अंतर्गत इलाज हुआ और 62 या 65 करोड़ रुपये के लगभग इस पर खर्च कर लिया है। इसमें छिपाने वाली बात क्या है? जो काम किया है, वह किया है । इनके प्रश्न का "ख" भाग है कि क्या यह सत्य है कि सरकारी अस्पतालों में लोकल कम्पनियों की दवाइयों की खरीद पर रोक लगाई गई है? "ग्" पार्ट यह है कि क्या यह सत्य है कि जो दवाइयां सरकार द्वारा रोगियों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उनके सैम्पल फेल हुए हैं? यदि हां, तो कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, इसका ब्यौरा दें। "घ"पार्ट में पूछा है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के लिए क्या नीति निर्धारित है? इसमें नीति भी पूछी गई है तो बहुत विस्तृत था और इस बार अगर इसका उत्तर नहीं आया तो अगली बार पोस्टपोंड क्वैश्चन के रूप में आ जाएगा और हम उसका उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि छिपाने का न हमारी सरकार का और न हमारा कोई मकसद है।

**श्री राम लाल ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी-जल्दी में दो-तीन बातें मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि जो अभी आशा जी ने कहा, कि जो इलिगल माइनिंग है, क्या कारण है कि आपकी माइनिंग की इनकम कम हुई है? इसके

लिए इन्होंने कहा कि क्योंकि आपका जो एम फार्म है, वह 9 टन के ऊपर है लेकिन 100-100 टन रेत और बजरी उनमें जा रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप सोर्सिज़ की बात कर रहे हैं, जो हमने यह दो साल में छोड़ा, पहले मुकेश जी जब उद्योग मंत्री थे, शायद उस वक्त भी यह 9 टन का ही था लेकिन मैं आज सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें सोच कर आगे कदम नहीं बढ़ाने चाहिए कि अगर आपकी माइनिंग से इन्कम कम हो रही है तो माइनिंग से इन्कम कैसे बढ़े,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**12.03.2020/1445/av-as/1**

**श्री राम लाल ठाकुर-------- जारी**

उसके लिए यहां पर जो आशा जी ने कहा हमें उस पर अमल करना चाहिए। अभी यहां पर मंत्री जी नहीं बैठे हैं इसलिए मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे बिलासपुर जिला में एक भी माईन नहीं है। वहां पर लोग मकान बना रहे हैं, आपकी सड़कें बन रही हैं तथा सरकारी बिल्डिंग्ज भी बन रही हैं। अगर प्राइवेट लोगों ने पत्थर, रोड़ी-रेता लेना है तो आप हमें यह बताएं कि वे लोग बिल्डिंग मैटीरियल कहां से लेंगे? मान लो, अगर कोई सड़क किनारे से लाइम स्टोन की रोड़ी उठाता है तो उसके लिए उद्योग विभाग का माईनिंग विंग 25,000-25,000 रुपये का चालान करता है। मेरा निवेदन यह है कि जिला बिलासपुर में विभाग की एक भी माईन नहीं है इसलिए वहां के लोगों को भी इसका फायदा होना चाहिए।

यहां पर कोल्ड स्टोरेज की बात भी हुई। मगर मैं तो यह कहूंगा कि हमारे हिन्दुस्तान में कोल्ड स्टोरेज तो अदानी ग्रुप के ही रह गये। इसलिए सरकार को इस पर काफी काम करना होगा। टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के अंतर्गत मैं यह कहना चाहूंगा कि कसौली जैसे एरिया में कहीं पर चार स्टोरीज बिल्डिंग बन रही है तो कहीं पर एन0जी0टी0 केवल अढ़ाई

मंजिल अलाउ कर रही है। जब वहां पर चार मंजिला बिल्डिंग्ज बन रही हैं तो आप दूसरों को अढ़ाई मंजिल पर क्यों रोक रहे हैं? लोगों को कहीं-न-कहीं तो लगना चाहिए कि हमारे साथ न्याय हो रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं फिशरीज डिपार्टमैंट की बात करना चाहूंगा। आज प्रदेश में खड्डों के किनारे लगभग 13,000 मछुआरे काम कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रदेश के कोल्ड एरिया में ट्राउट मछली का उत्पादन हो रहा है। साथ में, आपने यहां पर केज फार्मिंग की बात की है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जहां से केज फार्मिंग सिस्टम आया वहीं पर वह फेल हो गया और हम अपने हिमाचल प्रदेश में केज फार्मिंग की बात कर रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने यह कर दिया है कि मान लो, आपने टैंडर फ्लोट कर दिए और जो कंपनी आयेगी वहां पर बीज डालने का काम भी वही करेगी तथा वह काम स्थानीय लोग नहीं करेंगे। उसमें यह

**12.03.2020/1445/av-as/2**

कहा गया है कि उसमें कम-से-कम इतनी टर्न ओवर होनी चाहिए उसमें स्थानीय लोग तभी हिस्सा ले पायेंगे। इस तरह से तो हिमाचल प्रदेश का एक भी व्यक्ति या मछुआरा उसमें शामिल नहीं हो पायेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ओर भी ध्यान दें। मेरा एक और अनुरोध रहेगा कि मुख्य मंत्री नाम से एक सड़क योजना मरम्मत के लिए है। वैसे तो हर जगह ऐसी ही स्थिति है, मेरे वहां पर अगर सड़क के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि नहीं दी गई तो वह पैसा सरेंडर हो जायेगा। क्योंकि मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो मरम्मत का पैसा गया है वह आज की तारीख में डी0सी0 के स्तर पर बांटा नहीं गया है। अगर वह पैसा इस महीने नहीं दिया जायेगा तो वह सारा-का-सारा सरेंडर हो जायेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार का काम कहने के लिए कुछ और है तथा करने के लिए कुछ और है। यहां पर यह भी कहा गया है कि धौलरा मंदिर के लिए भी पैसा आयेगा। उस मंदिर के लिए ट्रस्ट बना था परंतु बाद में यह कहा गया कि इसको पंडित ही चलायेगा। अब वहां पर कुछ पैसा तो बी0बी0एम0बी0 से आ रहा है तथा कुछ पैसा केंद्र

सरकार दे रही है। वहां पर जो ट्रस्ट बना था; उसको आपने प्राइवेट आदमी को दे दिया। फिर यह भी कहा गया है कि वहां पर केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग का पैसा भी खर्चा जाए; तो क्या आपने वहां पर बैठे हुए पुजारी की सेवा करने के लिए यह सारा काम किया है। मेरा निवेदन यह है कि हम सारी चीजों को देखें। वहां पर जो सड़कें व पुल हैं क्योंकि हमारे बबखाल के पुल का कार्य आज भी पैसा न मिलने के कारण रुका पड़ा है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इन सारी बातों की तरफ ध्यान दें। ऐसा न हो कि हम अपने-अपने चक्र में फंसे रहें और जहां पर सचमुच में पैसा जाना चाहिए; वहां न दें। मान लो, यदि सड़क या पेयजल स्कीम के लिए पैसा आ भी जाए तो उसे केवल किसी-किसी निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित कर दिया जाए; यह ठीक नहीं रहेगा। अतः आपको पूरे हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखना चाहिए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सुख राम टी सी द्वारा जारी**

**12.03.2020/1450/TCV/AS-1**

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री सुख राम इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री सुख राम(पावंटा साहिब) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने 6 मार्च, 2020 को वर्ष 2020-21 का जो बजट अनुमान यहां सदन में प्रस्तुत किया, मैं उसके ऊपर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, यह किसानों, मजदूरों, महिलाओं, कर्मचारियों, बागवान इत्यादि सभी वर्गों का हितैषी बजट है। इस बजट में माननीय विधायकों का भी ध्यान रखा गया है। नाबार्ड की स्कीमों का बजट 105 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये किया गया है, 'विधायक निधि' को 1.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये और विधायकों की विवेक अनुदान राशि जो प्रत्येक विधायक को 8,00,000/- रुपये मिलती थी उसको बढ़ाकर 10,00,000/- रुपये किया गया है। इन 2 वर्षों में मुख्य मंत्री जी ने दैनिक भोगी कर्मचारियों की दिहाड़ी 65 रुपये बढ़ाई है और यह दिहाड़ी 210 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये की है। पिछले सरकार के समय में यह

दिहाड़ी 5 सालों में केवलमात्र 40 रुपये बढ़ी थी। पूर्व सरकार के समय में यह 170 रुपये से शुरू हुई थी और 210 रुपये में जाकर ख़त्म हो गई थी। वर्तमान सरकार को बने हुए अभी 2 वर्ष हुए हैं, उसमें मज़दूरों की दिहाड़ी इस वर्ष 250 से 275 रुपये की गई है और इसमें 25 रुपये की बढ़ौतरी हुई है। ये बहुत सराहनीय कदम मुख्य मंत्री जी द्वारा मज़दूरों के हित में लिया गया है। सिलाई अध्यापकों का मानदेय 500 रुपये और आई.टी., शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई। इसी तरह से आशा व़र्कर्ज का मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया,जलगार्ड, पैरा टीचर्ज़, पम्पों ऑपरेटर्ज़ का 300 रुपये प्रति महीना, 22000 कर्मचारी जो शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में हैं, उनका ग्रेड-पे 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत किया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्ज का मानदेय 500 रुपये, आंगनबाड़ी सहायक-300 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी व़र्कर्ज-300 रुपये और अंश कालीन कर्मचारियों-300 रुपये, लम्बरदारों-500 रुपये और मिड-डे मील व़र्कर्ज़ का मानदेय 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया है। इस तरह से मुख्य मंत्री जी ने गरीब वर्ग के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी का पूरे प्रदेश में आम कर्मचारी वर्ग धन्यवाद कर रहा है। इस समय हिमाचल प्रदेश में हज़ारों-लाखों पद खाली पड़े हैं क्योंकि पूर्व सरकार के कार्यकाल में 5 साल में जे0बी0टी0 के करीब 6000 पद भरे गये। मैं

**12.03.2020/1450/TCV/AS-2**

आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं, पिछले 2 सालों में 6500 से अधिक पद एलिमैंटरी एजुकेशन में भरे गये। इस वर्ष 20000 पद फंक्शनल पोस्टों के भरे जाने हैं जिनका मुख्य मंत्री जी ने बजट में ज़िक्र किया है। शिक्षा विभाग में 6000, बिजली बोर्ड में तकनीकी कर्मचारी 3000, एच0आर0टी0सी0 में 1300 पद भरे जाने हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग व पुलिस विभाग सहित कुल 20000 पद इस साल भरे जाएंगे। इससे भी बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। हमारे विपक्ष के मित्र कहते हैं कि बेरोज़गारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं लाए। केन्द्र में जब परम श्रेद्धय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज़ 10 साल के लिए 2003 से 2013 तक दिया गया था। आप तो बेरोज़गारों का रोज़गार

लेने वाली सरकार है यानी ख़त्म करने वाली सरकार के रूप में जाने जाते हैं। केन्द्र में आपकी सरकार थी, हमारा पैकेज़ जो 2003 से 2013 तक था, उस समय की यू0पी0ए0 की सरकार ने उस पैकेज़ की अवधि को कम करके 7 साल कर दिया था।

**श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी**

12.03.2020/1455/RKS/DC-1

श्री सुख राम ... जारी

हिमाचल प्रदेश में जितने उद्योग उस समय आने थे वे उद्योग आने बंद हो गए। तीन साल में वह पैकेज कम हो गया। उस समय केंद्र में आपकी सरकार थी लेकिन वह पैकेज आप नहीं ला सके। आप बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं कर सके। उस समय हजारों उद्योग हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित होने थे परंतु वे उद्योग स्थापित नहीं हो सके। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो इंवैस्टर मीट का आयोजन किया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां पर हजारों इन्वैस्टर्ज आएंगे और हजारों औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेंगे। इन इकाइयों के स्थापित होने से हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 'कृषि सिंचाई योजना' के तहत 338 करोड़ रुपये की स्कीमें चल रही हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 111 स्कीमों के लिए 202 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस बजट में 87.35 करोड़ रुपये की 4 बड़ी परियोजनाएं भी केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं। जिन 42 प्रतिशत लोगों के घरों में पानी के कनैक्शन्ज नहीं हैं उनको वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत पानी के कनैक्शन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन में 2900 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं और मुझे आशा है कि हम वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को पूर्ण कर लेंगे। इस वर्ष इस योजना के तहत 1 लाख घरों को पानी के कनैक्शन्ज दिए जाएंगे। यह

एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने जो हर घर में मुफ्त पानी का कनैक्शन देने का निर्णय लिया है, यह बहुत सराहनीय कदम है। इस बजट में 'प्रवाह धारा योजना' के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत जो ढलानदार खेत हैं, उनमें जल स्त्रोतों को रिवाइव करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। ये योजनाएं नाबार्ड और अन्य मदों में स्वीकृत होंगी जिससे कृषि क्षेत्र काफी मजबूत होगा। 'मुख्य मंत्री गृहिणी सुविधा योजना' के अंतर्गत प्रदेश में 2,74,000 महिलाओं को फ्री में गैस कनैक्शन्ज वितरित किए गए। मुख्य मंत्री ने इस वर्ष के बजट में यह

12.03.2020/1455/RKS/DC-2

कहा है कि कोई भी पात्र इस सुविधा से वंचित रह गया है तो उसे 'मुख्य मंत्री गृहिणी सुविधा योजना' के तहत गैस कनैक्शन दिया जाएगा। इस योजना से हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ हुआ है। पैंशन के लिए 80 वर्ष की आयु को घटाकर 70 वर्ष किया गया है जिससे 1,50,000 लोगों को 1500 रुपये के हिसाब से पिछले एक वर्ष में पैंशन मिली है। इस वर्ष विधवा पैंशन की राशि 850 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दी गई है और जो 50,000 पैंडिंग केसे पड़े हुए हैं उनके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किया है। बुजुर्ग, विधवाओं और गरीब व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े उसके लिए क्लस्टर स्कूलों को उन्नयित करने के लिए 100 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए इस बजट में प्रोविजन किया है। इन स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन 68 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 500 या इससे अधिक होगी उन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। 'मेधा प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत दसवीं की कक्षा में सर्वाधिक अंक लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 1 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी अनुदान सहायता दी जाएगी ताकि वे विद्यार्थी आगे की शिक्षा प्राप्त कर सके। प्राइमरी स्कूलों में जलवाहकों

के स्थान पर मल्टी टास्क वर्कर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। जलवाहकों के हजारों पद खाली पड़े हैं और इन पदों के स्थान पर मल्टी टास्क वर्कर भरने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किया है। 'हिम केयर योजना' के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 68,222 लोगों को 63 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने यह बहुत बड़ा लाभ लोगों को दिया है। 'आयुष्मान भारत योजना' में लगभग 52 हजार लोगों को 53 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

12.03.2020/1500/बी.एस./डी.सी./-1

**श्री सुख राम जारी...**

और सहारा योजना, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है और बिस्तर पर पड़ जाता है उसे इलाज की जरूरत होती है। उस राशि को भी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2 हजार रुपए से बढ़ा कर 3 हजार रुपए कर दी है। विद्युत विभाग में भी रेणुका जी परियोजना, जो फस्ट स्टेज की बननी है उसमें 2021 के बजट में भारत सरकार द्वारा 6947 रुपए अनुमोदित करने की बात कही गई है। इससे न केवल यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा परंतु हिमाचल प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। रेणुका बांध परियोजना जब बनेगी और फस्ट स्टेज का पॉवर हाउस जो बनेगा और सैकिण्ड स्टेज का जो गिरी में पावर हाउस बना है उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत सारा लाभ इससे हिमाचल प्रदेश को भी होगा और जो जल विद्युत की परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनको किस तरह से समय बद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि उनका दोहन हो और हिमाचल प्रदेश की इंकम में उनका योगदान हो सके इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। इस बजट में प्रावधान है कि उसकी नीति निर्धरित की जाएगी ताकि समय बद्ध तरीके से इन 1500 मैंगावाट की परियोजनाएं जो हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं उन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर सकें और हिमाचल प्रदेश की आय में इजाफा हो।

हिमाचल प्रदेश में 3226 पंचायतों है जिसमें से 3138 पंचायतें सड़क से जुड़ी हैं और 88 में से 49 सड़कें उन पर कार्य प्रगति पर है और 39 पंचायतें ऐसी हैं जिन पर काम नहीं चल रहा है। इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि हम इन पंचायतों को भी सड़क से जोड़ेगें। इससे आगे बढ़कर 100 से 200 तक जिस गांव की जनसंख्या है उस गांव को भी मुख्य मंत्री ग्रास सड़क योजना के तहत जोड़ने का प्रावधान किया गया है और बजट में इसके लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण के रखरखाव के लिए भी 3986 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पर्यटन विभाग में भी नए हवाई अड्डे बनाने के लिए और अड्डों का विस्तार करने के लिए 1013 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों के पास घर नहीं हैं उनके लिए 12.03.2020/1500/बी.एस./डी.सी./-2इस बार 10 हजार घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है उसमें हमारी सरकार ने कहा है कि 20 हजार रुपया प्रदेश की सरकार अपनी ओर से देगी, यह भी एक बहुत सराहनीय कार्य

12.03.2020/1500/बी.एस./डी.सी./-1

हमारी सरकार ने किया है। जो भूमि हीन लोग हैं उनकी आय का जो क्राइटिरिया है पहले 50 हजार का था जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर एक लाख कर दिया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, मैं कहना चाहता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यह योजना नहीं लाते तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी 20 वर्ष तक गावों और पंचायतों को सड़कों से नहीं जोड़ सकते थे। जल जीवन मिशन, इसमें भी आदरणीय जय राम ठाकुर जी को यह शौभाग्य प्राप्त होगा और इनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश बन जाएगा जिसमें सभी घरों में पेयज की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। यह वर्ष 2022 तक पूर्ण कर ली जाएगी। (घंटी) मुख्य मंत्री गृहिणी सुविधा योजना, सहज बिजली योजना, जिनके घरों में अभी बिजली नहीं हैं उन सभी घरों को बिजली मिलगी और जिला सिरमौर में भी विकास को एक नई दिशा इन दो वर्षो में मिली है।

**(माननीय सभापति, श्री राकेश पठानिया जी पदासीन हुए)**

आई.पी.एच. का डिविजन शिलाई में खोलना, सब डिविजन सरांह में खोलना, एस.डी.एम. का कार्यालय सरांह में खोलना, लोक निर्माण विभाग का डिविजन सरांह में खोलने की घोषणा करना, आई.पी.एच. का डिविजन पांवटा में खोलना, बिजली बोर्ड का सब डिविजन पावंटा में खोलना, बस स्टैंड का निर्माण करना और चार आई.टी.आई. सिमौर में खोलना, 15 पी.एच.सीज खोलना, पावंटा के अस्पताल को 100 से 150 बिस्तरों का करना, शिलाई के अस्पताल को भी 50 से 100 बिस्तरों का दर्जा देना, राजगढ़ के अस्पताल को 50 से 100 बिस्तरों का दर्जा देना इस तरह के कदम हैं। सब तहसीलों का खोलना अपने आप में सरकार के विकास कार्यों को दर्शाता है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी..

**12.03.2020/1505/DT/HK-1**

**श्री सुख राम चौधरी क्रमागत**

बहुत सी तहसीलें और उप-तहसीले खोली गई हैं। यह बजट जो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है यह आम आदमी का बजट है। इससे प्रत्येक वर्ग को राहत मिली है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों को इन योजनाओं के माध्यम से जब फेसिलीटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और लोगों की इन्कम का क्राइटेरिया बढ़ेगा तो लोग साधन सम्पन्न होंगे। इन योजनाओं से कृषि व सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा । यह जो बजट आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय जी ने यहां प्रस्तुत किया है, यह आम आदमी का बजट है, किसानों का बजट है, गरीब आदमी का बजट है, मजदूरों का बजट है, कर्मचारियों का बजट है, बागवानों का बजट है। इसलिए इस बजट की मैं भरपूर प्रशंसा करता हूं। यह स्वागत योग्य बजट है। जय हिन्द, जय भारत, जय हिमाचल।

**सभापतिः** धन्यवाद, श्री सुख राम चौधरी जी। अब अगले सदस्य, श्री नन्द लाल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री नन्द लालः** माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट अनुमान 6 मार्च, 2020 को इस सदन में प्रस्तुत किये हैं, मैं भी उस चर्चा में शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट बुक को मैंने बड़े गौर से पड़ा है। इसमें शुरूवात में लिखा गया है कि हैल्थ, एजुकेशन, पॉवर में हिमाचल प्रदेश टॉप परफोरमिंग स्टेट में आया है। इसमें आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पूर्व की सरकारें थी उनका भी प्रदेश के विकास में एक बहुत अहम रोल रहा है। Because the Government is in continuity. इसमें भी आप अपनी पीठ थपथपायें ऐसा हमें महसूस नहीं होता। इस दस्तावेज का जो तीसरा और चौथा पैरा है, it is totally a politically agenda . इसमें उन्होंने सीर्फ इलैक्शनस की बात है। इसमें Parliament Election की बात कही गई है, इसमें उपचुनाव की बात कही गई है। बेहतर होता कि इसमें दिल्ली के विधान सभा इलैक्शन्ज की बात भी आ जाती। जनमंच का जिक्र है बजट बुक में किया गया है उस

**12.03.2020/1505/DT/HK-2**

पर भी मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत रेपिटिशन हो जाएगा। जनमंच में हम सरकार से एक प्रार्थना करना चाहेंगे the expenditure incurred on these Jan Manchs may kindly be curtailed and I know that your don't want to stop it because it is a political agenda for your Party. इसलिए इसके खर्चे में कमी लाई जाए ताकि यह पैसा कहीं और खर्च हो सके। धर्मशाला में जो अभी इन्वेस्टरस मीट हुई, उसकी काफी चर्चा हुई, यह अच्छी बात है! हम चाहते हैं कि यहां पर इन्वेस्टरस आयें लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। हमें नहीं लगता की यह मीट कामयाबी की ओर बढ़ रही है। There is nothing new in this Investors Meet यह पहले कांग्रेस की सरकारों के समय में भी हुई थीं। मगर जो खर्चा हो रहा है, कल नेता प्रतिपक्ष ने इसकी काफी डिटेल दी है, जो एक्सपैंडिचर हुआ है वह लगभग 60 करोड़ रुपये है। This is a huge amount which has incurred on this

Investors Meet. इस पर थोड़ी कटौती की जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। मैं ज्यादा डिटेल पर न जाते हुए सीधा बजट पर आता हूं। स्टेट इकॉनोमी में जो पैरा 13 है उसमें लिखते हैं कि Government has managed fiscal affairs of the State prudently. इसमें दो चीजें अहम हैं one is Centrally Sponsored Schemes and additionally securing new projects under Externally Aided Projects. These are the two things they are emphasizing. हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स पर डिपैंड करता है कि वहां से कितना पैसा आएगा। जबकि इसकी नेगोसिएशन इस वर्ष होनी है। इन दोनों मामलों में जो सरकार ने नेगोसिएशन करनी है that is going to be held this year. उसका क्या रिजल्ट निकलता है, आपको क्या मिलता है, भगवान जानें? आप सब लोग जानते हैं कि Budget is the statement of receipts and expenditures. हमारी receipts क्या है हमारा एक्सपैंडिचर क्या है, वह बजट कहलाता है कि

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी**

**12-03-2020/1510/एच.के.-एन.जी./1**

**श्री नन्द लाल जारी.....**

रिसीट्स के अंदर हमारे पास State Tax Revenue, Non-Tax Revenue, share in the Central Taxes, the Finance Commissioner Transfer, CSS Transfers and Debt है। This is all in revenue receipts, क्योंकि रेवन्यू रिसीट्स जो हैं यह हमारे टोटल पैसे का खजाना होता है जिसको हम एक्सपेंडिचर साइड में खर्च करते हैं। जैसा की मैंने कहा कि ये जो दो चीजें थी इसके अलावा इनके पास रिसीट्स में कुछ आने वाला नहीं है। Today we are in a state of fiscal deficiency situation. Fiscal deficiency situation में है क्योंकि जो टोटल रेवन्यू रिसीट्स हैं वह Rs. 47,318 . 58 crores and expenditure side receipts Rs. 49130.84 crores, so the total revenue deficit would be Rs. 6,83.98

crores or fiscal deficit would be Rs. 77,272.76 cores. So this is total mismatch. हमारी जो रिसीट्स हैं और हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं यह दोनों मिसमैच हैं।

सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि जब यह हालात हैं तो there is a shamble (state of disorder). हम अपनी जी.डी.पी. और स्टेट ग्रोथ की बात करते हैं तो we are comparing with the Centre Government. केन्द्र सरकार अपने आप shamble में हैं। मुझे नहीं लगता की हम ज्यादा कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। It is basically jugglery of figures and nothing else. 47,00/- crores, 4200/- crores. यदि हम इसे डायरेक्शन लैस बजट कहें तो इसमें कोई exaggeration नहीं है और न ही कोई अतिश्योक्ति होगी।

सभापति महोदय, सामान्यता होता क्या है कि जब बजट बनता है, जैसा मैंने कहा कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के हिसाब से, it is basically financial management. किस तरीके से हम उपलब्ध संसाधनों के अंदर एक्पेंडिचर दिखाएंगे उसके लिए यह फाइनैंशियल मैनेजमेंट है। मुझे याद है कि वर्ष 2016 में जब श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे और जब उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया था

**12-03-2020/1510/एच.के.-एन.जी./2**

तब उसमें कर्जा भी था लेकिन on the expenditure side, the way he has moved with the direction, like हमको अपनी प्राथमिकताएं फिक्स करनी है और सरकार का फोक्स किन-किन महत्वपूर्ण बातों पर है उसे ध्यान में रख कर बजट बनाया गया था। Whether it is education, health, roads उसके हिसाब से बजट का एलोकेशन किया गया था। जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेंडिचर के साथ allocation of budget किया वह इतना सफल रहा कि उन पांच सालों में विकास के बहुत कार्य हुए। सरकारों को इस प्रकार का मैनेजमेंट चाहिए होता है।

सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोशिश की है कि हर वर्ग को कुछ-न-कुछ दिया जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई बात हुई है। इसमें कुल मिलाकर if you see the price index तो बड़ा marginal enhancement है। आंगनबाड़ी वर्कर या आशा वर्कर की जो enhancement हुई है these are just nominal enhancements. इसमें भी सरकार को पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। Let me very clear on this, कर्मचारियों को जो डी.ए. दिया गया है this is known as obligatory payment. वह देना ही देना है । think rather you are late in giving it. सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. देने में और Seventh Pay Commission के एरियर देनें में आप लेट हैं। इसमें भी आपको पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। यह obligatory है और आपको करनी ही होती है। हमारे विकास में जो महत्वपूर्ण सैक्टर हैं, चाहे सड़कों की बात करो, चाहे आप पर्यटन की बात करो, चाहे आप बागवानी की बात करो, चाहे आप कृषि की बात करो, बजट में इस बार कितना enhancement हुआ। हम अच्छे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम अच्छे होर्टीकल्चर की बात करते हैं, हम अच्छे टूरिज्म की बात करते हैं see the enhancement done. पिछले और इस साल में मुझे कुछ ज्यादा इज़ाफा नज़र नहीं आता।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

**12/03/2020/1515/MS/YK/1**

**श्री नन्द लाल जारी**------

पिछले सवा दो सालों में जो कर्ज़े में बढ़ोतरी हुई, यह भी जग-जाहिर है। कल विपक्ष के नेता ने बड़ी डिटेल में कर्ज़े की बात की है, I will not repeat that. आज सुबह भी यहां यस बैंक की काफी चर्चा चली। Knowing fully well, स्टेट बैंक इसमें कुछ करेगा। इस सबके बावजूद अभी भी हम प्रिकोशन नहीं ले पा रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस पर सोच-विचार करके जल्दी एक्शन करें।

इसी तरह की हालत रिसीट साइड में है। अभी भी ए0डी0बी0 बैंक ने आपको लोन देने से इन्कार कर दिया है। आपने पहले ही 1092 करोड़ रुपये का लोन ले लिया है।

जहां तक पर्यटन की बात है उसमें हम गिनाते हैं कि हमारे यहां हर वर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। अफ़सोस की बात है कि पर्यटन में रिसीट साइड में पैसा लाने की अथाह संभावना है लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। हिमाचल के अंदर जो ऑलरैडी सैंक्शन सर्किट हैं, उस काम को पूरा नहीं किया जाता है unless you submit the Utilization Certificate (UC) there, केन्द्र सरकार को जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब तक वे सैकिण्ड इन्स्टालमैंट इशू नहीं करते हैं। क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जितने भी टूरिस्ट सर्किट हैं, इन्हें कम्पलीट करें और जो ए0डी0बी0 से सैंक्शन पैसा है, उसका सही इस्तेमाल करें ताकि हम पर्यटन में अपने आपको डवलप कर सकें। पर्यटन के लिए दूसरी जो चीजें हैं, जैसे गुड रोड कनैक्टिविटी, जहाज की सुविधा या रेल की सुविधा है, इन सारी चीजों पर कोई खास इज़ाफा नहीं है। How would you attract the tourist. आप सड़कों की हालत देखिए। शिमला में आने के लिए सड़कों का क्या हाल है। कुल्लू में जाने के लिए सड़कों का क्या हाल है। हमें एन्श्योर करना होगा कि हमारी सड़कें दुरूस्त हैं और रेलवे लाइन का अच्छा इंतजाम है। फ्लाइट्स का सबको पता ही है कि हमारे यहां क्या हो रहा है। हमारे जो तीन एयरपोर्ट्स हैं, उनमें फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं। शिमला में फ्लाइट नहीं आ रही है। We have an airport there. अध्यक्ष जी, हम यह कहना चाहेंगे कि हमें इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

**12/03/2020/1515/MS/YK/2**

एनुअल प्लान में इस बार 711 करोड़ रुपये जन-जाति उप-योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना में 88 करोड़ रुपये हमेशा की तरह डाला गया है। बड़े अफ़सोस की बात है कि जन-जाति उप-योजना में जो 711 करोड़ रुपया है, उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हमें मालूम है कि इस प्लान के पैसों को कई जगह तो सैलरी में दिया जाता है diversion of funds इसके पैसे को डायवर्ट किया जाता है। मेरा यह कहना है कि जन-जाति उप-योजना का जो पैसा है उसको नीति आयोग की गाइडलाइन्ज के हिसाब से खर्च न होने के बाद इसको हर जगह खर्च किया जाता है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा इस पैसे को उसी काम में लगाया जाए जिसके लिए यह मिला है।

जो विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधान सभा चुनाव क्षेत्र धनराशि सीमा 120 करोड़ रुपये की है यदि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाता है तो उसमें और फायदा होगा। एक सड़क की अपग्रेडेशन के लिए यदि आपको 15 करोड़ रुपये की जरूरत है तो यदि इसमें ज्यादा प्रावधान होता है तो हर चुनाव क्षेत्र में दो-तीन सड़कें उसमें कवर हो सकती थीं। यही हमें कहना है।

सभापति जी, मुझे पता है कि समय का अभाव है। मैं बागवानी के क्षेत्र की बात करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सैक्टर है। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि सी0ए0 स्टोर जिनमें सब्जियों और फलों का रख-रखाव होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल तीन जगह सी0ए0 स्टोर की कपैस्टी को अभी एन्हांस किया है लेकिन नये किसी भी सी0ए0 स्टोर का प्रावधान नहीं किया है। हमारा आग्रह रहेगा कि हमारे यहां ननखड़ी में एक जांगड़ जगह है, जहां सी0ए0 स्टोर का प्रोविजन था। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि उस पर ध्यान दिया जाए।

इसी तरह से रोड्ज के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में लिखा है कि हम सबको कनैक्टिविटी दे देंगे लेकिन अभी तक भी हमारी एक पंचायत ऐसी है जहां पर सड़क नहीं है। ..(घण्टी)

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

**12.03.2020/1520/JK/YK/1**

**श्री नंद लालः**-----**जारी**--------

वहां सी.ए. स्टोर का प्रोविजन था तो मेरा आग्रह रहेगा कि उस पर ध्यान दिया जाए।

**Chairman (Shri Rakesh Pathania):** Shri Nand Lal Ji, I request you to kindly wind-up now.

**Shri Nand Lal:** Sir, I will take just a few minutes. रोड़ज के बारे में मुख्य मंत्री जी ने अपनी बजट किताब में लिखा है कि हम सभी को कनैक्टिविटी दे देंगे लेकिन अभी तक हमारी एक पंचायत ऐसी है, जहां पर सड़क नहीं है।

**Chairman (Shri Rakesh Pathania):** Hon'ble Member, there are more than twelve speakers yet to speak.

**श्री नंद लालः** मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि उस सड़क को जल्दी-से-जल्दी बनाएं। मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया है लेकिन कई सालों से वह वायदा ही चल रहा हैं परन्तु वहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारे क्षेत्र के अन्दर बहुत सारी सड़कें हैं उनकी ओर भी सरकार ध्यान दें, ताकि वे सड़कें बन जाएं और जो आपने किताब में लिखा है, वह भी पूरा हो जाए।

**Chairman (Shri Rakesh Pathania):** Hon'ble Member, please wind-up now.

**श्री नंद लालः** सभापति महोदय, इस बजट में हमने जो भी देखा और जो हमारे समझ में बात आई, उस हिसाब से मैं अपने आपको इसका समर्थन करने में असमर्थ समझता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**12.03.2020/1520/JK/YK/2**

**सभापतिः** अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात):** सभापति महोदय, दिनांक 6 मार्च, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष वर्ष 2020-2021 का बजट आदरणीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में प्रस्तुत किया। यह एक ऐतिहासिक बजट है। आज से पहले इतना संतुलित बजट सभी वर्गों को जैसे गरीब, मज़दूर, अपाहिज, बुजुर्ग, महिला वर्ग, लाचार, बीमार, विधवा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा वर्कर, एस.एम.सी., अध्यापक, व्यापारी वर्ग, बेसहारा, कृषक, बागवान, पिछड़ा वर्ग, युवाओं, स्कूली बच्चों, कर्मचारी वर्ग, पत्रकारों, लम्बरदारों एवं चौकिदारों के हित में, जनता को प्रेषित किया उसकी मैं सराहना करता हूं,उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, मैं आदरणीय मु1ख्य मंत्री जी और सरकार को बधाई देता हूं कि पिछले दो वर्षों में जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को 21 पुरस्कार मिल चुके हैं। समय लगेगा, बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण है और इस सरकार को 21 पुरस्कार दो वर्ष में मिल चुके हैं। कुछ मेरे साथी देश के बारे में बता रहे थे क्योंकि जब कोई देश के बारे में बोलता है तो तब मुझे थोड़ी-बहुत चुभन होती है। मेरे साथी ने कहा कि धारा- 370 और 35-ए के लिए कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने कश्मीर से एग्रीमैंट किया था और अपनी नाकामियों को छुपा रहे थे। मैं यह बाताना चाहता हूं कि इतना खून हमारे सैनिकों का, हमारे भाइयों का कश्मीर में बहा है, उसका कर्ज़ हम जिन्दगी भर नहीं उतार सकते हैं। मैं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि आज वहां पर अमन है, चैन है, न वहां पर पत्थरबाजी हो रही है और न ही गोलीबारी हो रही है। मेरे कुछ मित्र यहां पर बोल रहे थे कि नेताओं को अन्दर किया हुआ है। अपनी सहुलियत के लिए उस समय जो सरकार थी, उसमें जो नेता थे, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए यह धारा वहां पर लागू की हुई

**12.03.2020/1520/JK/YK/3**

थी। परन्तु आज आदरणीय मोदी जी ने पूरे हिन्दुस्तान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरो दिया है, इसके लिए हम उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। यहां से मेरे मित्र बोल रहे थे कि कन्हैया लाल जी जब प्रदर्शन करते हैं तो बोलते हैं कि ये आतंकवादी हैं, यह फलां है।

**12.03.2020/1525/SS-AG/1**

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल क्रमागत :**

ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। यहां तक कि इन्होंने आर्मी को भी बदनाम किया। --- (***)--- बदमाशियां करती है तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा आर्मी का इतिहास बताना चाहता हूं। कर्नल साहब, इधर बैठे हुए हैं। जब स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री

थीं तो हिन्दुस्तान में उन्होंने एक-दो बार तीनों जनरलों (एयरफोर्स, नेवी और थल सेना) को बुलाया और एक फरमान जारी कर दिया कि संडे को सैनिकों की तनख्वाह और राशन बंद कर दिया जाए क्योंकि रविवार को ये कुछ नहीं करते। बेचारे सुनकर चले गए। वजीरेआजम का हुक्म था तो मानना पड़ा। जब संडे को सेना का सब कुछ बंद कर दिया है तो सेना ने नीचे से लिखकर देना शुरू कर दिया कि अगर रविवार के दिन हिन्दुस्तान पर हमला होता है तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तब हुक्मरानों की आंखें खुलीं कि फिर तो देश गुलाम हो जायेगा। इसी प्रकार से 1947 में बोलते हैं ..(व्यवधान) Yes, I have proof. I was in the Indian Army. I have served Indian Army. What do you know?

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** कृपया सदस्य बैठकर न बोलें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** आर्मी की डैफिनेशन क्या है? What do you know about Army?

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** माननीय सदस्य, आप चेयर को अड्रैस करें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** मैं आपको बताता हूं। दुख इसलिए होता है, सभापति महोदय, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। ---(***)--- I am telling you like this. मैं इसलिए बोल रहा हूं।

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** माननीय सदस्य, आप कृपा करके बजट पर बोलें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथ रहने वाले जो 17 जवान थे, वे मारे गए। मेरे सामने उनको गोलियां लगीं। एक और बात है।

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** माननीय सदस्य, आप कृपया बैठकर न बोलें। एक मिनट बैठिये। सदस्य केवल अपने सब्जैक्ट पर बोलेंगे प्लीज़।

---

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

12.03.2020/1525/SS-AG/2

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** सभापति महोदय, यहां पर इनके लोग ऐसे बाजू ऊपर करते हुए ***बाउंसर** बनकर आए थे। उस समय ये कहां थे? Where are you at that time?
...(interruption)

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** आप बैठकर न बोले प्लीज़।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** आपको कुछ पता नहीं है इसलिए आप बैठे रहो। मैं जानता हूं कि जब सैनिक मरता था तो उसकी डैडबॉडी घर नहीं आती थी। कुछ नहीं आता था।

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** जरयाल साहब, आप चेयर को अड्रैस करें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल : मैं** इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने वहां पर बोला था। बॉडी घर नहीं आती थी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद करता हूं कि आज अगर हमारा सैनिक कहीं भी शहीद होता है तो उसका मृत शरीर तिरंगे में लिपटकर घर आता है और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसकी क्रिमेशन होती है। आपको सच्ची बात झूठी लग रही है।

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** बिक्रम जी, आप अपने सब्जैक्ट पर बोलें। केवल बजटपर ही बोलिये।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को दर्द होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इतिहास के गवाह हैं। हम उस चीज़ के भुक्तभोगी हैं।
...(व्यवधान)

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** एक मिनट प्लीज़, माननीय सदस्य बीच में न बोलें। बैठकर न बोलें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** ---(***)---

---

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए1

12.03.2020/1525/SS-AG/3

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** कृपा करके बैठ के न बोले। We will expunge all these words. जरयाल साहब, आप चेयर को अड्रैस करें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने उधर लड़ाई लड़ी हैं। तुम्हारी तरह उधर बैठ के नहीं बोल रहे। अपना खून बहाया है। कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सेना को श्रीलंका भेज दिया। मुफ्त में श्रीलंका में सेना को मारा गया। ...(व्यवधान) ऐसे नहीं होता।

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** आप प्लीज सब्जैक्ट पर बोलें।

**Shri Bikram Singh Jaryal:** Madamji, I was in the fighting troops. Okay.

**सभापति जारी श्रीमती के0एस0**

12.03.2020/1530/केएस/एजी/1

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल जारी**----

**सभापतिः** मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बैठे-बैठे न बोलें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** सभापति महोदय, जो हमारी सरकार ने पिछले दो साल में विकास किया है, इनकी सरकार ने 10 साल तक नहीं किया। सभापति महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि कृपया मुझे गाली दे दो, मेरे देश को गाली मत देना। ...(व्यवधान) ऐसे ही बोलते रहोगे तो आपका भी सत्यानाश हो जाएगा।

**सभापतिः** माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बैठे-बैठे बीच में न बोलें। बिक्रम जरयाल जी, आप सब्जैक्ट पर बोलें और चेयर को एड्रेस करें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयालः** अध्यक्ष महोदय, यहां पर घोटालों की बात हो रही थी। केन्द्र में 10 साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हर रोज़ समाचार पत्र घोटालों से भरे रहते थे। आज मैं बहुत खुश हूं, जब मैं सुबह समाचार पत्र पढ़ता हूं, पूरा समाचार पत्र आदरणीय मोदी जी और जय राम जी की जनहित की योजनाओं से भरा होता है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं कि जो जनमंच योजना चलाई है, इससे लोगों को घर-द्वार पर सेवाएं मिल रही हैं। इसमें मौके पर आज तक 47,848 शिकायतों के निपटारे कर दिए गए हैं। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? आपने सिर्फ बातें ही की। "सहारा योजना" के तहत आज तक आदरणीय जय राम जी की सरकार 1,51,45,000 सहायता दे चुकी है। क्या आपने किसी को सहारा दिया? आप बैठे-बैठे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जैसे बॉक्सर होते हैं, उनकी तरह इस माननीय सदन में वैल में आ जाते हैं। किया आपने कुछ नहीं, सिर्फ वैल में घुसना सीखा है।

सभापति महोदय, वृद्धावस्था पैंशन की कांग्रेस सरकार के समय में 80 साल उम्र रखी थी। इनको पता था कि 80 साल तक इस जमाने में कोई नहीं जीता। मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी को धन्यवाद करता हूं, इन्होंने यह उम्र 70 वर्ष की

**12.03.2020/1530/केएस/एजी/2**

और कई लोगों को इसका फायदा मिला। "गृहिणी सुविधा योजना" के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके पास अपनी गैस न हो और इसके लिए भी मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, "हिम केयर योजना" के अंतर्गत 65,800 लाभार्थियों को फायदा मिला है और 60.98 करोड़ रुपया सरकार ने इस पर खर्च किया है और गरीब लोगों को मुफ्त इलाज दिया है।

"मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता योजना" के अंतर्गत 327 लाभार्थियों को 5.74 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं, आप लिख लो और जिसको लेने होंगे, मुझसे ले लेना।

"अटल आशीर्वाद योजना" के अंतर्गत 69,752 लाभार्थियों को फायदा मिला है । कांग्रेस के मेरे भाइयों को दुख होता है कि इतनी योजनाएं क्यों चलाई। इसी तरह से "मुख्य मंत्री आवास" योजना है। मोबाईल पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से घर-घर जाकर पशुओं का इलाज हो रहा है। आज पशुओं को पशु चिकित्सालयों में नहीं जाना पड़ता।

**सभापतिः** माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयालः** सभापति महोदय, "मुख्य मंत्री कन्यादान योजना" के अंतर्गत अब 51,000 रुपये की राशि दी जा रही है। मैं रोज़गार की बात करना चाहता हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**12.03.2020/1535/av-as/1**

**श्री-बिक्रम सिंह जरयाल-------- जारी**

मैं यहां पर पंचायती राज की बात करना चाहता हूं। उसके लिए आदरणीय मोदी जी ने थ्री टीयर सिस्टम चला दिया है। अब ये भी अपने कार्यों को खुद एग्जिक्यूट करेंगे। मैं इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करता हूं। ...(घंटी) सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय और चाहिए। आज हमारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नम्बर एक पर रहा है, ...(व्यवधान) आज हमारी सरकार ने कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों; जो अच्छे अंक लेकर पास हो रहे हैं उनके लिए भी लैपटॉप देने शुरू कर दिए हैं। ...(घंटी) सभापति महोदय, मेरी आदरणीय बड़ी बहन आशा जी 29 मिनट बोली हैं। ये भी जिला चम्बा से हैं और मैं भी जिला चम्बा से हूं इसलिए मैं भी अब 20 मिनट बोलूंगा। प्रदेश के युवाओं को रोज़गार देने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने स्वावलम्बन योजना, मधुमक्खी पालन

योजना, बागवानी, कृषि, पशु पालन, मछली पालन, मूर्गा पालन इत्यादि कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 20,000 युवाओं को नौकरी देने बारे कहा गया है और उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आज सभी विभागों में निरंतर भर्तियां हो रही हैं। ...(व्यवधान) मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय सदस्य नेगी जी कहां गये? उनको अंदर बुला लो, ऐसे बाउंसर बनकर काम नहीं चलेगा। ...(घंटी) मोदी जी ने नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, जी0एस0टी0, वन रैंक-वन पेंशन, उज्ज्वला योजना, प्रधान मंत्री रोज़गार योजना, किसान सम्मान निधि योजना, जीवन बीमा योजना, जन-धन योजना, श्रमधन योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पं0दीनदयाल योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, आयुष्मान भारत, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी अनमोल, जे0जे0एम0, अनुच्छेद 370 व 35 (ए) तथा सी0ए0ए0 लागू किया। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के बच्चों को नौकरियों में दस प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। वर्ष 2017 में आपकी सरकार के कार्यकाल में वित्तायोग के तहत 4,000 करोड़ रुपये आए थे और वर्ष 2020 में मोदी जी हमें 19,000 करोड़ रुपये की राशि दे रहे हैं। हम उनको कहां-कहां न याद करें। ...(घंटी) सभापति महोदय, बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं

**12.03.2020/1535/av-as/2**

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। मैं बोलने के लिए दूसरे सदस्य को आमंत्रित करने वाला हूं।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** सभापति महोदय, बस एक मिनट।

करता हूं फरियाद, आदरणीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी से।
इतनी रहमत कर देना, पुकारे आपको कोई भी; उसकी झोली भर देना॥

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

12.03.2020/1535/av-as/3

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश कुमारी भाग लेंगी।

**श्रीमती कमलेश कुमारी (भोरंज) :** सभापति महोदय, दिनांक 6 मार्च, 2020 को वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण यहां सम्माननीय सदन में दिया; उस पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करती हूं।

दिनांक 6 मार्च, 2020 को हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए; इससे प्रदेश के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी। मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के द्वारा गरीब का कल्याण, किसान का विकास, बागवान की चिंता, बेरोज़गार के लिए संसाधन, गुणवत्तायुक्त शिक्षा व शिल्पकारों के लिए सक्षम संसाधन जुटाने का अनूठा प्रयास किया है।

**टी सी द्वारा जारी**

12.03.2020/1540/TCV/AS-1

**श्रीमती कमलेश कुमारी ... जारी**

इससे प्रदेश में चहुंमुखी विकास होना सुनिश्चित है। सभापति महोदय, ऐसा सर्व-स्पर्शी बजट प्रस्तुत कर हिमाचल प्रदेश को शिखर की ओर अग्रसर करने के लिए मैं मुख्य मंत्री जी का इस सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूं, उनको बधाई देती हूं। पिछले 2 दिन से इस माननीय सदन में बजट पर चर्चा हो रही है, यहां 68 माननीय विधायक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आये हैं। हमारी विधायक प्राथमिकता का बजट जो 105 करोड़

रुपये होता था उसको बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये किया गया है, 'विकास निधि' को 1.25 करोड़ से बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये किया है और विधायक विवेक निधि की राशि को बढ़ाकर 8,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये किया है, जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। यह जो बजट है, यह भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों व विधायकों के लिए नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश से जो 68 विधायक चुनकर आये हैं, उन सबके लिए यह बजट है। लेकिन विपक्ष के 1-2 माननीय विधायकों को छोड़कर बहुत-सारे विधायकों ने कहा कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह सारा लाग-लपेट वाला बजट है। मैं माननीय सदन में कहना चाहूंगी कि 'सहारा योजना' उन परिवारों के लिए हैं जिन परिवारों के सदस्य बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति दिन-रात व्यस्त रहता है, अगर उन परिवारों की किसी ने सहायता की है तो माननीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने इस योजना के माध्यम से की है। उनकी सहायता राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये से 3000 रुपये किया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'आयुष्मान भारत योजना' शुरू की थी और उससे एक कदम आगे बढ़कर हमारी प्रदेश की सरकार व आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने 'हिम केयर योजना' शुरू की है। आज मुझे इस सदन में बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 'हिम केयर योजना' के तहत 68,222 लाभार्थियों को लगभग 63 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 52,922 लाभार्थियों

**12.03.2020/1540/TCV/AS-2**

को लगभग 53 करोड़ रुपये की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। यहां इस माननीय सदन में बात हो रही थी कि यह सरकार सूट-बूट की सरकार है लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि यह सूट-बूट की सरकार नहीं है, यह सरकार, वह सरकार है जिसके ऊपर 5-6 वर्षों के कार्यकाल में एक भी धब्बा नहीं लग पाया है। हम सब जानते हैं कि एक महीने के अंदर-अंदर 'चारा घोटाला', 'खेल घोटाला' ऐसे अनेकों घोटाले होते थे

**श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी ।**

12.03.2020/1545/RKS/DC-1

श्रीमती कमलेश कुमारी... जारी

लेकिन 6 वर्ष के कार्यकाल में हमें इस सदन में यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधान मंत्री गरीब परिवार से निकले हुए हैं। उनकी माता दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी और प्रधान मंत्री जी स्वयं रेलवे स्टेशन में चाय बनाकर बेचते थे। उस समय भी यह बात होती थी कि चाय बेचने वाला प्रधान मंत्री नहीं हो सकता। मैं इस माननीय सदन में कहना चाहूंगी कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना किसी जाति, धर्म, विशेष सम्प्रदाय के लिए नहीं हैं। ये योजनाएं उन लोगों के लिए हैं जो आम लोग हैं, गांव में बैठे लोग हैं। उज्ज्वला योजना में आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने 26 मई, 2018 को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का शुभारंभ किया था और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस योजना के तहत एक वर्ष के कार्यकाल में 2,76,000 महिलाओं को फ्री में गैस कनैक्शन्ज बांटे गए। यह गरीबों की सरकार है। यह गरीब, बेरोजगार, कर्मचारियों, महिलाओं, आम-आदमी, किसान-बागवान और पशुपालकों का बजट है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके लिए जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे। यह कैंसर की बीमारी गंभीर बीमारी है और इसके ऊपर विचार करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में इसका गुणगान किया है और बजट का प्रावधान भी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आउटसोर्स आधार पर जो आई.टी. शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं उनके मानदेय को बढ़ाया गया है। वे कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं परंतु उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इस बजट में उनके मानदेय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 प्रतिशत की वृद्धि की है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। जलगाड्र्स, पैरा फिटर्ज और पंप ओप्रेटर्ज़ के मानदेय में वृद्धि की गई है। जब मैं वर्ष 2016-17 में पंचायत प्रधान थी

तो जो पंचायतों में चौकीदार नियुक्त थे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद चौकीदार के पदों को भरा जाना था। उस समय हमें चौकीदार रखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। वे कहते थे कि

12.03.2020/1545/RKS/DC-2

हम 1800 रुपये में अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करेंगे। लेकिन मुझे इस सदन में बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज उस चौकीदार का मानदेय 5000 रुपये हो गया है। दो वर्षों के कार्यकाल में यह मानदेय 1800 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

12.03.2020/1550/बी.एस./डी.सी./-1

**श्रीमती कमलेश कुमारी जारी**...
इसी के साथ हमारी जो शिलाई अध्यापिकाएं थी, आंगनबाड़ी कार्यकताएं थीं, सहायिकाएं थीं, उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। महिलाएं जो शिलाई अध्यापिकाएं थीं और जमा दो की शिक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी उन बहनों को पंचायतों में सचिव के पद पर लगाया गया है। कौशल विकास भत्ते की सहायता से प्रदेश के हजारों युवाओं को लाभ मिला है। वर्ष 2021 में 80 हजार युवाओं को इस भत्ते का लाभ मिल रहा है इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करूं तो जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी, दिव्यांग जन थे उनके लिए जो पेंशन थी वह 600 रुपए से बढ़ा कर 850 रुपए की गई और वर्तमान बजट में उसे बढ़ा कर 1000 रुपए किया गया है।

**सभापति :** माननीय सदस्य कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्रीमती कमलेश कुमारी :** मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगीः

**कितनों की तकदीर बदल दी तूने, कितनों को लक्ष्य तक पहुंचाया है।**

**आपके बेहतर प्रयासों ने हिमाचल में नया इतिहास बनाया है।।**

सभापति महोदय जी, कृपया मुझे दो मिनट का समय और चाहिए। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात थी, 50 हजार पेंडिंग पड़े केसों के लिए प्रोविजन किया है और बढ़ी हुई राशि का लाभ लगभग 1.25 लाख लोगों को मिलेगा। इस वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 766 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके लिए में माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। युद्ध जांगीर लाभार्थियों को मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि को 5 हजार रुपए से बढ़ा कर उसे 7 हजार रुपए किया गया है। 50 स्कूलों में गणित की प्रयोगशालाएं तथा साइंस लैब बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। आदरणीय सभापति महोदय जी हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है कि जब आदरणीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल में 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया और जिस

12.03.2020/1550/बी.एस./डी.सी./-2

क्षेत्र में जो-जो लोगों की समस्याएं थीं उन्हें ध्यान में रखते हुए जो वहां पर घोषणाए की गईं उनको जमीन पर उतारा। यदि मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र के लिए दो डिविजन दिए गए, क्या इससे पहले सरकारों को पता नहीं था कि उस क्षेत्र के लिए दो डिविज चाहिए। चंदरूही से अगर बड़सर के लिए जाना होता था तो 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। यदि किसी को एक नलका सैंक्शन करवाना होता था तो 60 किलोमीटर जाना पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री और माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने दोनों डिविजन दिए और आज करोड़ों का बजट मेरे चुनाव क्षेत्र में लग रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कि हमारी सरकार और आपकी सरकार।

**सभापति** : माननीय सदस्य कृपया वाईंडअप करें, आपने 15 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है।

**श्रीमती कमलेश कुमारी** : माननीय सभापति महोदय, फट्टे वाली बात को कृपया सुन लें। पिछली सरकार ने केवल फट्टे लगाने का कार्य किया और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया तो उस अस्पताल का दर्जा भी बढ़ाया और 16 बिस्तर से 100 बिस्तरों का इसे किया गया और 12 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया अब उसके टैंडर हो गए हैं उसका कार्य शुरू होने वाला है। उस अस्पताल में आज चार विशेषज्ञ आएं हैं। एक गाइनी का, एक बच्चों का और एक डैंटल का विशेषज्ञ आएं हैं। ऐसी बातों अवश्य सुननी चाहिए।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

12.03.2020/1555/DT/YK-1

**श्रीमती कमलेश कुमारीः जारी...**

अगर हम अपनी सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल का गुणगान करने लगे तो हमें 15 मिनट नहीं चाहिए हमें इन कार्यों का गुणगान करने के लिए दो घंटे का समय चाहिए तभी हम अपनी पूरी बात रख सकते हैं। ऐसी-ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे-ऐसे काम हैं और मैं पंचायतों की बात करूं तो हमारे 13वें वित्त आयोग का बजट जो श्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की सरकार के समय 4 हजार करोड़ रुपये था उसे वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की की सरकार के समय बढ़ाकर 14 हजार करोड़ रुपये किया गया। अभी 15वें वित्त आयोग में 19 हजार करोड़ रुपये किया गया है जिसमें 5 हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

**सभापतिः** माननीय सदस्य आप प्लीज वाइंड-अप करें। आपका समय 16 मिनट से ऊपर हो गया है, कृपया वाइंड-अप करें।

**श्रीमती कमलेश कुमारीः** माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट अनुमान प्रस्तुत किया है मैं इसका अर्न्त दिल से समर्थन करती हूं। यह बजट गरीब जनता और युवा का बजट है। आपने मुझे बोलने का मौक दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय श्री राम

12.03.2020/1555/DT/YK-2

**सभापतिः** अब माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी इस चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

**श्री राकेश सिंघा(ठियोग)ः** सभापति महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में बजट पेश किया है मैं उस चर्चा में अपने आपको शामिल करता हूं। मैं इस बात का उलेख करना चाहता हूं कि पिछले 10 दिन की अवधि के अंदर-अंदर इस सदन में तीन दस्तावेज पेश किये गये हैं। पहला दस्तावेज माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 25 फरवरी को रखा गया। दूसरा, दस्तावेज इक्नोमिक सर्वे 5 मार्च को रखा गया और फिर finally, The Hon'ble Chief Minister placed this Budget proposals in this House.मै चुनौती देता हूं कि सरकार और सरकार में बैठे हुए जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं इन्होंने इन तीन दस्तावेजों को नही पढ़ा। मैं यह इसलिए यह कहा रहा हूं क्योंकि बहुत सी त्रुटियां इनके अंदर हैं। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जिस समय मुख्यमंत्री महोदय बजट भाषण को इस सदन में रख रहे थे तो उस समय कुछ मंत्री ऐसी थकान महसूस कर रहे थे जैसे वे कितने दिनों से महेनत कर रहे होंगे। यह थकान उनकी मेहनत की नहीं है यह थकान इस बजट प्रपोजल से उत्पन हुई है और आने वाले समय में यह थकान बनने वाली है। मैं इस सरकार को चार्ज सीट करना चाहता हूं। मैं लापरवाही के लिए चार्ज सीट करना चाहता हूं। जो सरकार का कैजुअल व्यवहार है मैं उसके लिए चार्ज सीट करना चाहता हूं। इस सदन को जो मिस लीड किया गया है। इस सदन को ही मिसलीड नहीं किया किया गया बल्कि हिमाचल प्रदेश की आवाम को इस सदन के जरिये मिसलीड किया गया है।

श्रीमती एम.एस द्वारा... जारी

12/03/2020/1600/MS/YK/1

**श्री राकेश सिंघा जारी**------

इसके लिए कौन दोषी है, उसका जवाब इस सदन के अंदर देना होगा? ...(व्यवधान) मैं बजट पर आ रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो फ्लैगशिप इस सरकार का रहा है, वह जनमंच रहा है। लेकिन आप बताइये कौन से आंकड़े सही है? क्या वे आंकड़े सही हैं जो इस बजट के अंदर आपने पेश किए हैं या जो माननीय राज्यपाल महोदय ने पेश किए या जिनका इकॉनोमिक सर्वे में आपने ज़िक्र किया है? क्योंकि तीनों आंकड़े मेल नहीं खाते हैं। Chairman, Sir, please allow me to read them. मैं सबसे पहले उन आंकड़ों को पेश करना चाहता हूं जो पैरा-5 के अंदर हैं। मैं उसको कोट करना चाहता हूं "During the tenure of present Government 189 'Jan Manch' programmes have been held in which 47 thousand 848 complaints and demands were received, out of which, 43 thousand 548 complaints were redressed". अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज-9 पर आप देखिए कि क्या आंकड़े पेश किए गए। "Till 16th February, 2020, a total 189 'Jan Manch' programmes have been organized in various Vidhan Sabha Constituencies. A total of 45 thousand 708 complaints and demands have been received and 41 thousand were redressed". एक डॉक्यूमैंट में आप 45,000 कह रहे हैं और दूसरे में 47,000 कह रहे हैं। आप बताइये कि आपके कौन से तथ्य सही हैं? ये वाले सही हैं या दूसरे वाले सही हैं। ...(व्यवधान) यही नहीं, ...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए।

**सभापति (श्री राकेश पठानिया):** कृपया माननीय सदस्यगण बैठकर न बोलें।

**श्री राकेश सिंघा:** ...(व्यवधान) मिसलीड नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, मुख्य मंत्री सेवा संकल्प के बारे में एक डॉक्यूमैंट कहता है कि 37,990 शिकायतें आईं और दूसरे डॉक्यूमैंट के पैरा-8 में कहते हैं कि 33,275 शिकायतें आईं। आपके कौन से आंकड़े सही हैं? यही नहीं, आगे देखिए। आपने बजट भाषण में "प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान" में जो आंकड़े पैरा-33 के अंदर पेश किए हैं, वे कुछ और हैं और जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज-15 में आंकड़े दिए हैं, वे कुछ और हैं।

**सभापति (श्री राकेश पठानिया):** माननीय सदस्य, कृपया बैठिए। मंत्री जी कुछ स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं।

**कृषि मंत्रीः** सभापति जी, राकेश सिंघा जी बहुत जोश में बात कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो इन्होंने दो आंकड़े

**12/03/2020/1600/MS/YK/2**

मुख्य मंत्री संकल्प सेवा योजना के बारे में बताए हैं, उसमें ऐसा है कि हमारे पास हररोज़ 3000-4000 शिकायतें आती हैं। मैं शिकायतों की बात कर रहा हूं। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आंकड़े कुछ अलग हैं और दूसरे डॉक्यूमैंट में आंकड़े अलग हैं क्योंकि शिकायतें लगातार आ रही हैं।

**Chairman (Shri Rakesh Pathania):** This is a very valid point.

**कृषि मंत्रीः** ये दोनों चीजें अलग हो सकती हैं क्योंकि लोगों की हररोज़ शिकायतें आती हैं और ये आंकड़े उसके हिसाब से हैं। Singha Sahib, don't misled the House.

**सभापति (श्री राकेश पठानिया):** राकेश सिंघा जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप आंकड़ों पर मत जाइए, आप पॉलिसी मैटर पर बोलिए। You are a very good speaker.

**श्री राकेश सिंघाः** सभापति महोदय, इन्होंने डॉक्यूमैंट पढ़ा नहीं है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि इस दस्तावेज़ के अंदर जो बजट को पेश करने का बेसिक सिद्धान्त है, उसको आपने वायलेट किया है। आपने कैसे वायलेट किया है, वह मैं आपको बताता हूं। बजट के प्रावधान, बजट को पेश करने से पहले कभी नहीं रखे जाते हैं लेकिन आप अपने इकॉनोमिक सर्वे को देखिए, उसमें पैरा-1.20 में कहा है कि

To be continued by AG in English----

**12-03-2020/1605/एच.के.-ए.जी./1**

**श्री राकेश सिंघा----जारी----**

"The Annual Plan Budget for 2020-21 has been proposed at Rs. 7900.00 crore which will be 11.3 percent higher than the plan size of current year 2018-19." Can you do it even prior to placing the Budget in the House? The same figure appears in your Budget proposals. Is it allowed? It amounts to leaking the Budget. You are leaking the Budget when you are already putting the proposals of the Annual

Plan. क्या मतलब बनता था इकोनॉमिक सर्वे में वह डाटा आना चाहिए था। इकोनॉमिक सर्वे में श्री महेन्द्र सिंह जी आपका डाटा वह आएगा, जो पिछले साल में आपने काम किया है, जो आपने बजट अलग-अलग हिस्सों में दिया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, कितना पैसा खर्च हुआ है और उस पैसे को लगाने के बाद क्या रिजल्ट निकला, वह आपको इसमें दर्शाना चाहिए था। लेकिन आप पढ़ कर देखिए कहीं भी आपने नहीं कहा है कि आपका रिजल्ट क्या आया है? सिर्फ आपने क्या किया है कि लास्ट इयर के बजट को उठा कर कट एण्ड पेस्ट कर इकोनोमिक सर्वे का दस्तावेज बना दिया है। Throw it in the dustbin. यह इस लायक भी सरकार का दस्तावेज नहीं है जो आप कोई भी एनालाइसिस इस दस्तावेज के अन्दर नहीं कर सके। मैं इस बात पर भी आना चाहता हूं कि पैरा-111 के अन्दर इन-करैक्ट स्टेटमैंट सरकार ने दी है। क्या कहा है - "The Central Government has been successful in keeping inflation under control".

कहां से यह तथ्य निकाला है, मुझे बताएं? यह सिर्फ इनफ्लेशन नहीं है लेकिन ग्रोथ भी रुक गई है। यह स्टैग इन्फ्लेशन का दौर आ रहा है। मुझे बताएं कि अगर इन्फ्लेशन नहीं थी तो डी.ए. की किस्त आपने क्यों दी? 5 फीसदी डी.ए. की किस्त तभी दी जाती है जब मुद्रा स्फीति बढ़ती है। एक तरफ से मुद्रा स्फीति बढ़ रही है जिसको आप रिकोगनाइज़ नहीं कर रहे हैं और मैं यह आपको बता दूं कि आर.बी.आई. इसको रैकग्नाइज़ कर रहा है। भारत सरकार का फाइनैंस डिपार्टमैंट इसको रैकग्नाइज़ कर रहा है कि जो मंहगाई पिछले दिनों में हुई जनवरी के अन्दर के जो आंकड़ें आए हैं, वे आए हैं 7.59 परसेंट, it has been the highest in the last six years. जो पिछले 6 वर्षों की यह मंहगाई हुई है। यही नहीं फूड इन्फ्लेशन 14 परसेंट हो गई है। एक समय था 60 फीसदी को उसने क्रॉस किया। यही नहीं, आपके पैरा-13 के अन्दर इन-करैक्ट स्टेटमैंट है, उसको मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं - "My Government has managed fiscal affairs of the State prudently". मैं यह

**12-03-2020/1605/एच.के.-ए.जी./2**

कहना चाहता हूं। आप Fiscal Responsibility and Budget Management Act को पढ़ो। वह कहता है कि आपका जो फिसकल डेफिसिट है, 3 फीसदी से अधिक नहीं जाएगा। अनुमति उसने इतनी ही दी है कि 3 फीसदी से आप 3.5 तक कर लें, उसके beyond नहीं जा सकते हैं। आपने 4 परसेंट का फिस्कल डेफिसिट शो किया है। देखिए, मैं FRBM Act

से खुद सहमत नहीं हूं। वह जो फाइनैंस केपिटल है, उसके आदेश है। मैं तो इस बात का हूं कि जितना खर्च सरकार करेगी उतना अच्छा होगा लेकिन आपके मुताबिक, यह जो आपने इसमें दिया है, यह स्टेटमैंट गलत है। जो आपने पैरा-11 में कोट किया है, आप देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है - "This has been a result of economic and structural reforms undertaken by the Central Government". यह जो स्ट्रक्चरल रिफोर्म आप कर रहे हैं, इसका नतीजा है जो बद्दी में हो गया। यह जो स्ट्रक्चरल रिफोर्म आप कर रहे हैं, उसका नतीजा है जो मानव भारती विश्वविद्यालय आज शिक्षा नहीं दे रहा है लेकिन शिक्षा के नाम पर नोट कमा रहा है। यह स्ट्रक्चरल रिफोर्म के मुताबिक है कि जो यस बैंक ने धंधा कर दिया है, जो लूटने का काम कर दिया है, यह स्ट्रक्चरल चेंजिंज़ की वजह से हुआ है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय डबल इंजन की सरकार, अभी डॉक्टर साहब यहां पर बैठे नहीं है लेकिन उसका भी मैं हवाला देना चाहता हूं कि यह जो आपकी डबल इंजन की सरकार है।
श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

**12.03.2020/1610/SS-AG/1**

**श्री राकेश सिंघा क्रमागत :**

ये डबल इंजन कोयले से चलने वाला है या यह डीजल से चलने वाला है या यह बिजली से चलने वाला है। ठाकुर साहब, सुन लें। जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो सबसे कठिन दौर हमारे सामने आने वाला है वह यह है कि कृषि संकट हमारे सामने आ गया है। यह दस्तावेज़ (इकोनॉमिक रिव्यू) इसको recognize करता है कि आज हिमाचल प्रदेश बहुत गहरे कृषि संकट से गुजर रहा है। उस कृषि संकट से ओवरकम के लिए आप सुझाव क्या दे रहे हैं? ठाकुर साहब, आप सिर मत हिलाओ। यह डाटा बोलता है। आपकी कृषि में 2.19 माइनस ग्रोथ है। ऑवरऑल कृषि में 1.79 माइनस ग्रोथ है। यह तो सेब ने छोटा-मोटा लिहाज रख दिया। नहीं तो यह ग्रोथ इससे भी नीचे जानी थी। आप मेरी बात को मानो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश को बचाओ। प्रदेश बच सकता है। लेकिन अगर आपकी नीतियां यही रहेंगी तो मैं लिखकर देता हूं कि यह प्रदेश डूब जायेगा। आप भी इस प्रदेश के बारे में चिन्तित हैं, ये भी प्रदेश के बारे में चिन्तित हैं, मैं

भी प्रदेश के बारे में चिन्तित हूं और अगर इस प्रदेश को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है और वह तरीका यह है कि आपको कृषि निवेश सही तरीके से करना है। आपने सुझाव क्या दिया है कि स्ट्रक्चरल चेंजिज़ भी आप कृषि के अंदर लायेंगे। पता है कि उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि Adani will take over our agriculture. आज सिर्फ वह सी0ए0 स्टोर बनाता है और उससे आगे वह आपकी खेती की तरफ बढ़ेगा।

सभापति महोदय, आप मुझे दो मिनट दें, मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसलिए अगर कृषि बचानी है तो करना यह होगा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जो किसान अपनी ज़मीन को छोड़कर इस शहर में आ गया, क्यों आया? वह इसलिए आया कि खेती आज लाभकारी नहीं रही है। तभी शहर में आया है। कोई इस तरीके से अपने खेत को छोड़कर नहीं जाता है। एक किसान आखिरी सांस तक खेत में काम करता है क्योंकि उसको अपनी ज़मीन प्यारी है। अगर वह उसे छोड़कर जा रहा है तो आप उसके कारण तलाशो। कारण यह नहीं कि उसकी ज़मीन पर खेती करने के लिए आप आढ़ती को ढूंढ लेंगे। आढ़ती उसकी खेती

**12.03.2020/1610/SS-AG/2**

करने के लिए आयेगा लेकिन आज खेती करेगा तो कल को उसका मालिक बन जायेगा। मेहरबानी करके यह काम मत करो। करना क्या है? आप खेती को लाभदायक कर सकते हैं आपमें इच्छा शक्ति चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए।

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** माननीय सदस्य, वाइंड अप करें प्लीज़।

**श्री राकेश सिंघा :** अगर वह राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करेंगे तो यह खेती बच पायेगी।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को इस बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि बहुत से विवाद रहेंगे। अगर मुझे बजट का समर्थन करना होता तो मैं उधर (सत्तापक्ष में) बैठा होता। आप तो इतना भी टॉलरेट नहीं करते

और ---(***)--- वे अपने माइंड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष होगा। आप इस बात को सीखने की कोशिश करो कि विपक्ष की बात को सुन लिया जाए। ...(व्यवधान) क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो प्रावधान आपने बजट में दिये हैं ये हिमाचल का विकास नहीं कर सकते हैं।

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** माननीय सदस्य, आप वाइंड अप करें, आपका भाषण बहुत लम्बा हो गया। आपको बोलते हुए 16 मिनट हो गए हैं।

**श्री राकेश सिंघा :** ये जो बजट प्रावधान आपने इस बजट में किये हैं मैं इनको रिजैक्ट करता हूं। अगर आप इनको संशोधित करेंगे तो इनका समर्थन हो सकता है अन्यथा कोई समर्थन इस बजट को नहीं मिल सकता है। मुझे आप माफ करें अगर मेरे शब्द आपको कड़वे लगे। लेकिन मैंने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो फार्मूला यहां पर पेश किया है उसे अमल में लाया जाए। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इन बजट प्रावधानों पर बोलने का यहां पर मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री राकेश पठानिया, सभापति :** ये जो आपने पर्सनल रिमार्कस दिया है, यहां पर सब इलैक्टिड लोग बैठे हैं, इनको एक्सपंज किया जायेगा। This will be expunged और

**जारी श्रीमती के0एस0**

---

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

**12.03.2020/1615/केएस/एएस/1**

**सभापति जारी**---

और ऐसे पर्सनलाइज़ रिमार्क्स मत दीजिएगा। इसको एक्सपंज किया जाए। अब आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी कुछ स्टेटमैंट देना चाहेंगे। ... (व्यवधान)

**Sh. Rakesh Singha:** Hon'ble Chairman, Sir, I take my words back.

**सभापतिः** श्री राकेश सिंघा जी, कृपया बैठिए। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

**जल शक्ति मंत्री :** सभापति महोदय, राकेश सिंघा जी ने विशेषकर कृषि और बागवानी के क्षेत्र के बारे में चर्चा की। दूसरे, इन्होंने बात कही है कि आर्थिक मंदी का दौर है इसलिए आपने कर्मचारियों और अधिकारियों को डी.ए. की किस्त क्यों दी? सभापति महोदय, यह सरकार आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में कर्मचारी/अधिकारी हितैषी सरकार है। यह सरकार किसान और बागवानों की सरकार है, सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना हमारी सरकार का कर्तव्य व धर्म है और हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा, जो खाली भूमि पड़ी है, उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमने अनेकों बड़ी-बड़ी योजनाएं लाई हैं। आप देखेंगे, उसके परिणाम अब आने वाले हैं। जैसे जो हमारा ऊपर का क्षेत्र है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट चला हुआ है और जो नीचे का सब-ट्रॉपिकल एरिया है, उसके लिए शिवा प्रोजैक्ट चला हुआ है। मैं माननीय सदस्य श्री सिंघा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि जो 17 क्लस्टर हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया में जो काम शुरू हुआ है, आप मेरे साथ चलें और देखें कि किस प्रकार से हम किसानों की ऐसी जमीन जो किन्हीं कारणों से हो सकता है उसमें जंगली जानवरों, बंदरो या कुछ आवारा पशुओं की वजह से किसान मज़बूर हुए हों, उस ज़मीन को कृषि और बागवानी क्षेत्र में लाने के लिए, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने योजना लाई है और वह योजना अब धरातल पर उतर रही है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने और भी बातें कही हैं, आपने जो कहा है, आज से पहले जब भी प्लानिंग की बैठक होती है, तो प्लानिंग की बैठक में पहले ही बताया जाता है कि इस

**2.03.2020/1615/केएस/एएस/2**

बार हमारा प्लान साइज़ इतना है, पिछली बार इतना था और इस साल बढ़कर इतना हुआ है। उसी प्लान साइज़ के मुताबिक अगले वर्ष का बजट बनता है। आप आर्थिक सर्वेक्षण की जो बात कर रहे हैं, जो कुछ यहां हाउस में रखा गया, वह बिल्कुल ठीक रखा गया है, दुरुस्त रखा गया है।

**12.03.2020/1615/केएस/एएस/3**

**सभापतिः** अब इस चर्चा में आदरणीय सदस्य श्री परमजीत सिंह जी हिस्सा लेंगे।

**श्री परमजीत सिंहः** सभापति महोदय, जो बजट 06 मार्च, 2020 को इस माननीय सदन में मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत किया, उस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, जो यह बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया, एक कर मुक्त बजट और माननीय मुख्य मंत्री जी का तीसरा बजट इस प्रदेश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए प्रस्तुत किया है। यह बहुत ही शानदार और जानदार बजट है, मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूं और इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इससे पहले जो दो बजट पेश किए, जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी उनमें ले कर आए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हरेक योजना को माननीय मुख्य मंत्री जी ने धरातल पर उतारा है। चाहे उसमें "हिम केयर" योजना है, "हिमाचल गृहिणी योजना" है, "सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना" है या "स्वावलम्बन योजना" है। अनेकों योजनाएं हैं। जैसे "हिमाचल गृहिणी योजना" है! हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सी बहनें, बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने आज तक गैस का कनैक्शन यूज़ नहीं किया था और लकड़ी से अपना खाना बनाती थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के सहयोग और आशीर्वाद से उन बहनों और माताओं को आज गैस का कनैक्शन उपलब्ध हुआ है।

श्रीमती अ0व0 द्वाराज री---

**12.03.2020/1620/av-as/1**

**श्री परमजीत सिंह-------- जारी**

माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से उन बहनों और माताओं को आज गैस के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2,76000 गैस कनेक्शन फ्री में वितरित किए गए हैं और यह माननीय जय राम ठाकुर जी के आशीर्वाद से सम्भव हो सका है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में विधायकों की विधायक निधि को 1.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये किया है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड के अंतर्गत बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं की निधि जो समाप्त हो रही थी उसको भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 105 करोड़ रुपये की राशि से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये किया। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक निधि की राशि जो पहले 8 लाख रुपये थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रदेश के बेरोज़गार युवा जो अपना काम करना चाहते थे; उनके लिए मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना कारगर साबित हुई है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के उद्यमियों को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए मशीनरी हेतु 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी गई है। यह सहायता राशि मिलने के कारण आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान केवल अपने आप ही काम नहीं कर रहा बल्कि आगे दो-तीन और व्यक्तियों को रोज़गार दे रहा है। सामाजिक पेंशन योजना हमारे वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को बिना आय सीमा के पेंशन देने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत अभी तक लगभग 1.50 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आज हिमाचल प्रदेश में 5.34 लाख लोग लाभ उठा रहे हैं और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस पेंशन योजना के तहत आगामी वर्ष में 50,000 लोगों को और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है; इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। इससे हिमाचल प्रदेश के और 50,000 वृद्ध लोगों

**12.03.2020/1620/av-as/1**

को फायदा मिलेगा। हमारे ऐसे लोग जिनके पास मकान नहीं है उन गरीब लोगों के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक साल के अंदर 10,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार 10,000 गरीब व्यक्तियों को घर बनाकर देगी; यह पहली बार हुआ है और इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में उन 10,000 गरीब व्यक्तियों के लिए घर बनकर तैयार होंगे जो आज छत के लिए तरस रहे हैं। हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि प्रदेश के बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश के अंदर यह पहली बार हुआ कि पिछले दो वर्ष के कार्यकाल में माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने 20,000 नौकरियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 साल के कार्यकाल में इतनी नौकरियां नहीं दे पाई जितनी वर्तमान में जय राम ठाकुर की सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में दी हैं। वर्तमान सरकार द्वारा 6000 नौकरियां शिक्षा के क्षेत्र, 3000 नौकरियां विद्युत विभाग, 1300 नौकरियां परिवहन विभाग, 1000 नौकरियां पुलिस विभाग में दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कई दूसरे विभागों में भी नौकरियां देने के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है मैं उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां पर पिछले दिनों हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बद्दी ट्रेड सैंटर की बात उठाई थी। बद्दी ट्रेड सैंटर के बारे में यहां पर सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है।--------

**टी सी द्वारा जारी**

**12.03.2020/1625/TCV/DC-1**

**श्री परमजीत सिंह .. जारी**

मैं आपके माध्यम से इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि यह ट्रेड सैंटर मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में आता है। यह ट्रेड सैंटर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 'एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रैक्चर विकास योजना' के अंतर्गत सितम्बर, 2000 में स्वीकृत हुआ था और हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'स्टेट लैवल

एक्सपोर्ट प्रमोशन' एक समिति का गठन किया गया था। जिसकी पहली मीटिंग 21.10.2008 को हुई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस बद्दी ट्रेड सैंटर को बी0बी0एन0डी0ए0 के माध्यम से बनाया जाएगा। इसकी कुल लागता 10.81 करोड़ रुपये थी जिसमें 5.40 करोड़ रुपये भारत सरकार ने देने थे और भूमि की कीमती जो 3.20 करोड़ रुपये थी, वह राज्य सरकार ने देनी थी। इसके अतिरिक्त 221 करोड़ रुपये बी0बी0एन0डी0ए0 ने देने थे। इसका निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ और इसको भटौली-कलां गांव में 33 बीघा 11 बिस्वा में इस ट्रेड सैंटर को बनाने का प्रावधान किया गया। इस ट्रेड सैंटर का निर्माण बी0बी0एन0डी0ए0 के माध्यम से वर्ष 2015 में पूरा किया गया लेकिन मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि उसके पश्चात आज तक उस ट्रेड सैंटर में कबूतर बोलते थे, लोग शराब पीते थे, उसका कोई मालिक नहीं था। मैंने मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी से निवेदन किया, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं , जिन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। हमने कहा कि इस ट्रेड सैंटर को किसी कम्पनी को दे दिया जाये या किसी होटल वाले को दे दिया जाये जिससे 13.81 करोड़ रुपये जो सरकार का इस पर खर्च हुआ, वह काम आ सके।

**12.03.2020/1625/TCV/DC-2**

माननीय सभापति जी, 10.06.2011 को पहला ऑन लाइन टेंडर आमंत्रित किया गया लेकिन किसी पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया। दूसरा टेंडर 29.06.2011 को ऑन लाइन किया गया और उसमें 3 पार्टियों ने भाग लिया, एक पार्टी डिस-क्वालिफाइड हो गई। इनमें सबसे ज्यादा बोली 1,70,777/- रुपये सुन्दर कक्कड़, होटल लुधियाना ने दी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह आबाद तो हुआ वरना इसकी हालत खराब थी। 33 बीघा 11 बिस्वा में जो प्रॉपर्टी बनी हुई थी उसको कोई लेने वाला ही नहीं था। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसके लिए पहले की। इस बद्दी ट्रेड सैंटर के ऊपर 2015 से लेकर हर साल मेंटेनेंस पर खर्चा होता था लेकिन

सरकार की इस पहल से जो ट्रेड सैंटर 33 बीघा 11 बिस्वा में बना है, वह बच जाएगा। ...(व्यवधान)

**सभापति :** माननीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे न बोलें।

**श्री परमजीत सिंह :** सभापति जी पहले टेंडर में तो कोई आया ही नहीं लेकिन दूसरे टेंडर में जो सबसे ज्यादा बोली वाला था, उसको यह दे दिया गया था। इससे डवलपमैंट होगी और सरकार का जो पैसा लगा था, वह यूज़ होगा। आज इससे हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति नीति अपनाई है, उसके तहत मेरा कल ही प्रश्न लगा था,

**श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी**

12.03.2020/1630/RKS/DC-1

श्री परम जीत सिंह... जारी

मैंने कहा था कि बी.बी.एम.बी. में जो अधिकारी बार-बार आ रहे हैं उससे लोगों के मन में गलत शंका पैदा हो रही है। कुछ लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन अधिकारियों को बार-बार बी.बी.एम.बी. में न लगाया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बद्दी में विजिलैंस थाना खोलने का निर्णय लिया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो किसानों को ट्रैक्टर खरीदने हेतु 3 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है उसे 50 हजार रुपये किया जाए ताकि अधिकतर किसान इस सब्सिडी के तहत कवर हो सके। बहुत कम किसानों को 3 लाख रुपये मिलते हैं और अधिकतर किसान लाइनों में लगे रहते हैं। यदि आप इस सब्सिडी को 50 हजार रुपये कर देंगे तो ज्यादा किसान इसमें शामिल हो सकते हैं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायक निधि, विधायक प्राथमिकता निधि और ऐच्छिक निधि बढ़ाई थी तो विपक्ष के मित्रों ने इसका

स्वागत किया था। लेकिन जब इस बजट में और कामों का जिक्र किया गया तो विपक्ष के साथी इन कामों का समर्थन करने में असमर्थ हो गए। हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता, गरीब आदमी और किसान इस बजट का समर्थन कर रहा है। मैं भी इस बजट का समर्थन करता हूं। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**सभापतिः** अब माननीय सदस्य श्री सुभाष ठाकुर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री सुभाष ठाकुर(बिलासपुर)**ः सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 06 मार्च, 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए जो बजट अनुमान प्रस्तुत किया है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट ऐतिहासिक, सर्वस्पर्शी बजट है और इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में कई पग उठाए गए हैं। पूर्व के बजट में जो अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थीं उन

12.03.2020/1630/RKS/DC-2

सभी योजनाओं को पूर्ण किया गया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। महिलाओं के लिए जो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरूआत की गई है, उसमें 2,76,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन्ज दिए गए हैं जिसमें 57 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को गैस मुहैया करवाई जाएगी और यह हमारे लिए गर्व की बात है। महिला सशक्तिकरण के लिए यह बहुत ही बड़ा योगदान है। जहां हमारे पेड़ कटने से बचे हैं वहीं हमारी माताओं और बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा गया है। चूल्हा जलाने के कारण जो सांस की समस्या होती थी, अन्य रोग होते थे उनसे निजात मिली है। वन हिमाचल प्रदेश की सुन्दरता है। गैस कनैक्शन मिलने से वनों के कटान में कटौती आई है। यह योजना हर वर्ग की बहनों व

माताओं के लिए लोकप्रिय रही है। 7-8 नवम्बर को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वैस्टर मीट का आयोजन किया गया।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

12.03.2020/1635/बी.एस./वाई.के./-1

**श्री सुभाष ठाकुर जारी...**

उसका भी मैं पुरजोर समर्थन करना चाहूंगा। यह पहली बार हिमाचल प्रदेश में इन्वैस्टर मीट हुई। इस देश के यशसस्वी प्रधान मंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और आर्शीवाद दिया और हिमाचल में आ करके देश और दुनिया से आने वाले जितने भी यहां पर इन्वैस्ट्र्ज थे उन्हें यह अहसास दिलाया कि भारत देश के प्रधान मंत्री हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ हैं। आप आपने उद्योग को यहां पर स्थापित करिए। हिमाचल प्रदेश को और यहां के लोगों को भारत सरकार का पुरजोर समर्थन है। यह संदेश दे करके प्रधान मंत्री जी यहां से गए। यह पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि प्रधान मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी और देश वासियों की पीठ थपथपाई है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा 97,700 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें 736 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और अनुमानित 1,96,000 नौजवानों को रोजगार देने का प्रावधान है। प्रदेश में निवेश के लिए प्रमुख क्षेत्र कृषि, बागवानी, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, वैलनैस, हाइड्रो इत्यादि हैं। इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने के लिए यह एक बहुत बड़ा पग है क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमेशा केन्द्र के पास जाता है तो हमेशा पैसा मांगता है। यह पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने पर्यटन के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, कृषि के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। इसके लिए भी इस बजट का भी समर्थन करता हू और इन येाजनाओं का भी समर्थन करता हूं।

उसी तरह से जनमंच कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आम व्यक्ति के लिए, दूरदराज गांव में बैठा हुआ निर्धन व्यक्ति जो जिला मुख्यालय में नहीं आ पाता और जो अधिकारी के साथ बात करने से संकोच करता है उनके लिए यह जनमंच कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय कार्यम है। लोग इसे अपना कार्यक्रम मान रहे हैं। गरीब इसे अपना कार्यक्रम मान रहे हैं। उनकी जो छोटी-छोटी दिक्कतें वर्षों-वर्षों से थीं उनके लिए उन्हें बार-बार कार्यालयों में जाना पड़ता था।

12.03.2020/1635/बी.एस./वाई.के./-2

आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां पर मंत्री भी जाते हैं अधिकारी भी जाते हैं और समस्याओं कापूछ करके उनका निवारण किया जाता है। यह पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे प्रतिपक्ष के जो लोग हैं वे भी इस विषय पर जो कहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि जिस विधान सभा में सत्ता पक्ष का कोई विधायक नहीं होता है वह विधायक यह कहते हैं कि सरकार के कार्यक्रम सरकार की योजनाएं और वहां के लोगों की दिक्कतें सरकार नहीं सुनती है अधिकारी नहीं सुनते हैं, जनमंच के द्वारा यदि किसी की चिंता की है तो सबसे ज्यादा विपक्ष के लोगों की चिंता की है। उस चुनाव क्षेत्र के आम जन की चिंता की है कि यदि आपका विधायक विपक्ष में है तो आप सभी की जिम्मेवारी भी हमारी है। अपनी जिम्मेवारी मानकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। जो लोग इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं वे आम व्यक्ति का विरोध समझा जा रहा है। यह किसी पार्टी, अधिकारी और नौकरशाहों का कार्यक्रम नहीं है। यह लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मंच है जो देश में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस कार्य के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में जो 181 कार्यक्रम इसमें हुए हैं और 91 प्रतिशत लोगों की समस्याओं का इसमें समाधान हुआ है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

12.03.2020/1640/DT/AG-1

श्री सुभाष ठाकुरःजारी ...

हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश गांव में बसता है इसलिए कृषि के क्षेत्र में किसानो की आय दोगुनी करने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रयास किए हैं और यह कहा है कि इस देश के किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की सरकारें इस विषय को ले रही है और उसी तरह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी यह बीड़ा उठाया है कि हिमाचल प्रदेश के किसान- बागवान की आमदनी दोगुनी हो। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को 61,161 लोगों ने अपनाया है। इस योजना के अधीन 2,114 हैक्टेयर भूमि आती है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना बहुत अच्छी साबित हुई है। आम किसान जंगली जानवरों, बंदरों और आवारा पशुओं के खेतों में आने के कारण अपनी खेती छोड़ रहा था। वे जानवर किसानों की फसल नष्ट कर देते थे। इसलिए इस योजना को एक संवेदनशील आधार पर हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी जलवायु इस प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त है। हिमाचल प्रदेश की सब्जी, बेमौसमी सब्जी पूरे देश में बिक सकती है। ओर्गेनिक खेती की पूरे देश में डिमांड है। ओर्गेनिक खेती के लिए हिमाचल प्रदेश का जलवायु बहुत ही उपयुक्त है। सहारा योजना के माध्यम से 5,580 लाभार्थियों को दो हजार रूपये का उपदान मिलता था उसको भी बढ़ा कर तीन हजार रूपये किया गया है। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हिमकेयर योजना के तहत 68,222 लोगों को लाभ मिला है और 63 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च हुआ है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत -बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बीमारी कभी भी किसी को पूछ कर नही आती। चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो कब आएगी, कैसे आएगी कौन-सी दिक्कत होगी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमकेयर योजना लागू की है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह एक बहुत ही कल्याणकारी कार्य किया है। सभापति महोदय, वर्तमान में दो रेल परियोजनाएं भानूपली से बिलासपुर बैरी और चंडीगढ़- बद्दी का

जिक्र किया है। भानूपली से बिलासपुर बैरी रेल लाइन के प्रथम चरण में 20 किलोमीटर भू-आधिग्रहण पूरा हो चुका है तथा इसका निर्माण कार्य भी आरम्भ हो चुका है। शेष बची अलाइनमैंट पर भू-आधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने के लिए कहा गया है। इस प्रयोजना के निर्माणाधीन कार्य के लिए वर्ष 2019-20 में बजटीय प्रावधान में

12.03.2020/1640/DT/AG-2

अतिरिक्त 105 करोड़ रुपये राज्य अंशदान के रूप में दिये गये हैं। सभापति महोदय, प्रथम चरण में तत्तापानी से नैहर हरनौड होते हुए सलापड़ तक अंतर्देशीय जल यातायात सुविधा 2020-21 को भी जनता को समर्पित किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिलासपुर से भाखड़ा की तरफ भी यह वाटर ट्रांस्पोर्ट

श्रीमती एम.एस. द्वारा... जार

**12/03/2020/1645/MS/YK/1**
**श्री सुभाष ठाकुर जारी**------

की व्यवस्था की जाए और पर्यटन की दृष्टि से जो हमारे इष्टदेव नारसिंह बजिया जी हैं, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। ...(घण्टी) उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश के जो माननीय प्रधान मंत्री हैं, वे इस देश के लिए काम कर रहे हैं और दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। वे देश की समस्याओं को राजनीतिक दृष्टि से नहीं तोल रहे हैं। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी भी प्रदेश-हित में रात-दिन काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पूर्व सरकारों का एक रवैया होता था कि एक-दूसरे के प्रति द्वेष भावना के आधार पर आपराधिक मामले और एक-दूसरे के ऊपर छींटाकशी की जाती थी, उसको समाप्त किया गया है और एक अच्छा माहौल मुख्य मंत्री जी ने दिया है। इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अगर दोनों पक्षों को अच्छा वातावरण

मिला है तो यह आदरणीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी के सरल स्वभाव ..(घण्टी) और सबकी बात सुनने वाले उनके चरित्र के कारण हुआ है। इसी कारण आज हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है तथा हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है। भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूं।

सभापति जी, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। यह बजट सभी वर्गों के लिए एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी बजट है और यह बजट हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। सभापति जी, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

**12/03/2020/1645/MS/YK/2**

**सभापति(श्री राकेश पठानिया):** अब इस चर्चा में श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी भाग लेंगे।

**श्री इन्द्र दत्त लखनपाल:** सभापति जी, वर्ष 2020-21 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके संदर्भ में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, पिछले दो दिन से बजट पर चर्चा हो रही है और काफी संख्या में माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा में भाग लिया है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने बजट के बारे में विस्तार से सारी बातें रख दी हैं। यह बजट एक दिशा से भटका हुआ बजट है और यह माननीय मुख्य मंत्री जी का तीसरा बजट है। जब ये पहली बार मुख्य मंत्री बने और इन्होंने पहली बार बजट पेश किया तो हमने सोचा कि चलो ये नये हैं इसलिए कोई बात नहीं, अभी नया-नया बजट है। दूसरी बार हमने कहा कि चलो इस साल भी देख लेते हैं। इस बार तो इन्होंने जो पिछली बार स्कीमें दी थीं, उनका तो कोई पता नहीं है कि कहां चली गईं लेकिन 25-30 स्कीमें बजट में और डाल दी हैं। इस तरह से तो यह एक मेला बजट हो गया है, जैसे मेले में स्टॉल लगा देते हैं फिर उसमें घुमते रहो। आदमी को पता ही नहीं होता है कि क्या खरीदना है। वह हाल इस बजट का है। जिस स्टॉल में जाओ, ...(व्यवधान) आप लोग सुन लीजिए। मेले में जब कोई आदमी जाता है तो वह सोचता है कि मेले में शायद कोई नई चीज मिलेगी लेकिन वहां जाकर वही गुब्बारे मिलते हैं जिनकी हवा 10 मिनट में निकल जाती है। यह बजट भी वही है। सभापति जी, जो यह बजट है

इसमें कोई दिशा नहीं है। इसमें युवाओं और बागवानों के लिए कोई दिशा नहीं है और ये लोग यहां इसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। हम दो-तीन बातों का समर्थन कर रहे हैं लेकिन वह परिपाटी हमारे समय से ही चली हुई है। विधायक क्षेत्र विकास निधि बढ़ रही है जिसकी परिपाटी राजा साहब ने शुरू की थी और उसको 50 लाख रुपये से 1,10,000,00/- रुपये तक पहुंचा दिया था। उससे आगे इसको आपने किया, आपका धन्यवाद। इसी प्रकार से जो विधायकों की ऐच्छिक निधि थी, वह भी राजा साहब ने इस प्रदेश में पहली बार दी थी। उसमें आपने बढ़ोतरी की, आपका धन्यवाद। एक आपकी सहारा योजना है जिसके लिए

**12/03/2020/1645/MS/YK/3**

हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस योजना से लोगों को फायदा हो रहा है।

यहां जनमंच की बार-बार बात आती है और बहुत तारीफें करते हैं। सभापति जी, जो यह बजट है इसमें कुछ नहीं है और सारा-का-सारा सारांश जनमंच के ऊपर फोकस कर दिया है। सारे अधिकारियों को तो आपने जनमंच में लगा दिया तो वे बजट का काम कब करेंगे? बजट के बारे में सोचने के लिए तो उनको समय ही नहीं मिलेगा क्योंकि 15-20 दिन तो उनके आपके प्रि-जनमंच में चले जाते हैं। उसके बाद फिर लाव-लश्कर के साथ आपको जनमंच में जाना होता है। फिर उसके मिनिट्स बनाने होते हैं और फिर यह भी देखना होता है कि काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। काम कोई नहीं होते हैं। फिर आप बोलते हैं कि 1100 हैल्पलाइन हमने खोल दी है। आपने अपने जनमंच के आंकड़े जो स्वयं दिए हैं, उनको देखिए। जनमंच के माध्यम से 48000 के लगभग मुद्दे वहां पर उठाए गए और 43000 के आसपास उसमें फैसले हुए हैं। जो दो साल आपका जनमंच चला, तब तक तो लोगों में काफी उत्साह था और लोग आ और जा रहे थे कि शायद भला हो जाए,

**जारी जे0के0 द्वारा**-------

**12-03-2020/1650/जे.के.-ए.जी./1**

**श्री इन्द्र दत्त लखनपालः---जारी**------

जब तीसरा जनमंच तीसरे साल हुआ तो आपने देखा होगा, उसमें संख्या घटनी शुरू हो गई। उसमें 5 हजार लोग पूरे प्रदेश में कम हो गए। जो समस्या जनमंच पर उठाई जाती है, वही 1100 पर उठाई जाती है। इस तरह से हल कहां पर हो रहा है? आम जनता को फायदा कहां हो रहा है? जिन कामों का आप श्रेय लेना चाह रहे हैं कि काम हो गए, वे काम तो रूटीन के काम हैं। आप ऑफिस में जाएं जिसके लिए वे बने हुए हैं, भारी भरकम पैसा एस्टेब्लिशमैंट के ऊपर खर्च किया जाता है, फिर वह पैसा क्यों खर्च किया जाता है? अधिकारियों की प्रताड़ना करना और कांग्रेसियों को प्रताड़ित करना, यही जनमंच का काम रह गया है। "सबका साथ सबका विकास" वाली इसमें कोई बात नहीं है। "सबका साथ केवलमात्र भाजपा का विकास" यह मैं जरूर कह सकता हूं। जनमंच के जितने भी स्टेज होते हैं उनके ऊपर कोई भी प्रबुद्ध नागरिक नहीं बैठा होता है। केवल मंत्रिगण होंगे, डी.सी. होंगे और दो-चार ऑफिसर्ज़ होंगे बाकी सारी ठेकेदारों की ज़मात वहां पर होती है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए ठेकेदार हैं वे सब उसमें बैठे होते हैं। आपके चुने हुए प्रतिनिधि नीचे बैठे होते हैं। ब्लॉक के चेयरमैन, जिनको मान-सम्मान मिलना चाहिए वे जनता के बीच में बैठे होते हैं, उनका तो नम्बर ही नहीं आता है। यह जो जनमंच है इसको बन्द कर दो। जो बजट में आपने प्रावधान किए हैं कि हम इतने हजार करोड़ रुपये के काम लाएंगे, 15वें वित्तायोग से इतना पैसा मिल गया, उसको सही तरीके से लगाना है तो आप आफिसर्ज़ को फील्ड में भेजिए और उनसे काम करवाएं, जनमंच से कुछ नहीं होने वाला है। आपने यहां पर कहा कि हमने इतने रोजगार मेले लगा दिए इतना रोजगार युवाओं को दे दिया लेकिन वह तथ्यों से परे है। आपके आदेशानुसार वहां पर रोजगार का मेला लगाने तो आ जाते हैं लेकिन जब उन बच्चों की प्लेसमैंट होती है और बी.टैक और एम.बी.ए. के बच्चों को जब वहां पर 8-9 हजार रुपये की नौकरी मिलती है तो उन्हें लगता है कि यह हमारी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं है और वे छोड़ के चले आ रहे हैं।

12-03-2020/1650/जे.के.-ए.जी./2

**(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)**

आज देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चर्मरा गई है। इसका सबको पता है, बुरी हालत है। आप बोल रहे हैं कि हम 20 हजार लोगों को नौकरियां देंगे। पिछले साल भी आपने कहा था कि 20 हजार नौकरियां देंगे। कहां से देंगे, पहले यह तो बताओ? सरकारी नौकरियां आपके पास नहीं है, इंडस्ट्रीज़ आपके पास नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप लोग बड़े जोर-शोर से बोलते थे कि आप अपना पक्ष दिल्ली में जोर से नहीं रखते हैं और आप लोग पैकेज ले करके नहीं आते हैं। आज क्या हो गया जबकि आज डबल इंजन की सरकार है? आज आपको क्यों नहीं औद्योगिक पैकेज मिल रहा है? इसका मतलब यह है कि हम जो करते थे वह ठीक करते थे। आप औद्योगिक पैकेज क्यों नहीं ला पा रहे हैं? कई बार मुख्य मंत्री महोदय और उद्योग मंत्री जी दिल्ली जा कर आए हैं और यहां पर प्रधान मंत्री जी तीन-तीन बार आ गए, गृह मंत्री जी आ गए। आप लोग क्यों नहीं औद्योगिक पैकेज लाते हैं? बोलने के लिए तो प्रधान मंत्री जी बोलते हैं कि हिमाचल मेरा अपना घर है लेकिन सेवा विदेश में जा करके करते हैं। बड़े-बड़े मंच वे विदेश में सजाते हैं। हमारे लोगों का क्या होगा? हम लोग कहां जाएंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, उनके रोजगार के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? जो बच्चे 40-40 हजार रुपये का वेतन कम्पनियों से ले रहे थे, कम्पनियां उनके साथ ताल-मेल बिठा कर बोल रही है कि दो साल का आप एक्स्ट्रा पैसा ले लो और घर चले जाओ और यदि आपने फिर से नौकरी करनी है तो 8 हजार रुपये में दोबारा से हमारे पास आ जाओ। यह तो आपके कार्यकाल में हो रहा है, आपकी सरकार के नाक के तले हो रहा है। ध्यान बांटने के लिए आप तरह-तरह के मुद्दे लाते हैं। आप इन्वैस्टर्ज़ मीट करते हैं। करोड़ों रुपया वहां पर तम्बुओं पर खर्च हो जाता है। यह पता नहीं है कि उसमें डेलिगेट के लिए कमरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सो रहे हैं। ...(व्यवधान) हमारे लिए विनोद जी वहां जगह ही नहीं थी। कहां से आना, आपके लोगों ने सारे कमरे बुक कर दिए थे। जो बाहर से इन्वैस्टर्ज़ आए हुए थे वे भी बेचारे वापिस चले गए। विनोद जी आप लोगों को पता लग जाएगा। आप लोगों को ढाई साल तो हो गए। जो यह आपने बजट दिया है और इसमें इतनी भारी भरकम स्कीमें दी हैं, उसमें आप यह देखिए कि ढाई साल तो हो गए, मार्च में फिर

बजट आ जाएगा और 7-8 महीनों में जो आपका बजट का दस्तावेज है, उसको इम्पलिमैंट कैसे करेंगे? श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

**12.03.2020/1655/SS-AG/1**

**श्री इन्द्र दत्त लखनपाल क्रमागतः**

आज आप सड़कों के हाल देख लीजिए। मैं यहां शिमला से लेकर हमीरपुर तक की बात करता हूं, आप गाड़ी में बैठ नहीं सकते हैं। सड़कों की इतनी बुरी हालत है। सारी सड़कें गड्ढों में तबदील हो चुकी हैं। मंत्री महोदय, आप सिर हिला रहे हैं। आप मेरे साथ अभी सत्र खत्म होने के बाद चलिये, आपको दिखा देंगे कि वहां बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं। ब्रह्मपुखर से लेकर हमीरपुर तक वाया जुखाला होकर आप कभी जाईये तो पायेंगे कि सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि उसमें गाड़ी नहीं चला पायेंगे। यह सच्चाई है। वाया बिलासपुर भी यही हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक क्वालिटी कंट्रोल विंग खोल रखा है। हमारी समझ से परे है कि वे क्या क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। आपके जो टेक्निकल लोग एक्सियन, चीफ इंजीनियर और एस0ई0 इत्यादि हैं वे कैसे-कैसे एस्टीमेट्स बनाते हैं यह हमारी समझ से बाहर है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपये की लागत से मैहरे से लेकर घोड़ीदवीर तक सड़क का निर्माण हो रहा है। दो साल से उस सड़क का निर्माण हो रहा है। उस सड़क को देखकर हमें हंसी आती है। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं। वहां पर ठेकेदार ने सड़क को उखाड़ा। उस सड़क की अपग्रेडेशन हो रही है। उसके बाद ठेकेदार ने उसकी रीटारिंग की। रीटारिंग के 6 किलोमीटर के बाद जब उसने दूसरी जगह काम शुरू किया तो पीछे सारी टारिंग उखड़ गई। इस पर बहुत हल्ला हुआ। मामला अखबारों में भी आया, टी0वी0 न्यूज चैनल पर भी आया। आपके सारे क्वालिटी कंट्रोल के लोग पहुंच गए। सबने वहां पर ठेकेदार से काम बंद करवा दिया। उसके बावजूद जब ठेकेदार ने उसको दोबारा रिपेयर कर दिया और अगला काम शुरू कर दिया तो वह टारिंग फिर उखड़ गई। महोदय, यह क्या हो रहा है? जब हमने एस0ई0 से पूछा कि यह क्या है तो उन्होंने कहा कि हमारा जो इस सड़क का एस्टीमेट बना हुआ है उसमें जो आईटम्ज़ ली हुई हैं ...(व्यवधान) मेरी विचारधारा का नहीं है। मेरा तो वह ठेकेदार ही नहीं है। आपकी विचारधारा का है। वह बहुत नामी-गिरामी ठेकेदार है और आपकी पार्टी का बहुत तकड़ा फाइनेंसर है। इस बात को रहने दो। अगर मैं

बोलने लगा तो आपको बहुत मुश्किल हो जायेगी। यह सच्चाई है। आप वहां कभी आईये, आपका स्वागत है। आप केवल दाएं-बाएं से जनमंच पर आते हैं। वैसे आप पूरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें। ...(व्यवधान) मैंने ठेकेदार से भी बात की। मैंने एक्सियन से भी बात की। एक्सियन ने कहा कि इस

**12.03.2020/1655/SS-AG/2**

सड़क का जो एस्टीमेट बना हुआ है और उसके तहत क्वांटिटी और आईटम्ज़ इस तरीके से ली हुई हैं कि इसमें टारिंग टिकनी नहीं है। कमाल हो गया। 21वीं सदी में यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। ठेकेदार ने क्या करना? ठेकेदार की भी कितनी जान लेनी, उसने तीन बार टारिंग उसी पैटर्न पर कर दी। कहने का मतलब है कि जो DNITs बनती हैं, उसमें जो क्वांटिटी, क्वालिटी और आइटम्ज़ ली जाती हैं वे कम-से-कम 21वीं सदी की तो ले लो। आज 10-10, 12-12 टायरों की गाड़ियां चलती हैं, कहां वे 6 टायरों वाली गाड़ियों के लिए सड़कें बनी हुई हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। कम-से-कम उसमें गुणवत्ता की तो फिक्र होनी चाहिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है। 1100 नम्बर पर कम्प्लेंट करते हैं, वह कम्प्लेंट वापिस आती है और वहां से उसको क्लोज करके भेज दिया जाता है। ये तो आपके काम हो रहे हैं। आप केवल मात्र वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार की स्कीमें मत चलाएं।

आज माइनिंग के हाल देख लीजिए। सारी खड्डें खत्म हो गईं। पानी के सोर्सिज़ खत्म हो गए। सरकार को माइनिंग के माध्यम से जो इन्कम होनी थी उसके क्या हाल हैं? हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कितनी बार यहां पर मुद्दा उठाया लेकिन सरकार सोई हुई है। खुली छूट दी हुई है कि लूटो जितना लूट सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, इनको बोलने दो। कोई चिन्ता की बात नहीं है। आज यह हाल हो रहा है। सब आप लोगों के राज में हो रहा है। आप जाकर देखिये। हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं इनके एरिया में धड़ाधड़ माइनिंग हो रही है। सब कुछ हो रहा है। रोज़ अखबारों में आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि खनन माफिया पुलिस वालों के साथ मरने-मारने पर आ रहे हैं। अधिकारियों को मारने की धमकियां दे रहे हैं। ये तो आपके राज में हो रहा है।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूंगा। आज मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य का ये हाल है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जारी श्रीमती के0एस0

**12.03.2020/1700/केएस/एएस/1**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य आप बैठिए। क्योंकि अभी दो सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेना है इसलिए अगर सदन की अनुमति हो तो 45 मिनट तक समय बढ़ाया जाए। ठीक है, सदन का समय 45 मिनट बढ़ाया जाता है।

**श्री इन्द्र दत्त लखनपाल :** अध्यक्ष महोदय, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए,"हिम केयर योजना" "आयुष्मान भारत योजना" है और ठीक है कि इनसे लोगों को कुछ लाभ हो रहा है लेकिन ये स्कीमें आपके द्वारा ही नहीं चलाई गई हैं। ये पहले भी चलती थी। यह अलग बात है कि आपने नाम चेंज करके उसमें थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया तो वाहवाही लेनी शुरू कर दी लेकिन मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि जो गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल आता है, हमीरपुर से बड़सर या अन्य क्षेत्र से टांडा जाता है या शिमला आता है, जब वह डॉक्टर के पास आता है, हॉस्पिटल में बैड नहीं होता। जब वह इतनी दूर से आई.जी.एम.सी. या टांडा पहुंचता है तो डॉक्टर उसको एक लम्बी लिस्ट दे देते हैं कि पूरे टैस्ट करवाओ। अब शिमला जैसे शहर में जहां उसकी ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उसके तो रहने के साथ-साथ टैस्ट कराने में ही 15-20 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। जब उसके टैस्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तो बुकिंग है, आप तीन महीने बाद आएं, तीन महीने के बाद आपका ऑप्रेशन होगा। यह जो गैप है, क्या आपने इसके बारे में भी सोचा है? मैंने पहले भी कहा था कि "हिम केयर" या "आयुष्मान भारत" की जो स्कीमें चला रखी हैं, शुरू से अंत तक इनका लाभ मरीजों को मिलना चाहिए। इसमें टैस्ट भी आने चाहिए ताकि उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। सबसे बड़ी बात जो मरीज यहां पर आते हैं, उनकी ठहरने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । उनको एन.जी.ओज़. के माध्यम से थोड़ी-बहुत राहत

मिलती है लेकिन शिमला में बहुत ठंड होती है। ठंड में यहां कैसे मरीज रहते हैं, आप कभी हॉस्पिटल में जा कर देखिए। आप आम आदमी बन कर जाएं तब पता लगेगा कि अस्पतालों में क्या हाल हैं। लोगों को स्पैशल वार्ड नहीं मिलते। बड़ी-बड़ी एप्रोच लगानी पड़ती है।

**12.03.2020/1700/केएस/एएस/2**

अध्यक्ष महोदय, मेरे बड़सर के सिविल हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ था। आप उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, आपको भली-भांति मालूम है। वहां एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी उसको जो टीका लगाया गया था, टीके बंद करके लैब में भेज दिए गए थे कि इनकी जांच की जाएगी लेकिन आज 6-7 महीने हो गए, न उस जांच का पता लगा और न ही उन टीकों का पता लगा। आखिर किसके पास जाएं? जवाबदेही कौन फिक्स करेगा? कम से कम जो बात संज्ञान में आती है, उसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने त्वरित एक्शन लिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बी.एम.ओ. को बदल दिया लेकिन बी.एम.ओ. को बदलने से क्या समस्या का समाधान हो गया? उसके बाद भी वहां पर 14-15 कैजुअल्टीज़ और हो गई लेकिन कोई अपने सर पर इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर से वे ही इंजैक्शन दोबारा से वहां सप्लाई हो रहे हैं। क्या कारण है, उन इंजैक्शनों की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आ रही है, जो उस समय बंद किए गए थे? सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी अनमोल है, तो उस बच्ची के परिवार के लिए मैंने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दे दी जाए लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बात को आई-गई कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, बागवानों की, आवारा पशुओं की, बंदरों की बात ले लीजिए, इस बजट में उसका कोई प्रावधान ही नहीं है। जिस समय इस सरकार का प्रथम बजट पेश किया गया, उस समय बड़ी-बड़ी बातें की गई कि चारागाह बनाएंगे, बड़े-बड़े बाड़े बनाए जाएंगे, वहां आवारा पशुओं को रखा जाएगा। बंदरों से निजात दिलाई जाएगी लेकिन आज उसके बारे

में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा आवाज आप लोग ही उठाते थे । आज बजट में उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। क्या आवारा पशु और बंदर अब खत्म हो गए? आप बोलते हैं कि हमने 2022 में किसानों की इन्कम को डबल करना है, वह कहां से डबल होगी?

**12.03.2020/1700/केएस/एएस/3**

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

**श्री इन्द्र दत्त लखनपालः** अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करुंगा। आप बोल रहे हैं कि हम 10 हजार मकान बनाएंगे। आपके पास 10 हजार मकान बनाने के लिए बजट कहां है? आपने जो प्रावधान रखे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो मेरे वैल्फेयर ऑफिस में सूची है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**12.03.2020/1705/av-as/1**

**श्री इन्द्र दत्त लखनपाल--------- जारी**

उसके अनुसार अभी 110 मकान वेटिंग में हैं। अभी माह जून-जुलाई के मध्य जब बैठक होगी, क्योंकि मंत्री जी बैठक में आए थे और आप मीटिंग करते हैं। एक विधान सभा क्षेत्र को 8 मकान मिलते हैं। आप बताइए 110 मकान और कहां 8 मकान; ये वर्ष 2022 में कैसे डबल हो जायेंगे? ये सब तो मेरी समझ से परे है। इसलिए बजट में आपने जितने भी प्रावधान रखे हैं ये धरातल पर कभी पूरे होने वाले नहीं है; यह आपको भी पता है कि वर्ष 2022 में आप सारे-के-सारे मकान आवंटित नहीं कर पायेंगे। आपने यहां पर जुमलेबाजी में जो अढ़ाई घंटे व्यतीत करने थे; वह कर दिए। केंद्र सरकार और इस प्रदेश सरकार के ऊपर एक ही छाया है कि जुमले बोलते जाओ और जनता को लोलीपोप देते जाओ; धरातल पर कुछ होने वाला नहीं है। इस बजट में समर्थन करने लायक कुछ भी नहीं है। इस बजट के अंतर्गत

आप लोगों के द्वारा जो स्कीम्ज गिनाई जा रही है और जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हैं यह सब आप लोगो की मज़बूरी है। अगर आप लोग प्रशंसा नहीं करेंगे तो आप लोगों के काम नहीं होंगे। इसलिए यह आपकी मज़बूरी है और यह प्रशंसा आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन यदि इस बजट को नटशैल में देखा जाए तो इसमें युवाओं, बेरोज़गारों और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। कॉलेजिज और स्कूल्स में हमारे जो वोकेशनल टीचर्ज लगे हुए हैं उनके बारे में तो बजट बुक में कोई चर्चा नहीं की गई है। हमारे बच्चे जो वोकेशनल क्लासिज लगा रहे हैं उनको 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनको यह भी पता नहीं है कि हम किसके अधीन है। सरकार बोलती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं है और कंपनी वाले उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों पर गौर किया जाए। हम तो यह कहते हैं कि आपने यहां पर जो तीन बजट पेश किए हैं इनके बारे में जनमंच कार्यक्रमों को छोड़कर 5-6 महीने ठीक ढंग से अध्ययन कर लें। अगर आप इन तीनों बजटों को ढंग से पढ़ लें और देख लें कि ज़मीन पर उतरा क्या है तो उससे शायद आपका भी भला होगा तथा जनता का भी भला होगा। मैं यही कहना चाहता था और मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि यह जनता, मज़दूर, युवा तथा किसान विरोधी है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**12.03.2020/1705/av-as/2**

**अध्यक्ष :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी हिस्सा लेंगे।

**श्री जीत राम कटवाल (झण्डुता) :** अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 के बजट पर चर्चा हेतु जो कि दिनांक 6 मार्च, 2020 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया है; मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बजट की पृष्ठभूमि में बहुत सारी बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आईं। ऐसा लगता है कि कुछ बातें तो स्वभाववश होती हैं, कुछ विचारधारा से होती हैं और कुछ तथ्यों

पर आधारित भी होती हैं। मैं यहां पर तथ्यों पर आधारित बातें करूंगा और यदि देखा जाए तो तथ्यों से दोनों पक्षों को लाभ होता है। इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष के बजट के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। वर्ष 2020 का स्वर्ण जयन्ती का पहला समारोह दिनांक 25 जनवरी, 2020 को झण्डुता से शुरू हुआ। उसके लिए मैं इस सदन, मुख्य मंत्री और अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस पृष्ठभूमि की बात करना चाहता हूं तो वह यह है कि पूरा विश्व पिछले 4-5 वर्षों से रीसैशन से गुज़र रहा है। हिमाचल की इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ष 2017-18 में 6.8 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 7.1 प्रतिशत और वर्ष 2019-20 में 5.6 प्रतिशत आई है। भारतवर्ष की वर्ष 2017-18 में 7प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 6.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 5 प्रतिशत आई। पूरे विश्व की रीसैशन के कारण जो आर्थिक परिस्थितियां रही हैं जिसको विकास दर भी कहते हैं; वह 2.9 प्रतिशत है।

**टी सी द्वारा जारी**

**12.03.2020/1710/TCV/DC-1**

**श्री जीत राम कटवाल .. जारी**

वह 2.9 प्रतिशत है और जो विश्व के सबसे बड़े विकसित देश यू0एस0ए0, चीन, जापान गिने जाते हैं, उनकी विकास दर भी 4.5 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत के बीच में रही हैं। अपवाद नहीं है भारतवर्ष, अपवाद नहीं है हिमाचल प्रदेश। यदि इन सारे आंकड़ों को देखा जाये तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी और भारतवर्ष की आर्थिकी फ़ास्ट ग्रोइंग इकोनोमी के रूप में उभर कर सामने आई है। वर्ष 2014 में भारत सरकार का डेफिसिट 5.2 प्रतिशत था, वह मार्च, 2019 में 4.8 प्रतिशत हुआ है। इस वर्ष का बजट अनुमान 49,131 करोड़ रुपये का है, 7272 करोड़ रुपये का इसमें डेफिसिट है। यहां पर माननीय सदस्य, श्री सिंघा जी ने कहा कि 7900 करोड़ रुपये के प्लॉन रिपोर्ट सर्वे से पहले ही आ गई और वॉयलेशन हो गया। यह सही है, एक प्लॉन को प्लानिंग बोर्ड अप्रूव करता है और वह सर्वे, चर्चा और

अख़बारों में भी आएगी, इससे शायद कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 1990 करोड़ रुपये की एस0सी0एस0टी0 कंपोनेंट प्लॉन, 711 करोड़ रुपये की ट्राइब्ल सब-प्लॉन है और 88 करोड़ रुपये की बैकवर्ड एरिया सब-प्लॉन है। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का कुछ एरिया भी बैकवर्ड एरिया को री-प्रेजैंट करता है। हिमाचल प्रदेश की इकोनोमी फॉस्ट ग्रोइंग है, इसका एक कारण यह भी है कि भारतवर्ष की जो एवरेज़ एज है, वह 26-27 वर्ष है जबकि अमेरिका की 46 है और दूसरी यूरोपीयन देशों की 52 के करीब हैं। हम किसी भी रिसैशन, झटके या किसी भी तरह की समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं। इसलिए न विपक्ष को घबराने की ज़रूरत है और न हमें घबराने की ज़रूरत हैं। हमारी आर्थिकी और व्यवस्था अच्छी तरह से चलने के लिए तत्पर है। अगर हम पिछले 15 सालों का इतिहास देंखे, जब 2006-07 की आर्थिक मंदी शुरू हुई थी, उसके बाद भी हम लोग विश्व स्तर पर अच्छे तरीके से टिके हैं। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी जो वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनोमी बनाने की बात करते हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं। यहां पर एग्रीकल्चर के लिए कहा गया कि इसके लिए बजट में कुछ भी

**12.03.2020/1710/TCV/DC-2**

नहीं है। आजादी के बाद एग्रीकल्चर का शेयर जी0डी0पी0 में लगातार कम हुआ है। एग्रीकल्चर इकोनोमी एक पिछड़ी आर्थिकी के रूप में जानी जाती है। अब एग्रीकल्चर-हॉर्टिकल्चर के लिए जो 16 प्वाइंट का एक्शन प्लॉन है, हमें पूरा विश्वास हैं, आप पढ़कर देंखे, हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा लोन्स की बात हुई, अभी तक कुल 53000 करोड़ रुपये का लोन है। इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में 2000 रुपये के लगभग कम लोन लिया है। केन्द्र सरकार से 75:25 की रेशो से हमें ग्रांट मिलती थी, वह अब 90:10 हो गई है, उससे भी हमें फ़ायदा हुआ है। 15वें वित्तायोग के तहत हमें इस वर्ष के लिए 11,431 करोड़

रुपये की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली है। अगर हम इसे देखें हैं तो पूरे भारत में केरल ही एक ऐसा राज्य है जो

श्री आर0के0एस द्वारा ... जारी

12.03.2020/1715/RKS/YK-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

हमारे प्रदेश से आगे है। इसमें पंजाब हमसे पीछे है और उसे 7659 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली है। जो अर्बन लोकल बॉडीज़, पी0आर0आईज और डिजास्टर मिटीगेशन के लिए 7980 करोड़ रूपये मिला है, इससे मालूम पड़ता है कि हम एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहें हैं। भारत सरकार की एक अच्छी सोच हिमाचल प्रदेश के प्रति है क्योंकि केन्द्र सरकार के बजट में भी हिमाचल प्रदेश को काफी कुछ मिला है। बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोलते हैं परंतु कई दफा तथ्य इसके विपरीत होते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह तथ्यों पर आधारित है। जल जीवन मिशन में भी हमें अच्छी राशि मिली है और इसमें कुल 327 स्कीमों के लिए 2896 करोड़ रुपये की AA&ES मिली है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय जल शक्ति मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि हम जल जीवन मिशन में अच्छा परफॉर्म कर रहें हैं इसलिए परफोर्मर स्टेट के रूप में केंद्र सरकार हमें पैसा देने के लिए अग्रसर है। वे कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अच्छा काम कर रहा है। अगर हमारे प्रदेश में साधनों का इजाफा हो रहा है तो उसके लिए हमें केन्द्र सरकार का धन्यवादी होना चाहिए। 'किसान सम्मान योजना' में केंद्र सरकार ने 597 करोड़ रुपये दिए हैं जिससे 8,46,784 किसानों को लाभ मिला है। मैं बहुत लम्बे समय तक सरकारी सेवा में रहा हूं। 10,000 की सब्सिडी के लिए 40 चक्कर लगाना पड़ते थे। यह पहली बार हुआ है कि किसानों के खाते में जो 2000, 4000, 6000 रुपये डाले गए हैं वे उनके खाते में उसी समयबद्ध तरीके से उन्हें मिले। पूरे भारतवर्ष में जो 75,000 करोड़

रुपये का आंकड़ा था उस प्रकिया को लागू किया गया है और यह कोई छोटी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश को 597 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। गृहिणी सुविधा योजना में 2,76,000 गैस कनैक्शन्ज दिए गए। मेरे चुनाव क्षेत्र में 7354 कनैक्शन दिए गए। यह भी किसानों की आय दोगुनी करने की तरफ एक कदम है इससे उनका घर, उनकी व्यवस्था खुशहाल होगी। हम उनके लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। काम करने के लिए एक आदर्श माहौल की व्यवस्था हो रही है और यह सारी चीजें बिना पक्षपात

12.03.2020/1715/RKS/yk-2

के हो रही हैं। जनमंच पर बहुत सारी चर्चा हुई। ग्लोबल इंवैस्टर मीट पर चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई कमी नजर आ रही हो। सहारा योजना के अंतर्गत जो लोग किडनी या कैंसर की बीमारी से ग्रस्ति होते हैं उन्हें अब 2000 रुपये की जगह 3000 रुपये दिया जाएगा। मुख्य मंत्री चिकित्सा कोष में बिल वैरिफाइ करवा के लाओ और पैसे ले जाओ। कोइ पक्षपात की बात नहीं है। यह राज्य सरकार का माइक्रो लैवल और मैक्रो लैवल फाइनैंशियल बजट है। अगर हम इस तरीके से इसे देखें तो छोटी-सी-छोटी स्कीमें और बड़ी-से-बड़ी स्कीमों की ओर कदम अग्रसर हैं। 'आयुष्मान भारत योजना' में 3,12,000 कार्ड बने हैं। हिम केयर योजना में 3,93,000 कार्ड बने हैं जिसमें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। मुझ से पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि यह हमारी स्कीमें थी। स्कीमें भी बनती रहती हैं और सन् 1971 से जब से हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा मिला है तब से बजट भी बन रहा है । लेकिन इन स्कीमों को स्वरूप देना और इनका अपग्रेडेशन करना अनिवार्य है। पहले सड़कें छोटी होती थी अब हाइवेज़ बन रहे हैं। यह किस मुख्य मंत्री और किस सरकार के पक्ष में जाता है यह देखने वाली बात है । अगर हम अपग्रेडशन और रिविजन को और पोजिटिव तरीके से लें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट तथा दूसरे जनहित के कार्य ज्यादा होते हैं। अभी 5,34,000 के लगभग लोगों को पैंशन दी जा रही है और अब इसमें 50 हजार आवेदन और एड किए जा रहे हैं। विधवाओं और अपंग व्यक्तियों की पैंशन को 850 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये करने

का प्रावधान किया जा रहा है। इससे 1 लाख 25 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह सब चीजें गरीब और बेसहारा लोगों के लिए हैं।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

12.03.2020/1720/बी.एस./वाई.के./-1

**श्री जीत राम कटवाल जारी...**

इन चीजों को अगर देखें तो हम स्वतः ही समझ जाएंगे कि सरकार काम करती है और सरकार किस तरीके से काम करती है इस बात का पता चलता है। हैल्थ में बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं और सब लोगों ने इस पर बहुत चर्चा भी की है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अंतोदय अन्न योजना, ये सभी योजनाएं पहले से चली हैं इनके ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा।

यदि में अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो यह एक पिछड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र है। इसमें 14 पंचायतें पिछड़ी हुई हैं। भाखड़ा डैम ऑस्टीज हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में 8 पुल बन रहे हैं और मैं दावे से कहता हूं अगले दो सालों में ये पुल बन करके तैयार हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सबसे लम्बे पुल इनमें बन कर तैयार होंगे जिनकी लंबाई 330 मीटर, 317 मीटर बाघछाल का पुल जो 15 वर्षों से रुका पड़ा था इसमें शामिल है। यहां मेरे बड़े भाई राम लाल ठाकुर जी ने कहा कि बजट नहीं है, 22 करोड़ रुपया सरकार ने एक मुश्त जारी किया हुआ है। मैं परसों ही उस क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। 193 किलोमीटर 56 मीटर और 112 मीटर, 26 मीटर इस तरह के 8 पुल बनने वाले हैं। इनमें से तीन का उद्घाटन अभी मई, जून 2020 को होने वाला है। 38 करोड़ रुपए का एम.डी.आर. रोड मेरे चुनाव क्षेत्र में टैंडर हो करके काम शुरू हो चुका है। बड़ी मैगा प्रोजैक्ट्स भी हैं और माइक्रो प्रोजैक्ट्स भी हैं। इस चुनाव क्षेत्र में यदि मैं कहूं कोडधार क्षेत्र के 6.50 हजार डैम ऑस्टीज जिनमें 254 गांवो में से 193 गांव मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित थे। वे बिजली-पानी से वंचित थे आज बी.बी. एम. से 80 लाख लीटर पानी लेने की परमीशन के साथ 52 करोड़ रुपए की बृहद पानी की योजना इस चुनाव क्षेत्र के

लिए लग रही है। बजट में ई.पी.सी. की बात की है। Engineering Procurement and Construction (EPC)दो सालों के भीतर पुल भी बनेंगे और दो सालों के भीतर 52 करोड़ की योजना भी लागू होगी। 33 के.वी. का सब स्टेशन भी उसमें शामिल है। उसमें 2 करोड़ रुपए की पुरानी पाइपों की रिप्लेसमैंट भी शामिल है। 12 करोड़ रुपए के स्ट्रक्चर शामिल हैं। यह सब माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय महेन्द्र सिंह जी के प्रयासों से हुआ है। मैं इनका आभार व्यक्त

12.03.2020/1720/बी.एस./वाई.के./-2

करना चाहता हूं। जो पिछड़े क्षेत्रों की बात होती है उसमें मैं अपने दावे के साथ कहता हूं कि यह सारी चीजें हुई हैं। इसके अलावा छोटी-छोटी बातें हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय महेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा चुनाव क्षेत्र निर्वाध पानी की सप्लाई के लिए शिमला शहरी, सिराज, तीसा और झण्डुता ये चार स्थान इन्ट्रपटिड वाटर सप्लाई के लिए जाने जाते थे। उसमें भी मेरा क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अलावा खेल स्टेडियम बन रहा है, नेचर पार्क बन रहा है, स्किल डवलपमैंट सैंटर बन रहा है, अटल आदर्श विद्यालय, सबसे पहला झण्डुता चुनाव क्षेत्र में अनाउंस हुआ था उसकी बिल्डिंग की रिपेयर हो करके तैयार कर दी गई है, शीघ्र ही वह चालू होगा। इसके अतिरिक्त एक नई बिल्डिंग का कार्य भी प्रगति पर है। सबसे पहला अटल आदर्श विद्यालय झण्डुता चुनाव क्षेत्र में शुरू होगा। माननीय शिक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का इस योजना को झण्डुता से शुरू करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। गेड़हवीं में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए माननीय उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसमें फोरेस्ट का केस कलियर हो चुका है और कुछ ही दिनों में इसका शिलान्यास होगा। डेढ़ साल के अन्दर-अन्दर वहां इन्डस्ट्री आएगी। मैंने यहां पर दो पुलों की बात की है ये दोनों गेम चेंजर पुल हैं। हमीरपुर के लिए 45 किलोमीटर किर्तपुर शॉट होगा, झण्डुता के लिए 60 किलोमीटर शॉट होगा। (घंटी) साहब, कृपया रुकिए, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी मेरी बारी छीनी गई है। मुझे कृपया पांच मिनट का समय दे दें। घुमारवीं के लिए 50 किलोमीटर शॉट होगा। ये एतिहासिक प्रोजैक्ट्स हैं झण्डुता क्षेत्र में इस सरकार द्वारा लागू की गई है। सब-जज का कोर्ट खुला, एक्सियन, आई.पी.एच. का कार्यालय खुला, एक्सियन, पी.डब्ल्यू.

डी. का कार्यालय खुला और अग्नि शमन केन्द्र खुला। जो एक नए तरीके से इसे अपग्रेडेशन की बात होती है तो मेरे चुनाव क्षेत्र में ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की हैं। इसके लिए आप लोगों का और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का, भारतीय जनता पार्टी की सैटअप सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

12.03.2020/1725/DT/AG-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

आदरणीय मोदी जी के बारे में कुछेक बातें हुई। मैं यहां पर 35-ए और धारा 370 के बारे में भी बोलना चाहूंगा। मैं जम्मू-कश्मीर में डांडी बल, हजरत बल में ऑबजर्बर रहा हूं। मुझे वहां की परिस्थितियों के बारे में सब पता है। जब मैं वहां पर ऑबजर्बर था मेरे साथ एक एक्सियन की डयूटी लाइजनिंग अधिकारी के रूप में लगाई गई थी। उसने मुझे कहा था कि भाई साहब हमें यहां पर शक की नजर से देखते हैं और मेरे सामने मेरे भाई को भी गोली लगी थी। मैंने उनसे पूछा कि यहां पर दिक्कत क्या है? तो उसने कहा कि यह कांग्रेस कांफ्रेस द्वारा क्रिएटिड प्रॉब्लम है। हजारों आदमी वहां पर मरे, चम्बा के सतरुडी में 32-35 आदमी मरे। इसी सदन में पिछली बार कहा गया कि वहां लोगों को अधिकार नहीं हैं। चम्बा के उन मासूम लोगों ने क्या गलत किया था जो उन्हें मार दिया गया। आज परिस्थिति यह है कि लोगों को हौंसला मिल रहा है और जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी मिल रहा है। मैं टॉरंटोशन एक इन्टरनैश्नल पेपर है। उसे पढ़ कर उदृत करना चाहूंगा। यह देखने वाली बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसके बारे में क्या कहता है। "A major shift took place in the Indian subcontinent in August, 2019 when the Government of India revoked the special status it had conferred on its only Muslim-majority state - the State of Jammu and Kashmir (J&K).

In doing so, India demonstrated a spinal cord of steel, this coming after 1,000 years of Arab, Turkic, Persian and Afghan Islamic invasions, followed by Portuguese, French and British colonization, had reduced it to mere spaghetti.

India today stands as tall as the Himalayas and walks as gracefully as the Bengal tiger, after this bold Internal Policy Decision.

12.03.2020/1725/DT/AG-2

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य कृपया वाईंडअप करें।

**श्री जीत राम कटवाल :** यह इण्टलनैशनल मीडिया का एडिटोरियल अखबार में आया था कोई भी इसे देख सकता है। यह सारी बातें मैंने कही। आपने 15 मिनट का समय मुझे दिया और भी बातें थी इसमें और भी बहुत सारी बातें थीं जैसे किसानों की आय की, इसमें 25 स्कीमें लागू की हैं। इसमें छोटी -सी-छोटी और बड़ी -से-बड़ी स्कीमें हैं। इसके लिए यह सरकार और माननीय मुख्य मंत्री और केन्द्र सरकार एवं माननीय प्रधान मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। इस देश को नई दिशा आज के समय मिली है। आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा स्टेटस है उसे सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान कभी हमें आंखे दिखाता था आज उसे भी थोड़ी सद्बुद्धि प्रदान हुई है। ज्यादा न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ माननीय महोदय, आपने मुझे वक्त दिया आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। मैं इस स्वर्ण जयंती वर्ष के बजट का, जिसका समारोह मेरे चुनाव क्षेत्र से शुरू हुआ, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। दूसरा समारोह भी मेरे चुनाव क्षेत्र में होगा उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्रीमती एम.एस. द्वारा ... जारी

**12/03/2020/1730/MS/ag/1**

**अध्यक्षः** अब चर्चा में माननीय सदस्य इन्द्र सिंह जी भाग लेंगे।

**श्री इन्द्र सिंह(बल्ह)**: अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी द्वारा वर्ष 2020-21 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और किसी वर्ग को अछूता नहीं रखा गया है। इसमें चाहे कर्मचारियों, व्यापारियों, महिला वर्ग, पुरूष वर्ग, दलित वर्ग, अनाथ या किसान/बागवानों की बात हो, सबका ध्यान रखा गया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं क्योंकि इस बजट में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के व्यक्ति को किसी-न-किसी स्कीम में शामिल किया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि इन्होंने हमारे क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी देने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि को मु01,25,000,00/-रुपये से बढ़ाकर 1,75,000,00/-रुपये किया है। इसके साथ ही जो विधायक प्राथमिकता की योजनाएं धरातल में उतारी जाती हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग की बात हो या जल शक्ति विभाग या अन्य विभागों की बात हो, उस राशि को 105 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये किया है। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। जो हमारी ऐच्छिक निधि होती है जो अनुदान राशि मानी जाती है, उसको 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष जी, जहां तक "उज्ज्वला योजना" की बात है, इस योजना को माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चलाया था और इस योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ मिला है। मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में उज्ज्वला योजना से छूटे हुए परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना में शामिल किया और हमारे हिमाचल में इस योजना से 2,76000 परिवारों को इसका लाभ मिला है। मैं धन्यवादी हूं कि मेरे क्षेत्र में भी 6000 के लगभग लोगों को इसका लाभ मिला है। आने वाले समय में और भी लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, यह भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष जी, जो परिवार निजी कारणों से अपनी ज़मीन छोड़कर बाहर चले

**12/03/2020/1730/MS/ag/2**

जाते हैं यानी बच्चों की पढ़ाई के कारण किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं तो उनकी ज़मीन खाली पड़ी रहती है। इसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सदन के सभी दलों के सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे जो खाली पड़ी भूमि को किसी अन्य, सिर्फ हिमाचली कृषक को खेती-बाड़ी हेतु देने की व्यवस्था बारे अध्ययन करके अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी।

इसके साथ खरीफ और रबी की बिजाई से पहले पूरे राज्य के सभी ब्लॉक्स में कृषक मेले आयोजित किए जाने का भी प्रावधान बजट में किया है। इन मेलों में कृषि, उद्यान, पशु पालन, मत्स्य पालन, कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय, बैंक के अधिकारी/वैज्ञानिक/कर्मचारी भाग लेंगे, जिससे कृषकों को तकनीकी तथा ऋण संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी। इसके लिए मैं कृषि मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

इसी तरह से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए इस वर्ष 338 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा इससे 111 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भारत सरकार से अब तक 202 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा कुछ क्षेत्र ऐसा था जो सिंचाई सुविधा से वंचित रहता था। वहां के लिए अनेकों स्कीमें धरातल में उतारी गई हैं। लेकिन जो कमाण्ड एरिया है उसको डवलप करने के लिए जो स्कीमें या लाइनें बिछाई जाती थीं, चाहे वे पाइप लाइनें थीं या कूहले थीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्षमता कम थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने उसके लिए 1024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

इसी तरह से मुख्य मंत्री आश्रय योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस योजना को चालू रखे ताकि शेष बचे व्यक्ति जो नये घर बना रहे हैं उनको इसका लाभ मिले।

"मुख्य मंत्री मधु विकास योजना" के तहत 7 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा है। मैं इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। "महक" योजना के अंतर्गत कृषक तथा बागवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा व सुगन्धित पौधारापेण, विकास एवं विपणन हेतु प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

इसके अलावा पशुधन की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु पशु पालकों के द्वार पर समाधान करने हेतु जो मोबाइल वैटरिनरी सेवा शुरू करने की बात कही है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि यह किसानों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। क्योंकि

**12/03/2020/1730/MS/ag/3**

आम जनता को पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए दूर-दराज़ के क्षेत्रों में जाना पड़ता था लेकिन अब डॉक्टर घर में ही पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे।
जहां तक लोकमित्र केन्द्रों की बात है तो 200 केन्द्रों को खोलने का बजट में प्रावधान किया गया है और 100 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। मैं केन्द्र सरकार का धन्यवादी हूं कि हमारे युवाओं के लिए लोकमित्र केन्द्रों का प्रावधान किया है।
जारी जे0के0 द्वारा----

**12.03.2020/1735/जेएस/एएस/1**

**श्री इन्द्र सिंह जारी**----

इससे गांव के युवाओं के लिए सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पंचायतों में इसका निर्माण किया जाएगा जिससे हमारे युवा साथियों को रोज़गार भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, "नई राहें-नई मंजिलें" के तहत मेरे रिवाल्सर क्षेत्र को जिसे एक त्रिवेणी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां हिन्दू भी हैं, बौद्ध भी हैं और सिक्ख भी हैं, तीनों को मिलाकर त्रिवेणी संगम का नाम दिया जाता है। उसको विकसित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, मैं इस योजना के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे बल्ह चुनाव क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रियों द्वारा विकास के बहुत से कार्य हुए हैं। सबसे बड़ी देन वहां पर मैडिकल कॉलेज है। वर्षों पुराना

मैडिकल कॉलेज, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाया गया था, बीच में कांग्रेस सरकार द्वारा वहां पर कई तरह के हथकंडे अपनाए गए, ये फट्टे लगा कर चले गए और उस मैडिकल कॉलेज को खंडहर बना दिया। अध्यक्ष महोदय, आपकी रहनुमाई से और माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से आज वह मैडिकल कॉलेज चला और हजारों लोगों को आज वहां पर मैडिकल सुविधा प्रदान हो रही है। वहां पर कैंसर हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सैंटर है। वहां के लिए जो इतनी बड़ी सुविधा प्रदान की गई है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का और आपका धन्यवादी हूं, अभिनंदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों की बात करना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि सड़कों व भवनों के निर्माण के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकृत की है। सड़कों के रख-रखाव के लिए 1.50 करोड़ रुपये की राशि

**12.03.2020/1735/जेएस/एएस/2**

स्वीकृत की गई है। जल शक्ति विभाग की तरफ से जल मिशन के लिए मेरे चुनाव क्षेत्र में 7 स्कीमें स्वीकृत की हैं और 15 करोड़ रुपये का इज़ाफा मेरे क्षेत्र को हुआ है, इसके लिए मैं मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोक निर्माण विभाग की बात है, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक डिविज़न दिया गया है, मैं इसके लिए विशेषकर माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ पक्षपात हुआ करता था लेकिन इन्होंने आज डिविज़न खोल कर हमारे क्षेत्र के लिए न्याय दिलाया है।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई सुविधा हेतु मेरे चुनाव क्षेत्र में, चाहे कमांद एरिया की बात हो या नई स्कीमें लाने की बात हो, 95 करोड़ रुपये की राशि बल्ह चुनाव क्षेत्र के लिए प्रदान की गई है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी का धन्यवादी हूं।

इसी तरह से मिनी सचिवालय जो नेरचौक में बनना है, वह 17 करोड़ रुपये के लगभग की राशि से बनेगा, यह भी बहुत बड़ी अचीवमैंट है। सुकेती खड्ड के चैनेलाइजेशन के लिए मैं जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवादी हूं, आपने 400 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. जो कि एक उपजाऊ भूमि के बचाव के लिए, उसके कटाव को रोकने के लिए बनाई है और यह डी.पी.आर. सी.पी.डब्ल्यू.डी. को भेजी गई है। मैं चाहूंगा कि इस कार्य में तेजी लाई जाए और लोगों की जमीन के भूमि कटाव को बचाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री लोक भवन जो लगभग 30 लाख रुपये की राशि से बन रहा है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं। इसी तरह नेरचौक में 20 करोड़ रुपये की लागत से एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी उसका शिलान्यास किया है।

अध्यक्ष महोदय, जो एयरपोर्ट की बात है, गग्गल -शिमला एयरपोर्ट और बल्ह के एयरपोर्ट के लिए 1013 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, मैं बल्ह

**12.03.2020/1735/जेएस/एएस/3**

और नाचन की जनता की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद प्रकट करता हूं क्योंकि जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, उससे हमारे लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट जो चक्र में बनेगा, पशुपालन मंत्री अभी बैठे नहीं हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। 16.32 करोड़ रुपये की राशि के प्रोसैसिंग प्लांट का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। उसके लिए 20 हजार लीटर केपेसिटी को बढ़ाकर 50 हजार लीटर किया है। दूध का खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने के लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

इसी तरह मेरे बल्ह चुनाव क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अग्निशमन केन्द्र खोला है, मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवादी हूं क्योंकि

रिवाल्सर में लोगों को बहुत बड़ी असुविधा होती थी लेकिन अब बस स्टैंड के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया अब वाइंड अप करें।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--

**12.03.2020/1740/SS-AS/1**

**श्री इन्द्र सिंह के बाद..**

**श्री इन्द्र सिंह** : इसी तरह से लस्सी के पाधरू में एस0सी0सी0पी0 के तहत एक बहुत बड़ा ब्रिज 6.80 करोड़ रुपये की राशि से बनने जा रहा है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं। इसी तरह से गलमा पुल है जोकि 5 करोड़ रुपये की राशि से बनने जा रहा है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जो गम्भर पुल है वह भी वर्षों पुराना पुल था। वहां 70 साल पहले कांग्रेस का राज था लेकिन साथियों जैसे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के लोग रहते थे वैसे ही जब वहां बारिश होती थी और खड्ड आती थी तो उधर के लोग उधर रह जाते थे और इधर के लोग इधर ही रह जाते थे। इस तरह की वहां व्यवस्था थी। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक करोड़ रुपये की लागत से वह पुल बनाया है। मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से 98.66 करोड़ रुपये की राशि से कोठीगैहरी पुल बनने जा रहा है। इसी तरह से 5.20 करोड़ रुपये की राशि से सी0एच0सी0 रिवॉल्सर बनने जा रही है। उसका निर्माण हो रहा है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से पी0एच0सी0 लेदा है वह 1.65 करोड़ रुपये की राशि से स्वीकृत हुई है। इसी तरह से अनेकों कार्य धरातल पर उतरने वाले हैं। हिमाचल गृहिणी योजना, हिमकेयर योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना, मुख्य मंत्री सेवा संकल्प योजना जिसमें 1100 नम्बर डायल किया जाता है उससे हमारे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है।

इसी तरह से जनमंच एक ऐतिहासिक निर्णय है। 181 जनमंच प्रदेश में हुए हैं। लगभग 45708 शिकायतें आईं, जिनमें से 41698 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। गुडिया हैल्पलाइन नम्बर जो 1515 है उससे बहुत-सी सुविधा प्रदान हुई है।

सहारा योजना, जिसमें राशि 2000 से बढ़ाकर 3000 की है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेधा प्रोत्साहन योजना, मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना, नई राहें नई मंजिलें, अन्त्योदय अन्न योजना, मुख्य मंत्री कन्यादान योजना, एक बूटा बेटी के नाम, इस तरह की बहुत-सी

**12.03.2020/1740/SS-AS/2**

योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। अनेकों व्यक्ति योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। आज मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का इस सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं और जो इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। जयहिन्द, जय भारत, जयश्री राम।

**अध्यक्ष :** इंद्र सिंह जी, आपने निर्धारित समय में अपनी बात रखी है आपका धन्यवाद।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

**शिमला-171 004** **यशपाल शर्मा,**
**दिनांकः 12 मार्च, 2020** **सचिव।**